M.P./BHOPAL/642/2021-23

• सिंधिया को तोहफे का इंतजार • 31 गौण खनिज की ई-नीलामी

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

कमलनाथ के सामने खुला मैदान

वर्ष 19, अंक-7 | 1 से 15 जनवरी 2021 | पृष्ठ-48 | मूल्य 25 रूपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718

टूटेगा चुनौतियों का चक्रव्यूह?

बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ...

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजतंत्र

9 | विधानसभा सत्र से परहेज क्यों?

विधानसभा का सत्र एक बार फिर टाल दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को इसकी वजह बताया जा रहा है। यद्यपि संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखकर सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं।

राजपथ

10–11 | नाथ के सामने खुला मैदान

कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लोगों के सामने एक शिगूफा छोड़ा था- संन्यास लेने जैसा। शर्त भी रख दी, अगर छिंदवाड़ा के लोग चाहें। वे लोग जिन्होंने 9 बार वोट देकर उनको लोकसभा पहुंचाया और उनके बाद उनके बेटे नकुलनाथ...

लालफीताशाही

13 | जाल में अफसर

करे कोई और भरे कोई की तर्ज पर मप्र के 4 अफसर जांच के घेरे में पड़ गए हैं। मप्र सरकार ने 4 अफसरों के खिलाफ जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। सरकार की चिट्ठी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कैश कांड में मप्र के 4 बड़े...

भर्राशाही

13 | एक्सटेंशन पर डायल-100

मप्र में चलाई जा रही डायल-100 योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस योजना को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। यह फैसला गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की वर्चुअल बैठक में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद् ने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

वर्ष 2020 हताशा-निराशा, टूटन, विरोध प्रदर्शनों का ऐसा गवाह रहा है, जो शायद ही कभी और इस दौर में भी शायद ही कहीं देखने को मिला। कोविड-19 महामारी के बड़े सबक में यह भी रहा है कि दुनिया में जिसने इसकी कम परवाह की, उसे उतना ही झेलना पड़ा। भारत में कोरोना ने सिर्फ मौतें ही नहीं दी हैं, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के साथ सामाजिक व मानसिक विकारों में भी वृद्धि की है। यानी पूरा वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा। अब आशा की जा रही है कि वर्ष 2021 में इन चुनौतियों का चक्रव्यूह टूटेगा।

राजनीति

30–31 | कांग्रेस के लिए निर्णायक घड़ी

राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने से पहले कांग्रेस को एक सवाल का जवाब जरूर खोजना चाहिए। वह यह कि राहुल कांग्रेस की समस्याओं का समाधान हैं या खुद समस्या हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग इसी सवाल से भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जवाब पता है।

राजस्थान

36 | 50 फीसदी से ज्यादा वादे पूरे

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बात करें अशोक गहलोत के पिछले 2 कार्यकालों की तो इस बार के तीसरे कार्यकाल में शुरुआती 2 सालों में गहलोत सरकार को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

बिहार

38 | अपराधी बेखौफ

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले तीन कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की खातिर काफी ख्याति अर्जित की थी, लेकिन अपने नए कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्हें कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

उम्मीद का टीका

पी रजादा कासिम का एक शेर है...

अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने
हाथ भी मल रहे हैं आप, आप बहुत अजीब हैं

कोरोना वायरस से फैला संक्रमण हम मानव की करतूतों का परिणाम है। लगभग पिछला एक साल कोरोना वायरस की चपेट में रहा। अब जाकर उम्मीद के टीके की संभावना नजर आ रही है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों में तैयार टीकों का कई देशों में परीक्षण पूरा हो चुका है और इनके इस्तेमाल की दिशा में बढ़ा जा रहा है। भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में रहा जिन्होंने टीका विकसित करने के काम को एक चुनौती के रूप में लिया और सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक सहित कुछ कंपनियों ने टीके तैयार किए। पिछले दिनों इन कंपनियों सहित अमेरिकी कंपनी-फाइजर ने भी डीजीसीआई के समक्ष के अपने टीकों के आपात इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। भारत की आबादी को देखते हुए टीकाकरण एक तरह का महाभियान है। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोगों को इसकी खुराक दी जानी है। सबसे पहले किसे दिया जाए, इसे लेकर भी प्राथमिकता तय हो चुकी है। कोरोना महामारी से निपटने में स्वास्थ्यकर्मियों व बुजुर्गों को सबसे पहले इसे दिया जाना है। सीरम ने इस महीने 10 करोड़ खुराक का उत्पादन कर लेने की तैयारी कर ली है। टीकाकरण को लेकर अब तक जिस तरह की तैयारियां हुई हैं और पिछले हफ्ते जिस तरह से इसके प्रयोग को लेकर पूर्वाभ्यास हुए, उससे तो लग रहा है भारत इस काम को बखूबी पूरा कर ले जाएगा। यह तो तय था कि जल्द ही टीका उपलब्ध होगा, लेकिन बड़ी चुनौती यह थी कि इसे देशभर में सुरक्षित रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचाया कैसे जाएगा। टीके की आपूर्ति और भंडारण सहित सारी तैयारियां समय से पूरी कर ली गईं और इसे देश के हर राज्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना को भी सतर्क रखा गया है। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री शुरू से ही बचाव के उपायों पर जोर देते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीका आ जाने और लग जाने के बाद भी सुरक्षित दूरी और मास्क लगाने जैसे उपाय ही लोगों को महामारी से बचाएंगे और इनकी अनदेखी हमें फिर से गंभीर संकट में डाल सकती है। परीक्षण के दौरान कुछ टीकों के नतीजे संतोषजनक न मिलने की बातें भी सामने आईं। इससे टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में थोड़ा डर भी बना। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी टीकाकरण को लेकर अफवाहों से बचने और बचाव के उपायों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। हालांकि टीके वर्षों के लंबे प्रयोगों और परीक्षणों से गुजरने के बाद ही उपयोग के लिए बाजार में लाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने संपूर्ण मानकों के तहत जितने कम वक्त में कोरोना के टीके तैयार किए, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे में टीकाकरण को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त जनभागीदारी से इस अभियान को सफल बनाकर हम महामारी को हरा सकते हैं। इस बीच कई देशों की प्रयोगशालाओं में कोरोना का टीका तैयार करने का काम चलता रहा। पहले रूस से यह खबर आई कि वहां स्पुतनिक-वी नामक टीका तैयार हो गया जो इस महामारी से बचा सकेगा। समूचे परिदृश्य में इसे एक उम्मीद की तरह देखा गया और इसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए कई देशों के चिकित्सा वैज्ञानिक और ज्यादा पुख्ता टीका बनाने की कोशिश में लगे रहे। अब ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के कोरोना टीके को आपात इस्तेमाल के लिए ब्रिटेन के दवा नियामक की मंजूरी मिलने की खबर वैश्विक स्तर पर इस बीमारी से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 जनवरी, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

शिवराज का एक्शन

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का नया रूप देखने को मिल रहा है। वे वाकई एक्शन में नजर आ रहे हैं। ड्रग माफियाओं के खिलाफ कदम उठाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को इसी तरह अन्य माफियाओं पर भी नकेल कसनी चाहिए।

● **सुरेश धाकड़,** ब्यावरा (म.प्र.)

भेदभाव छोड़ना होगा

प्रदेश सहित देशभर में कुछ आदिवासी गांवों या अन्य विशिष्ट स्थितियों वाले गांवों को छोड़ दें, तो अधिकांश गांवों में जातिगत भेदभाव की विकराल समस्या है। अधिकांश गांवों में अनेक जातियां एकसाथ रहती हैं। हमें गांवों में ऐसी सोच को बरकरार रखना होगा जिससे भेदभाव को खत्म किया जाएगा।

● **विनीता वर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

स्मार्ट सिटी का हाल

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट घटिया निर्माण चर्चा में है। शहर की आम सड़कों की स्थिति भी स्मार्ट रोड से कही बेहतर है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सपने दिखाने का काम किया है। घटिया निर्माण कार्य के चलते कई स्थानों पर डिवाइडर जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं।

● **गौरव सैनी,** भोपाल (म.प्र.)

किसानों की समस्या सुने सरकार

देश की आबादी का दो-तिहाई हिस्सा हमारे किसान या कृषि सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। किसानों का आर्थिक कायाकल्प ही उसकी सब समस्याओं का संपूर्ण हल है। तब तक किसान कानूनों के संशोधन का झगड़ा उनके किसी काम न आएगा। फसलों का वैविध्यकरण, कृषि संबंधित सेवाओं का विनिर्माण और ग्रामीण युवा शक्ति को खेतीबाड़ी में अपने नए जीवन की तलाश करने का संदेश ही उनका मुक्ति प्रसंग है, न कि अराजक हो सकने वाले आंदोलनों की उथल-पुथल। सरकार को किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनसे बात करने के लिए आगे आना चाहिए। जब तक सरकार सामने आकर किसानों की नहीं सुनेगी, बात कैसे बनेगी।

● **पुरुषोत्तम गुप्ता,** राजगढ़ (म.प्र.)

जल्द होगा स्वच्छता सर्वे

कोरोना संक्रमण के कारण ज्यादातर नगरीय निकाय दूसरी व्यवस्थाओं में जुटे रहे और स्वच्छता सर्वे की गाइडलाइन के अनुरूप ज्यादा काम नहीं कर सके। इसी कारण कई शहरों के निकायों ने मंत्रालय के वॉटर प्लस और सेवन स्टार रेटिंग के लिए दावा पेश करने और स्वच्छता सर्वे के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था, जिसे मंत्रालय ने मान लिया है। स्वच्छता सर्वे अब मार्च 2021 में होगा, जबकि बाकी दोनों सर्वे 20 फरवरी बाद शुरू होंगे।

● **राजकुमार कुशवाहा,** इंदौर (म.प्र.)

मौजूदा सरकार दौड़ा रही कांग्रेस की नीतियां

केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का निजी स्वार्थ पूरा करने का ज्यादा सामर्थ्य नहीं बचा है और जो कार्यकर्ता विचारधारा की वजह से हैं, उनके सामने भी स्थिति अमूर्त है। जिस नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति को कभी कांग्रेस ने शुरू किया था, मौजूदा सरकार उसे ही बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा रही है। कांग्रेस की ओर से 'क्रोनी कैपिटलिज्म' को बढ़ावा देने की चाहे जितनी आलोचना की जाए, मूल नीतियों की न तो कोई समीक्षा की गई है और न उन्हें उलटने का कोई प्रस्ताव ही है।

● **अवनीश मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

महत्वाकांक्षा में उबाल

2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में मिली कामयाबी से अरविंद केजरीवाल भाजपा को बिना सांगठनिक ढांचे के ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की चूक तो कर ही बैठे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने भी पहुंच गए थे। पर बुरी तरह असफलता हाथ आई। पंजाब में लोकसभा की चार सीटें मिल गई थी। उसके बाद तो घोषित कर दिया था कि दिल्ली पर ही फोकस करेंगे। हालांकि पंजाब में जरूर पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता का ख्वाब पाल लिया था। पर बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। अब केजरीवाल की महत्वाकांक्षा फिर उभरी है। ऐलान किया है कि 2022 में उप्र और उत्तराखंड दोनों जगह उतारेंगे अपने उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस और भाजपा से खफा मतदाता उसकी झोली में आ जाएंगे। सपा और बसपा की जमीन खिसकने से भी इसकी संभावना बढ़ी है। सिसौदिया ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा का असंतुष्ट खेमा सिसौदिया के आरोपों से बम-बम नजर आया। अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज व विजय बहुगुणा जैसे नेता पार्टी में त्रिवेंद्र सिंह के वर्चस्व के चलते अपने भविष्य को अंधकारमय मान रहे हैं तो इसमें अटपटा तो कुछ है भी नहीं।

पानीपत की लड़ाई जैसा हाल

पश्चिम बंगाल में पानीपत की लड़ाई जैसा हाल दिख रहा है। भाजपा जहां ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है वहीं ममता बनर्जी भी आसानी से हार मानने वाली नहीं हैं। पहले उनके कुछ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की जबरन केंद्र में तैनाती का आदेश हुआ। फिर राज्यपाल की रिपोर्ट के हवाले से हवा चली कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। ममता फिर भी टस से मस नहीं हुई। अब कैलाश विजयवर्गीय उनकी पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। विधायकों, सांसदों और दूसरे नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना किसी भी तरह सुखद संकेत तो नहीं माना जा सकता पर केवल दल बदलुओं के बूते भाजपा भी अगर 200 सीटें जीतने का दम भर रही है तो इसे अभी तो दिवास्वप्न ही माना जाएगा। ममता जुझारू नेता हैं। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने से भाजपा की आस जगी है। पर 2016 में भी ममता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह मात दी थी। दिल्ली में भी सामने आ चुका है कि लोकसभा चुनाव जीतने का यह निश्चित नतीजा नहीं हो सकता कि विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही परिणाम आएगा।

खतरे की घंटी

नए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर भारत के किसान धरना तो दिल्ली में दे रहे हैं पर चिंता उत्तराखंड भाजपा की बढ़ गई है। सूबे के मैदानी इलाकों में सिखों की खासी तादाद है। ज्यादातर किसान हैं। रायवाला, डोईवाला, हरिद्वार और उधमसिंहनगर में सिख किसानों की तादाद इतनी है कि वे विधानसभा की कम से कम 30 सीटों को प्रभावित करते हैं। पिछले दो दशक से सूबे के सिखों का रुझान भाजपा के साथ रहा है। पर अब किसान आंदोलन को जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उसका खमियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सिख किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी दिखाने का सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में सुनियोजित प्रयास हुआ है, उसके दूरगामी नतीजे देश के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। मैदानी इलाकों में ही नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी किसान नाराज दिखते हैं। तभी तो पिथौरागढ़ जिला पूरी तरह बंद रहा। गनीमत है कि भाजपा नेताओं की आंख जल्दी खुल गई और वे किसान आंदोलन की काट में कूद पड़े हैं। मौके का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस किसानों के समर्थन में कूद पड़ी है। उसने भारत बंद का भी समर्थन कर दिया।

बेचैनी नीकु की

सुशील मोदी दिल्ली गए तो बिहार में भाजपा का कोई कद्दावर चेहरा दिखना ही बंद हो गया। कहने को तो तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही उपमुख्यमंत्री हैं। पर अभी तो नीतीश कुमार दोनों को ही खास भाव नहीं दे रहे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि वे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। नीतीश ने तपाक से जवाब दिया कि जब भाजपा कहेगी तब। इससे एक तरफ तो उनकी बेचारगी झलकी दूसरी तरफ यह साफ हुआ कि देरी भाजपा की तरफ से हो रही है। विधानसभा की संख्या 243 है। पंद्रह फीसदी के हिसाब से कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मेवालाल आर्य के इस्तीफे के बाद बचे हैं केवल चौदह। नीतीश का जवाब संजय जायसवाल को चुभ गया। तभी तो प्रतिक्रिया दे डाली कि भाजपा जल्दबाजी में फैसले नहीं करती। हकीकत तो यह है कि भाजपा साझा सरकार में अपनी हैसियत के हिसाब से अपना वर्चस्व चाहती है। नीतीश इस बार डरे हुए हैं। अपनी खोई जमीन को पुख्ता कर संभलने की कोशिश में हैं।

मेहनती नड्डा

उप्र और उत्तराखंड के चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है। पर अपने संगठन कौशल के बूते भाजपा अभी से तैयारी में जुटी है। खुद अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराखंड जैसे छोटे सूबे में लगातार चार दिन गुजारना उनकी गंभीरता का प्रमाण है। विधानसभा चुनाव की तैयारी से लेकर पार्टी के विधायकों, सांसदों व कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम साधु-संतों से सत्संग का वक्त निकाला भाजपा अध्यक्ष ने। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से मुलाकात कर सरकार के रंग-ढंग को भी जांचा परखा। अपनी मिलनसारिता, मृदुभाषी मिजाज और बिंदास अंदाज से वे हरिद्वार के साधु-संतों पर अच्छी छाप छोड़ गए। हरिद्वार में 4 दिसंबर को गंगा पूजन कर अपने 120 दिन का देशव्यापी अभियान शुरू किया। हैरान तो उन्होंने कनखल के जगद गुरू आश्रम में अचानक पहुंचकर वहां के पीठाधीश्वर शंकराचार्य राज राजेश्वराश्रम महाराज को कर दिया। जो संघी अतीत वाले तो हैं ही, संघ के मुखिया मोहन भागवत और सह महासचिव कृष्ण गोपाल के चितेरे हैं।

बड़े साहब की दखलअंदाजी

लोकतंत्र में मंत्रियों के हाथ में शासन और प्रशासन की बागडोर होती है। लेकिन अजब-गजब वाले मप्र में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां शासन और प्रशासन में अफसरों की धौंस है। आलम यह है कि मंत्रियों को अपने छोटे-छोटे काम के लिए बड़े साहब पर आश्रित रहना पड़ रहा है। दरअसल, प्रदेश में मंत्रियों की बातों को अफसर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कौन है यह तो दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़े साहब के इशारे पर यह सब हो रहा है। गत दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब बुंदेलखंड क्षेत्र से आने वाले एक मंत्रीजी को अपने काम के लिए बड़े साहब से गुहार लगानी पड़ी। दरअसल, खनिज विभाग से जुड़े उक्त मंत्रीजी की फाइलें विभाग के सचिव के पास पड़ी हुई थी। मंत्रीजी चाहते थे कि उक्त सचिव उस फाइल को क्लीयर करके जल्द से जल्द आगे बढ़ा दे। लेकिन सचिव मंत्रीजी की एक नहीं सुन रहे थे। सचिव से परेशान मंत्रीजी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने बड़े साहब को फोन करके आपबीती बताई। बताया जाता है कि मंत्रीजी को बड़े साहब ने कहा कि आप किसी भी काम के लिए अफसरों से कहने की बजाय सीधे मुझे बता दिया करें। मैं आपके काम को करवा दूंगा। बड़े साहब के इस कथन के बाद मंत्रीजी को यह अहसास हो गया कि साहब की दखलअंदाजी के कारण ही उनकी फाइल अब तक अटकी रही।

मंत्री और पीए की मनमानी

एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यह कहावत इन दिनों प्रदेश की एक मंत्री और उनके पीए पर चरितार्थ हो रही है। मंत्री अपनी दबंग छवि के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। उस पर उन्होंने एक निजी पीए रख रखा है। मंत्री के पीए का पूरा समय उगाही में लगा रहता है। आलम यह है कि पीए मंत्रीजी के विधानसभा वाले जिले में जमकर मनमानी कर रहे हैं। हर जगह मंत्री का नाम ले लेकर उगाही कर रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे अधिक रेत ठेकेदार हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्री के पीए सुबह होते ही इस अभियान में जुट जाते हैं कि किस तरह अधिक से अधिक लक्ष्मी जी की कृपा बटोरी जाए। बताया जाता है कि मंत्रीजी के निजी पीए को मंत्री का भरपूर समर्थन प्राप्त है। इस कारण वे जिले में कलेक्टर-एसपी को भी ठेंगे पर रखे रहते हैं। कभी-कभी स्थिति इस कदर बिगड़ जाती है कि कलेक्टर-एसपी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि जिले में वैध तरीके से रेत का खनन करने वाले ठेकेदार मंत्री के पीए की उगाही से इस कदर परेशान हैं कि वे अपना धंधा-पानी बटोरने का मन बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन करने वाले मंत्री और उनके पीए की शह पर चांदी काट रहे हैं।

नहीं गली दाल

प्रदेश के एक तेज तर्रार मंत्री अपने विभाग के हर कार्य में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। दरअसल, उक्त मंत्रीजी के ख्वाब बड़े-बड़े हैं। वे अपने आप को सरकार का कर्ता-धर्ता मानते हैं। इस कारण उनकी लगातार यही कोशिश रहती है कि शासन हो या प्रशासन हर जगह उनकी चले। मंत्रीजी के पास वर्तमान समय में प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा है। इस महकमे में आए दिन तबादले होते रहते हैं। गत दिनों एडिशनल एसपी स्तर के अफसरों के तबादले की सूची तैयार की गई। बकायदा ट्रांसफर बोर्ड ने उक्त सूची को फाइनल किया था। लेकिन मंत्रीजी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने इस तबादले की आड़ में अपनी दाल गलाने की कोशिश की। इसके तहत उन्होंने 6-7 डीएसपी के तबादले की एक सूची भी आगे बढ़ा दी। लेकिन मंत्रीजी यह भूल गए कि उनके विभाग के अफसर बड़े ही सचेत और संवेदनशील हैं। अफसरों ने एडिशनल एसपी की तबादला सूची के साथ मंत्रीजी द्वारा भेजी गई, डीएसपी के तबादला सूची को छन्ना लगाकर छान लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरी लिस्ट पर रोक लगा दी। इस कारण न तो एडिशनल एसपी के तबादले हो पाए और न ही डीएसपी के। यानी मंत्रीजी की दाल नहीं गल पाई। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी इस बात से खुश हैं कि उन्होंने अफसरों की नहीं चलने दी। मंत्रीजी की इस मनमानी से विभाग में असंतुलन की स्थिति बनती जा रही है।

मंत्रीजी ताकते रह गए

प्रदेश में सुशासन के लिए सरकार के मुखिया कमर कसे हुए हैं। कहने को तो इसके लिए उन्होंने अपने आसपास ईमानदार और साफ छवि के नौकरशाहों को बैठा रखा है। लेकिन इन नौकरशाहों में एक साहब ऐसे भी हैं जो मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ और दमदार मंत्री को भी दगा दे गए। दरअसल, ये वह साहब हैं जो हाल ही में आईएएस बने हैं। इन्होंने अपनी दमदारी दिखाते हुए निर्माण विभाग से जुड़े अफसरों का तबादला कर दिया। हद तो यह रही कि इसकी खबर मंत्रीजी को कानोंकान नहीं लगी। जब तबादला सूची जारी हुई तो मंत्रीजी को इसकी भनक लगी तो वे भौचक्के रह गए। प्रदेश सरकार में अपनी वरिष्ठता और दमदारी के लिए ख्यात मंत्रीजी इस सोच में पड़ गए कि आखिर बिना मेरे संज्ञान के मेरे ही विभाग में इतना बड़ा तबादला कैसे हो गया। लेकिन मंत्रीजी करते भी तो क्या करते। क्योंकि इस बार बड़ी आपाधापी के बाद तो उन्हें मंत्री पद मिला है। ऐसे में वह यह नहीं चाहते हैं कि अफसरों से पंगा लेकर अपनी भद पिटवाएं। इसलिए मंत्रीजी ने तबादले का विरोध करने की बजाय चुप रहना ही उचित समझा।

भाई-भतीजावाद

कांग्रेस को भाई-भतीजावाद के नाम पर कोसने वाली पार्टी में भले ही भाई-भतीजावाद कम है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले मंत्रियों का पूरा काम भाई-भतीजों और नाते-रिश्तेदारों ने संभाल रखा है। आलम यह है कि प्रदेश में लगभग हर मंत्री के जिले और उनके विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी भाई-भतीजों और नाते-रिश्तेदारों के जिम्मे है। यानी मंत्रियों के विभाग में उनके नाते-रिश्तेदारों की जमकर चल रही है। एक जिले में तो एक मंत्रीजी के बड़े भाई विभाग को चला रहे हैं। आलम यह है कि जिले में विभाग में वही हो रहा है जो मंत्रीजी के बड़े भाई चाहते हैं। वहीं एक मंत्रीजी का पूरा परिवार पार्टी और उनका विभाग चला रहे हैं। मंत्रीजी का बेटा, दामाद के साथ ही उनके रिश्तेदारों की जमकर चल रही है। इसका खामियाजा पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है। स्थिति यह हो गई है कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन वे करें भी तो क्या करें। क्योंकि संविधान की शपथ लेने वालों के आगे वे भी विवश हैं।

ईडी राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहा है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमें परेशान करने के लिए ईडी को माध्यम बनाया जा रहा है। अगर मैं अपनी पर आ गया तो भाजपा के कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ सकता है।

● **संजय राउत**

बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना किसी रणनीति का अंग नहीं है, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है। पीएम मोदी का मार्गदर्शन था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। इसलिए नीतीश के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाना उचित नहीं था। लोग कुछ भी सोचें, लेकिन वही हुआ जो होना चाहिए।

● **सुशील मोदी**

अजिंक्य रहाणे ने यह दिखा दिया है कि वे एक महान खिलाड़ी के साथ धैर्यवान कप्तान भी हैं। रहाणे जल्दी फैसले लेने वालों में नहीं हैं। जिस तरह से फील्डिंग सजाई और बॉलिंग चेंज की, उसकी तारीफ करनी होगी। दबाव और विषम परिस्थितियों में किस तरह कप्तानी की जाती है। यह अजिंक्य रहाणे ने दिखा दिया है। उन्हें आगे भी मौका मिलना चाहिए।

● **सुनील गावस्कर**

देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीन का कहीं अता-पता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सपना दिखा रही है। सरकार जनता को पहले यह बताए कि कोरोना वैक्सीन की प्रमाणिकता क्या है।

● **राहुल गांधी**

फिल्म रश्मि रॉकेट में मैं एक एथलीट का किरदार निभा रही हूं। मैंने एथलीट रूप पाने के लिए अपनी डाइट में कोई बदलाव नहीं किया। मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल इंडियन खाने से बेहतर कुछ नहीं है। पंजाबी लड़की होने के नाते मेरी खाने की आदतें भी आम पंजाबी परिवार के लोगों की तरह हैं। मैं पराठे को घी के साथ पसंद करती हूं। लेकिन रश्मि रॉकेट के लिए मुझे जिम में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर मेरे लुक की खूब तारीफ हुई है। अब उम्मीद है फिल्म को भी लोग इसी तरह पसंद करेंगे।

● **तापसी पन्नू**

वाक्युद्ध

देश के किसान अपनी खेती-किसानी को छोड़कर सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार किसानों पर ऐसे कानून को क्यों थोप रही है, जिसे किसान नहीं चाह रहे हैं। अगर किसान तैयार नहीं हैं तो सरकार को कृषि कानून वापस लेकर आंदोलन खत्म कराना चाहिए।

● **प्रियंका गांधी**

केंद्र सरकार किसानों को सुखी और संपन्न बनाना चाहती है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि किसानों के हित में कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां किसानों को बरगलाकर आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही हैं।

● **स्मृति ईरानी**

विधानसभा सत्र से परहेज क्यों?

विधानसभा का सत्र एक बार फिर टाल दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को इसकी वजह बताया जा रहा है। यद्यपि संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखकर सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं। भीड़ भरे राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल सत्र को टालने के कारण भाजपा की अंदरूनी राजनीति से जुड़े हुए हैं। मार्च में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा का कामकाज प्रोटेम स्पीकर के जरिए संचालित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का पद एक अनार सौ बीमार वाला हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आ जाने के बाद पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी बदल चुके हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है।

विधानसभा की बैठकें लगातार टाले जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह कहते हैं कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। पर्याप्त संख्या बल के बाद भी विपक्ष बैठकें बुलाने पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहा? इस सवाल के कटघरे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खड़े हुए हैं। कमलनाथ को भी इस बात का अहसास है। शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होना था। केवल तीन दिन का सत्र रखा गया था। विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के कुछ कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने को आधार बनाकर 27 दिसंबर को सत्र पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की ओर से जब बैठकें न रखने का कारण पूछा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उलटा सवाल किया कि यदि किसी विधायक को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कमलनाथ ने जवाबदारी सरकार पर डाली तो तत्काल सत्र टालने का निर्णय प्रोटेम स्पीकर ने ले लिया। बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव कुशवाह कहते हैं कि तीन दिन के सत्र में जनता के मुद्दे तो उठाए ही नहीं जा सकते थे। सत्र का टाला जाना ही बेहतर रहा। बसपा के दो विधायक मप्र में भाजपा के साथ हैं।

सत्र आहुत किए जाने की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी की गई थी। सत्र के पहले दिन उपचुनाव में निर्वाचित 28 विधायकों का शपथ ग्रहण होना था। सत्र टाल दिए जाने के कारण प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को अपने कक्ष में शपथ दिलाई। कांग्रेस ने इसी दिन किसानों के समर्थन में विधानसभा को घेरने की रणनीति बनाई थी। कांग्रेस के नेताओं का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन ट्रैक्टर पर बैठकर होना था। सत्र टल गया तो कांग्रेस को भी आंदोलन की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर में स्थापित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। सांकेतिक रूप से खिलौना ट्रैक्टर भी रखा। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी रहता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं की भीड़ थी। यहीं से नेता विधानसभा गए।

मंत्रिमंडल का विस्तार भी शिवराज के लिए मुश्किल भरा

28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा विधानसभा में पूर्ण बहुमत में है। कुल 126 सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस विधायकों के भाजपा में आने के कारण शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। सरकार सिंधिया के कारण बनी इसका दबाव भी मुख्यमंत्री चौहान पर साफ दिखाई दे रहा है। यद्यपि वे यह संदेश देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि सिंधिया भाजपा के सामान्य कार्यकर्त्ता हैं। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव जीतने के बाद भी सिंधिया के खांटी समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को मंत्रिमंडल में वापस शामिल नहीं किया है। छह माह के भीतर विधायक न चुने जाने के कारण उपचुनाव के नतीजों से पहले ही इन दोनों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शिवराज सिंह चौहान को डर है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में वरिष्ठ विधायकों की उपेक्षा हुई तो असंतोष बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहते, लेकिन संगठन वरिष्ठ भाजपा विधायकों के लिए दबाव बना रहा है। सिंधिया साफ तौर पर कह कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच का विषय है। विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में चौदह गैर विधायक भी रखे थे। तीन मंत्री चुनाव हार गए। इनमें दो इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया, सिंधिया समर्थक हैं।

तीन दिन के शीतकालीन सत्र में 29 दिसंबर का दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए रखा गया था। राज्य में मार्च में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के सभी कामकाज कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं। वे भोपाल जिले की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था नई विधानसभा के गठन के समय होने वाले सत्र के लिए की गई है। प्रोटेम स्पीकार का काम और कार्य अवधि स्पष्ट होती है। प्रदेश में पहला मौका है कि छह माह से विधानसभा का कोई अध्यक्ष नहीं है। शर्मा 2 जुलाई को प्रोटेम स्पीकर नामांकित हुए थे। मार्च में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार में अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति और उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष पद के दावेदारों में रामेश्वर शर्मा के अलावा पूर्व मंत्री अजय विश्नोई और राजेंद्र शुक्ला का नाम भी है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का नाम भी चर्चा में है। सीधी के विधायक केदार शुक्ला भी दावेदार हैं। विंध्य क्षेत्र के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का झुकाव राजेंद्र शुक्ला के नाम पर है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पद बने रहना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान पर शर्मा का भी दबाव है। शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं और केदार शुक्ला चौथी बार के विधायक हैं। पिछले कार्यकाल में भी केदार शुक्ला को मंत्री बनाने का दबाव था। विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही इस कारण सत्र टालना मुख्यमंत्री चौहान की मजबूरी है।

● **जितेंद्र तिवारी**

वर्तमान समय में कांग्रेस संक्रमण के दौर से गुजर रही है। पहले अहमद पटेल, फिर मोतीलाल वोरा के निधन के बाद पार्टी में एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत है जो इनके खालीपन को भर सके। इस कड़ी में मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल, कमलनाथ सोनिया गांधी के विश्वसनीय नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नाथ को सोनिया गांधी अपनी कोर कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वैसे नाथ के लिए मैदान खुला है।

कमलनाथ के सामने खुला मैदान

कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लोगों के सामने एक शिगूफा छोड़ा था- संन्यास लेने जैसा। शर्त भी रख दी, अगर छिंदवाड़ा के लोग चाहें। वे लोग जिन्होंने 9 बार वोट देकर उनको लोकसभा पहुंचाया और उनके बाद उनके बेटे नकुलनाथ को भी जिता दिया। वो भी तब जब मोदी लहर की आंच में कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी झुलस गए और अपने गढ़ में चुनाव हारने वाले पहले सिंधिया बने।

असल बात तो ये रही कि कमलनाथ मप्र में अब तक डेप्युटेशन पर रहे और जब उनके दिल्ली लौटने का रास्ता खुल गया तो संन्यास लेने और आराम करने का मूड होने जैसी बातें करने लगे। वरना, मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ वो मप्र कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद छोड़ने तक को तैयार न थे। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन लागू होने से पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था- आज के बाद कल आता है और कल के परसों भी आता है। कमलनाथ के बयान के कई तरीके से राजनीतिक मतलब निकाले गए थे, लेकिन उपचुनावों में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। लिहाजा वो 'कल' तो आया नहीं, शायद इसीलिए अब 'परसों' की तैयारी में लग गए हैं।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बरसों राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के निधन के बाद पार्टी को शिद्दत से उनके उत्तराधिकारी की तलाश है। जब अहमद पटेल के बाद कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाए जाने की बात चली, तो भी कमलनाथ का नाम संभावित लिस्ट में आया था, लेकिन फिर पवन कुमार बंसल की कुछ खासियतों के चलते फिलहाल उनको अंतरिम कोषाध्यक्ष बना दिया गया। मतलब, कमलनाथ के सामने अब भी खुला मैदान है और वो चाहें तो मप्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी की ही तरह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अहमद पटेल की जगह ले सकते हैं। सुनने में आया है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की मीटिंग के अघोषित संयोजक कमलनाथ ही हैं और ये मीटिंग ही कमलनाथ के आगे का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली है। सोनिया गांधी ने मीटिंग के दौरान राहुल गांधी को लेकर कमलनाथ को एक बहुत ही मुश्किल टास्क दे रखा है।

कमलनाथ की ये पहल कम से कम इस हिसाब से तो ठीक ही लगती है कि इसी बहाने अहमद पटेल की जगह लेने की कोशिशों में ये मीटिंग रिहर्सल का मौका मुहैया करा रही है और बाकी सब ठीक रहा, तो फिर कमलनाथ की बल्ले-बल्ले ही है। सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की एक अति महत्वपूर्ण बैठक ऐसे वक्त बुलाई गई है, जब कुछ बातें पहले से तय और निश्चित हैं, एक-

ये इम्तिहान है

कमलनाथ के लिए कांग्रेस में अब तक की राजनीति स्कूल टाइम जैसी ही रही है। ये पहला मौका लगता है जब उनको इम्तिहान देकर कुछ हासिल करना पड़ रहा है। कमलनाथ, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के साथ पढ़े हुए हैं और वही दोस्ती अब तक कांग्रेस में उनकी राजनीति को कायम रखे हुए है। इंदिरा गांधी उनको तीसरे बेटे की तरह मानती थीं और वो रिश्ता राजीव गांधी से होते हुए सोनिया गांधी के जमाने तक चला आ रहा है। हालांकि, आगे का सफर तय करने के लिए कमलनाथ को साबित करना है कि वो अहमद पटेल जैसे तो नहीं लेकिन बाकियों से बेहतर संकटमोचक बन सकते हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। कमलनाथ को अहमद पटेल जैसे नेता का उत्तराधिकारी बनना है जो गांधी परिवार के मौजूदा तीनों शक्ति केंद्रों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कभी भी उनके मोबाइल का नंबर डायल करने के मैंडेट हासिल किए हुए था।

कांग्रेस के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव, दो- सोनिया गांधी का यूपीए चेयरपर्सन पद भी छोड़ना और तीन- यूपीए के लिए नए चेयरमैन का चुनाव। हाल ही में यूपीए के नए चेयरमैन को लेकर शरद पवार का नाम उछला था जो एनसीपी के इंकार और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के सस्पेंस खड़ा करने के बीच गायब भी हो गया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीब हफ्ता भर गोवा में बिताने के बाद दिल्ली लौटने पर ये मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते डॉक्टरों ने सोनिया गांधी को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाने की सलाह दी थी। जाने से पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए कुछ कमेटियां भी बनाई थीं जिनमें चिट्ठी लिखने वाले जी-23 नेताओं को भी जगह दी गई थी और अब होने जा रही मीटिंग में करीब आधा दर्जन ऐसे नेताओं के शामिल होने की भी संभावाना जताई जा रही है। सोनिया गांधी के दिल्ली लौटने के बाद कमलनाथ दो बार उनसे मिल चुके हैं और राहुल गांधी की नए सिरे से संभावित ताजपोशी से पहले रास्ते की अड़चनों को दूर करने का दावा करते हुए कुछ करने की पहल की है। सुना है सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मिल चुके हैं।

सोनिया गांधी को लगने लगा है कि जिस तरीके से जी-23 नेता सक्रिय हैं, कहीं ऐसा न हो राहुल गांधी के अध्यक्ष चुनाव के दौरान जितेंद्र प्रसाद जैसा वाकया न हो जाए। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर जब आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी तो जितेंद्र प्रसाद ने बगावत कर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी।

अगर जितेंद्र प्रसाद जैसा विरोधी रुख अपनाते हुए किसी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ध्यान रहे जब जितेंद्र प्रसाद ने चैलेंज किया था, सोनिया गांधी के पक्ष में सारे कांग्रेसी खड़े हो गए थे और वो अकेले पड़ गए। ऐसा ही तब भी हुआ था जब शरद पवार के साथ कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने को मुद्दा बनाकर बगावत कर डाली थी, तब भी सोनिया गांधी का जादू चला और विरोध आसानी से दब गया।

मौजूदा माहौल काफी अलग है। सोनिया गांधी को लेकर तो कांग्रेस में अब भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर आम सहमति नहीं है। ये सही है कि राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस में खासी एकजुटता है, लेकिन सच तो ये भी है कि वो आम सहमति जैसी तो कतई नहीं है।

हाल फिलहाल, जी-23 के चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को काफी सक्रिय देखा गया है। बिहार चुनाव के बाद कुछ सीनियर नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंग हुई है। गुलाम नबी आजाद जी-23 के सर्वमान्य नेता बने हुए हैं और कपिल सिब्बल झंडा लेकर आगे-आगे चल रहे हैं। ऐसे कुछ नेताओं और कमलनाथ के बीच भी संवाद हुआ था और फिर सोनिया गांधी से मुलाकात में कमलनाथ ने असंतुष्ट नेताओं का संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की। कमलनाथ ने अपनी तरफ से ऐसे नेताओं को बुलाकर उनकी बात सुनने की सोनिया गांधी को सलाह दी तो वो तैयार हो गईं।

कमलनाथ की वफादारी पर सोनिया गांधी को अहमद पटेल जैसा भरोसा भले न हो, लेकिन मौजूदा दौर में उनकी नजर में जो भी ऐसे नेता होंगे उनमें कम भी नहीं है। लगता है यही सब सोचकर सोनिया गांधी ने कमलनाथ के सामने उनको नए संकटमोचक की भूमिका में आने और कुछ ठोस नतीजे हासिल करने का काम सौंपा है और इन कामों में सबसे ज्यादा अहम है राहुल गांधी के रास्ते की बाधाओं को खत्म करना।

राहुल गांधी के राजनीतिक राह की बाधाएं भी बला की तरह हैं जो बगैर बताए किसी भी तरफ से आ धमकती हैं। कभी अमेरिका से बराक ओबामा किताब लिखकर उनकी कमजोरियां बताने लगते हैं तो कभी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में हिस्सेदार एनसीपी नेता शरद पवार निरंतरता की कमी बताने लगते हैं। बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि राजनीतिक विरोधी भाजपा नेता ऐसी बातों को लेकर हमलावर हो जाते हैं, मुश्किल ये है कि कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी को नाकाबिल मानने वाले नेता भी ऐसी बातों को खूब हवा देते हैं।

कमलनाथ को ऐसी ही मुश्किलों का हल निकालकर कांग्रेस नेतृत्व के दिल और दल में भी बराबर मजबूत जगह बनाने की चुनौती है और यही वजह है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की इस मीटिंग को मनमाफिक नतीजे पर ले जाना भी कमलनाथ के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा ही है। मगर, कुदरत के कुछ नियम ऐसे होते हैं कि कभी भी मंजिल की कोई राह आसान नहीं होती।

● **कुमार राजेन्द्र**

कमलनाथ पीसीसी चीफ रहेंगे या दिल्ली जाएंगे फैसला 3 को

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर दिल्ली में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? यह 3 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में तय हो सकता है। हालांकि कमलनाथ कह चुके हैं कि वे फिलहाल मप्र में ही रहेंगे। लेकिन कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे, यह लगभग तय हो चुका है। आगे यह जिम्मेदारी किसे मिलेगी, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि सीनियर विधायक डॉ. गोविंद सिंह और बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गोविंद सिंह की पैरवी कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ कैंप बाला बच्चन के लिए लॉबिंग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इसको लेकर कमलनाथ ने कहा है कि यह विधायक आपसी सहमति के आधार पर तय करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ 6 जनवरी तक दिल्ली में रहेंगे। वे 3 जनवरी को होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बुलाई गई है। जिसमें अगले एक महीने में पार्टी के अध्यक्ष पद सहित कार्यसमिति के 12 सदस्यों के चुनाव कराने के लिए तैयारी को लेकर निर्णय होना है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भूमिका भी इस दौरान तय होने की संभावना है। क्योंकि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा को निधन के बाद 10 जनपद के भरोसेमंद नेता कमलनाथ हैं।

जाल में अफसर

क रे कोई और भरे कोई की तर्ज पर मप्र के 4 अफसर जांच के घेरे में पड़ गए हैं। मप्र सरकार ने 4 अफसरों के खिलाफ जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। सरकार की चिट्ठी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कैश कांड में मप्र के 4 बड़े पुलिस अफसर नपेंगे? बता दें कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कैश कांड की जांच के बाद इन अफसरों पर कार्रवाई के लिए मप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद 17 दिसंबर को मप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिस पर जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को पत्र लिख **मामले** की जांच करने को कहा है। पत्र में जिन चार अधिकारियों के नाम हैं उनमें आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने, वी मधुकुमार और राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा हैं।

दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ सरकार के समय मप्र में पड़े आयकर विभाग के छापों के दौरान चारों अफसरों और नेताओं के **बीच पैसों** के कथित लेनदेन का जिक्र मिला था। इन छापों ने मप्र के साथ-साथ देश की सियासत को भी गरमा दिया था जिसने काफी तूल पकड़ा था। बता दें कि 5 जनवरी को सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को चुनाव आयोग में जवाब देना है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि उससे ठीक पहले ईओडब्ल्यू को मामले की जांच सौंपी गई है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारतीय पुलिस सेवा के मप्र कैडर में पदस्थ तीन अधिकारियों के समेत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं जिन पर 2019 के आम चुनाव के दौरान कालाधन ले जाने के आरोप लगे थे। आयकर विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिजनों और उनके सहयोगियों के यहां मारे गए छापों के बाद आरोप लगाए गए थे। आयोग ने केंद्रीय मुख्य सचिव से भी इन अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। मप्र के मुख्य सचिव से भी इसी तरह की कार्रवाई करने को कहा गया है। आयकर विभाग ने छापों में पाया था कि 2019 के आम चुनाव में भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग की शीर्ष संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चुनाव आयोग को भेजी थी। आयोग ने कहा कि उसने इस रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद ही यह निर्देश दिए हैं।

4 अफसरों पर है आरोप

जिन 4 अफसरों पर आरोप लगे हैं, उनमें सुशोभन बैनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार आईपीएस अधिकारी हैं जबकि अरुण मिश्रा मप्र राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आयकर विभाग दिल्ली की इंवेस्टिगेशन विंग ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, मोजेर बियर कंपनी के मालिक भांजे रतुल पुरी और एक अन्य कारोबारी अश्विन शर्मा के 52 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। 8 अप्रैल को आयकर विभाग ने 14.6 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की थी। इसके साथ बड़े पैमाने पर डायरियां और कम्प्यूटर फाइल जब्त की थीं। इनमें सैकड़ों करोड़ रुपए के लेनदेन के हिसाब थे। बाद में आयकर विभाग ने बताया था कि दस्तावेजों में यह प्रमाण मिले हैं कि 20 करोड़ रुपए की राशि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजी गई। इन छापों में कुल 281 करोड़ रुपए के लेनदेन के पुख्ता प्रमाण मिले थे। यह पैसा विभिन्न कारोबारियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों से एकत्र किया गया था। यह 20 करोड़ रुपए की नकदी हवाला के माध्यम से तुगलक रोड स्थित एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय को भेजी गई थी।

चुनाव आयोग से जारी बयान के मुताबिक सीबीडीटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि इन अधिकारियों की एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से कुछ लोगों तक पहुंचाने में भूमिका रही है। आयोग ने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह बोर्ड का इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर है। चुनाव आयोग ने मप्र के सीईओ को 28 अक्टूबर 2020 को ही यह रिपोर्ट भेज दी थी। इसमें सीईओ को निर्देश दिए गए थे कि वह तीन अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराए।

आयकर विभाग की जांच में यह सामने आया था कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय को 20 करोड़ नहीं, बल्कि 106 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त विकास ढींगरा नामक व्यक्ति के खाते में 72 करोड़ रुपए भेजे गए। आयकर विभाग की यह जांच **विकास ढींगरा** नामक व्यक्ति पर भी केंद्रित रही। जिसमें पाया गया है कि ढींगरा अप्रैल 2019 को ही विदेश चला गया था। इसके बाद अब तक नहीं लौटा। हालांकि विभाग का दावा है कि वह इस रकम के लेनदेन का सीधे लाभार्थी नहीं है। वह केवल रकम एक जगह से दूसरी जगह भेजने का माध्यम भर है।

सूत्रों के मुताबिक 7 अप्रैल 2019 को आयकर ने छापे मारे थे, उनमें मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी 5 लोग शामिल थे। जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों के लेनदेन के सबूत मिले थे। इसके बाद इकट्ठा किए गए सबूत और रिपोर्ट सीबीआई को भेज दिए गए थे। आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को जो साक्ष्य और जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान 11 उम्मीदवारों को कथित तौर पर भारी रकम ट्रांसफर किए जाने का आरोप है। यह जानकारी दिल्ली के एक शख्स ललित कुमार चेलानी के कम्प्यूटर से मिली थी। चेलानी एक अकाउंटेंट हैं, जो कमलनाथ के **करीबी** आरके मिगलानी के साथ काम कर चुके हैं। चेलानी के खाते से ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को रकम का भुगतान करने के सबूत आयकर को मिले थे।

सूत्रों के मुताबिक 11 लोकसभा उम्मीदवारों को चेलानी के माध्यम से रकम मिली थी। हालांकि भुगतान से जुड़ी रसीदें सिर्फ दो उम्मीदवारों सतना से राजाराम प्रजापति और बालाघाट से मधु भगत के मामले में मिली थी। अन्य जिन उम्मीदवारों को फंड मिलने का आरोप है, वे हैं- मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, मंडला से कमल मांडवी, शहडोल से प्रमिला सिंह, सीधी से अजय सिंह, भिंड से देवाशीष जरारिया, होशंगाबाद से शैलेंद्र सिंह दीवान, खजुराहो से कविता सिंह, भोपाल से दिग्विजय सिंह और दमोह से प्रताप सिंह लोधी।

● **सुनील सिंह**

एक्सटेंशन पर डायल-100

मप्र में चलाई जा रही डायल-100 योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस योजना को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। यह फैसला गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की वर्चुअल बैठक में लिया गया। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद् ने डायल-100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में 6 माह यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक तथा फिर 6 माह यानी 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है।

वर्तमान डायल-100 योजना की अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए योजना को वर्तमान स्वरूप में आगामी 5 वर्ष के लिए निरंतर संचालन हेतु मंत्रिपरिषद आदेश आयटम क्रमांक-5 दिनांक 12 सितंबर 2019 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। खुली निविदा के माध्यम से नवीन सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में विलंब होने एवं **अनुबंधित** फर्म मेसर्स-बीवीजी इंडिया लिमिटेड की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने के दृष्टिगत योजना की महत्वता एवं जन सुरक्षा की आवश्यक सेवा होने के कारण, तत्समय मंत्रिमंडल गठित नहीं होने से 30.03.2020 को समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर सिस्टम इंटीग्रेटर फर्म मेसर्स-बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ निविदा की अनुमोदित दर पर ही अनंबंध अवधि में 6 माह (1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक) का विस्तार किया गया था।

डायल-100 योजना को अगले 5 वर्ष के लिए निरंतर संचालन के लिए नवीन सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन हेतु खुली ई-निविदा दिनांक 18.03.2020 से 30.07.2020 तक संपादित की गई, जो कि विश्व व्यापी कोरोना महामारी संकट के कारण सरकार द्वारा 23 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन प्रभावशील रहने, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मार्च-2020 के पश्चात बीएस6 उत्सर्जन श्रेणी के वाहनों का ही आरटीओ रजिस्ट्रेशन प्रावधानित होने तथा इस श्रेणी के वाहन बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने आदि प्रमुख कारणों के चलते निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न फर्मों के अनुरोध को मान्य करते हुए कोरीजंडम के माध्यम से 5 बार टेंडर अवधि में वृद्धि करने के बावजूद भी किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया है। तथा निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। अत: री-टेंडर कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय मंत्रिमंडल गठित नहीं होने से दिनांक 01.10.2020 को समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर डायल-100 योजना के निरंतर संचालन हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स-बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में पुन: 6 माह (1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक) का विस्तार किया गया था।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डायल-100 योजना के **निरंतर संचालन** हेतु अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में 6 माह (1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक) की वृद्धि हेतु दिनांक 30.03.2020 को मुख्यमंत्री द्वारा समन्वय में दिए गए अनुमोदन पर मंत्रिपरिषद का अनुसमर्थन प्रार्थित है। डायल-100 मप्र सेवा की शुरुआत 1 नवंबर 2015 को हुई। राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 कॉल सेंटर में उपलब्ध संसाधन, 130 टीबी का डाटा सेंटर, 1000 मोबाइल डाटा टर्मिनल, जीआईएस मैप जिस पर पूरे प्रदेश के थानों का क्षेत्राधिकार का सीमांकित किया गया है, कम्प्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम, कॉल्स को हैंडल करने के लिए कॉल मैनेजमेंट सिस्टम आदि से लैस है, डायल-100 पर प्राप्त होने वाले कॉल की रिकॉर्डिंग हेतु वायस लॉगर। अगस्त 2018 में 33 जिलों में डायल-100 वाहनों की पहुंच शहरी क्षेत्र की संकीर्ण गलियों तक सुनिश्चित करने हेतु 150 मोटरसाइकिल एफआरवी वाहन उपलब्ध कराए गए। डायल-100 सेवा के 1000 एफआरवी वाहन एमडीटी, वायरलैस सेट, मोबाइल फोन, जीपीएस, पीए सिस्टम तथा आपात स्थिति में उपयोग होने वाली एक्स्ट्रेक्शन किट के साथ संपूर्ण प्रदेश के 1000 स्थानों पर 24 घंटे तैनात हैं।

● **रजनीकांत पारे**

थाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अदालत ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। दरअसल, अदालत की मंशा यह है कि थानों में होने वाली हर गतिविधि पर कैमरे की नजर रहे। गौरतलब है कि थानों में शिकायत दर्ज कराने जाने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी शिकायत समय पर दर्ज नहीं की जाती है। ऐसे में अदालत ने प्रदेश के सभी थानों के हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। अदालत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने थानों में कैमरे लगाने के लिए योजना बना ली है। इसके लिए विभाग ने वित्त विभाग को 140 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव भेजा है। इस बजट के मिलते ही प्रदेश के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या थानों में कैमरे लगाए जाने से पुलिस के व्यवहार में बदलाव आएगा? गौरतलब है कि देश में पुलिस के प्रति आमजन में अविश्वास की भावना भरी हुई है। इस अविश्वास की भावना को दूर करने के लिए समय-समय पर कई प्रयोग किए जा रहे हैं। मप्र में सरकार थानों को सर्वसुविधायुक्त बना रही है। अब देखना यह है कि प्रदेश के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद जनता का विश्वास पुलिस पर कायम होता है या नहीं। एक बात तो तय है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने से पुलिस की कार्यप्रणाली में जरूर बदलाव आएगा।

लव जिहाद पर अंकुश

देशभर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे लव जिहाद पर अब भाजपा शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने लगा है। दरअसल, दूसरे धर्मों की युवतियों खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों द्वारा जबरिया, प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी पूर्वक किए जाने वाले विवाहों के मामले सामने आते रहे हैं। क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है। क्या इसे खत्म करने के लिए देश में एक कड़े कानून की आवश्यकता है। लव जिहाद का मुद्दा एनसीआर के नोएडा ही नहीं बल्लभगढ़ की निकिता हो या कानपुर से लेकर इंदौर तक, भोपाल से लेकर बागपत तक जिधर भी देखो लव जिहाद की खबर सामने आ रही है। साहिल खान साहिल सिंह बन जाता है और एक मासूम को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर एक शर्मनाक खेल खेला जाता है। ये खेल बागपत, भोपाल, केरल, इंदौर देश के हर कोने में होता है। ऐसे में क्या इस पर देशव्यापी कानून बनने का वक्त आ चुका है। देशभर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे लव जिहाद पर अब भाजपा शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने वाला है। उप्र के बाद अब मप्र ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाकर उस पर नकेल कस दी है।

उप्र की योगी सरकार की तरह ही मप्र की सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश लागू करने जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून में जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी, उनको भी अपराधी बनाया है। सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का प्रावधान किया है। सरकार इस कानून को लागू करने जा रही है।

26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। इसे 6 महीने के अंदर पास कराना होगा। ऐसे में इस बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। मप्र से पहले उप्र में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया। यहां पर 26 नवंबर को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूरी दी थी। वहां विधानसभा सत्र नहीं होने के कारण अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, जबकि मप्र में विधानसभा सत्र प्रस्तावित था, लेकिन इसके स्थगित होने के कारण अब इसे अध्यादेश के रास्ते लाया गया है।

लव जिहाद की पृष्ठभूमि उस विषैले दर्शन में निहित है, जिसमें विश्व को 'मोमिन' और 'काफिर' के बीच बांटा गया है। जिसके अनुसार, प्रत्येक सच्चे अनुयायी का यह मजहबी कर्तव्य है कि वह काफिरों की झूठी पूजा-पद्धति को नष्ट कर तलवार, छल, फरेब और प्रलोभन के माध्यम से उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करे या फिर मौत के घाट उतार दे। चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इसी मानसिकता ने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, तैमूर, बाबर, अलाऊद्दीन खिलजी आदि कई विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। इसी जिहाद ने 70 वर्षों में पाकिस्तान की जनसंख्या को शत-प्रतिशत इस्लाम बहुल कर दिया है। क्या यह सत्य नहीं कि विभाजन के समय जिस पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में 15-16 प्रतिशत आबादी हिंदू, सिख और जैन आदि अनुयायियों की थी, वे आज एक प्रतिशत रह गए हैं? पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के प्रति जिहाद आसान है। भारत में 79 प्रतिशत आबादी हिंदुओं की है, इसलिए यहां पाकिस्तान की भांति तौर-तरीके अपनाकर गैर-मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करना कठिन है। इसी कारण यहां जिहाद के लिए तथाकथित प्रेम का प्रयोग किया जा रहा है। साल 2009 में, रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने माना था कि केरल और मैंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। तब उन्होंने केरल सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम के नाम पर, किसी को धोखे या उसकी मर्जी के बगैर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

लव जिहाद के ज्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते रहे हैं। आरोपी को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधी कानूनों के तहत भी केस चलते रहे हैं। इसके अलावा, बलपूर्वक शादियों के मामले में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत सजा दे सकते हैं। महिला की सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी पेंच यहां फंसता रहा है कि मुस्लिम शादियां शरीयत कानून और हिंदू शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनन होती हैं। चूंकि मुस्लिम शादियों में सहमति दोतरफा अनिवार्य है इसलिए इन शादियों में अगर यह साबित हो जाता है कि सहमति से ही शादी हुई थी, तो कई मामले सिरे से खारिज होने की नौबत तक आ जाती है।

● **प्रवीण कुमार**

10 साल की सजा का प्रावधान

कानून में बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, माता-पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है। सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा।

कांग्रेस पर उपेक्षा कर आरोप लगाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए हैं और अभी तक उन्होंने जैसा चाहा है भाजपा ने उन्हें वैसा दिया है। लेकिन अभी भी सिंधिया को उस तोहफे का इंतजार है, जिसके वे पात्र हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का।

ज्योतिरादित्य को तोहफे का इंतजार

जन्मदिन पर उपहार मिले तो हर किसी को अच्छा लगता है। बच्चे हैं तो खिलौने, चॉकलेट, कपड़े। युवा हैं तो बाइक, कार, घड़ी, चश्में। महिला हैं तो गहने, साड़ियां। बुजुर्गों को बच्चों की अटेंशन की चाहत होती है। अगर आप राजनेता हैं तो समर्थकों का हुजूम, शुभकामनाओं के होर्डिंग्स और बैनर से पटा शहर आपकी लोकप्रियता का ग्राफ दर्शाता है। एक जनवरी को महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का 50वां जन्मदिन है। उनके पास बाकी तो सभी चीजे हैं। इंतजार है तो दिल्ली दरबार से मिलने वाले उपहार का। इस उपहार को पाने के लिए उन्होंने नए दल की सभी अहर्ताएं पूरी कर ली हैं। सूबे में सरकार पलटकर न सिर्फ शिवराज को गद्दी पर बिठा दिया बल्कि उपचुनाव में अच्छी सीटें जितवाकर सरकार को स्थायित्व भी दिला दिया। अब जिम्मेदारी सरकार की है वह महाराज को स्वर्णिम जन्मदिन पर मनवांछित उपहार दे।

माना जा रहा है कि नए साल में सिंधिया को उनकी मंशानुसार तोहफा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले सिंधिया जिस तरह अपने समर्थक विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनवाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, उससे तो एक बात साफ है कि वे किसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए उनकी कोशिश है कि अपने समर्थक विधायकों को जल्द से जल्द मंत्री बनवा दें। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए ग्वालियर के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सीहोर में भाजपा जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर जवाब दिया कि अभी तो माफियाओं को निपटा रहा हूं।

खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम से बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए गए नेताओं में से दो विधायक (तुलसीराम सिलावट एवं गोविंद सिंह राजपूत) मतदान से पहले कार्यकाल खत्म हो जाने के कारण इस्तीफा दे चुके हैं और चुनाव हार जाने के कारण इमरती देवी, एदल सिंह कंसाना और गिर्राज दंडोतिया के 6 महीने का कार्यकाल दिसंबर के साथ खत्म होने जा रहा है। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से बार-बार मिल रहे हैं। प्रदेश भाजपा की नई टीम नए साल में आ सकती है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को भी भाजपा संगठन ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इन दोनों मुद्दों पर गाइडलाइन प्रदेश में सत्ता और संगठन को प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव दे गए हैं। इसके तहत सत्ता और संगठन के नए चेहरे नए साल में साफ हो जाएंगे। संभावना है कि पहले हफ्ते में ही टीम आ जाए।

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों प्रदेश भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण में पूरे दिन शिरकत की थी। सिंधिया ने प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश भाजपा की नई टीम को लेकर भी इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। इसके बाद मुरलीधर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाइडलाइन को साफ कर दिया है। इसके तहत प्रदेश भाजपा की नई टीम का ऐलान जनवरी में हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सिंधिया की बात मानी जाना तय हो गया है। कम से कम गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट की शपथ को जल्द कराया जाएगा। बाकी 4 पदों को लेकर सिंधिया और शिवराज के समन्वय से तय होगा। हारे हुए तीन मंत्रियों के पुनर्वास को लेकर भी सिंधिया की बात को महत्व दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा की नई टीम में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर दिखेगा। संभावना है सबसे पहले नई टीम आएगी। इसमें सिंधिया समर्थकों को समायोजित करने की लाइन भी पार्टी ने दी है। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह और सिंधिया के सबसे ज्यादा समर्थक नई टीम में रहेंगे। पार्टी युवाओं को नई टीम में मौका देना चाहती है। इससे सिंधिया समर्थकों की एंट्री आसानी से होने का रास्ता खुल गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते एक महीने में तीन बार मप्र का दौरा कर चुके हैं। सिंधिया के दौरे को देखते हुए मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार और वीडी शर्मा की टीम के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बीते एक महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई बार मुलाकात कर चुके हैं।

● **लोकेंद्र शर्मा**

सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी

ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कई चीजें चुनौतियां बनकर खड़ी हो गई है। केंद्र में उनका अपना मंत्री पद और मप्र की सत्ता एवं संगठन में अपने समर्थकों का प्लेसमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। यदि वह चूक गए तो कांग्रेस पार्टी में उनके नाम से काफी किरकिरी होगी। फिलहाल उनका नाम लेकर लोग कांग्रेस हाईकमान की पॉलिसी को गलत बताते हैं, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में सफल नहीं हो पाए तो गांधी परिवार से जुड़े कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की असफलता का वर्षों तक उदाहरण देंगे। इसलिए सिंधिया की हर पल यही कोशिश है कि वे अपने समर्थकों को सरकार और संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने के साथ ही अपने आपको भी केंद्रीय सरकार में स्थापित करें।

नए कृषि कानून को लेकर देश के कई राज्यों में किसान आक्रोशित हैं, लेकिन मप्र के किसान मंडी सिस्टम से खुश हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में सरकार ने कोरोनाकाल में गेहूं, चना, मूंग, उड़द, धान और चना के बाद हरड़, बहेड़ा, चिरोंजी के साथ लघु वनोपज खरीद की जो व्यवस्था बनाई, वह किसानों को भरोसा दिलाती है कि यहां उनके हित सुरक्षित हैं। इसलिए यहां का किसान कानून का विरोध नहीं कर रहा है।

80 फीसदी किसान मंडी सिस्टम से खुश

नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उप्र सहित कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मप्र के किसान इसमें शामिल नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मप्र के अन्नदाताओं को विश्वास है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तो उनका विकास निर्बाध होता रहेगा। दरअसल, पिछले 9 माह के दौरान कोरोना महामारी का संकट होने के बावजूद शिवराज और उनकी सरकार ने किसानों के साथ ही हर वर्ग का जिस तरह ख्याल रखा है, उससे उनके प्रति जनता का विश्वास प्रगाढ़ हुआ है।

मप्र में इस समय सीमांत व छोटे किसान मिलाकर कुल 1.10 करोड़ काश्तकार हैं। इनमें से 50 लाख किसानों पर कर्ज है। लेकिन उसके बावजूद किसान खुशहाल हैं। इसकी वजह यह है कि शिवराज सरकार किसानों के साथ खड़ी है। यही कारण है कि प्रदेश के लाखों किसानों को आलू-प्याज और सब्जियों पर एमएसपी का इंतजार है, फिर भी किसान आंदोलन में शामिल नहीं, क्योंकि अनाज-दलहन-तिलहन पर एमएसपी और मंडियों की व्यवस्था से 80 प्रतिशत तक किसान संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ मांगें ऐसी हैं, जो पूरी हो जाए तो किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

दरअसल मप्र गांवों का प्रदेश है और यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर वे बेहद संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि मप्र के किसानों ने बीते कुछ वर्षों में सफलता के कीर्तिमान गढ़े हैं और अब किसान कल्याण और कृषि उत्पादन में प्रदेश का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाने लगा है। इस समय समूचा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है। इसका प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ा है और समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं। अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चुनौती का समय होने के बाद भी किसानों के हितों पर कोई आंच न आए, इसका ध्यान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बखूबी रखा जा रहा है। समय-समय पर किसानों को राहत राशि ट्रांसफर की जा रही है। उधर, किसानों द्वारा रबी सीजन में की गई कड़ी मेहनत को पूरे देश में सराहा गया है। इस वर्ष गेहूं उत्पादन में प्रदेश के किसानों ने जो इतिहास रचा, उससे मप्र देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। किसानों की इस उपलब्धि के ऐवज में राज्य सरकार द्वारा किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। यही नहीं प्रदेश सरकार ने किसानों से तिवड़ा लगा चना भी खरीदा। पूर्व में 13 क्विंटल चना खरीदी की अनुमति थी, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा कर चना खरीदी लिमिट को 20 क्विंटल तक बढ़ाया गया। पूर्व में मप्र के 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिलता था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 77 लाख किसानों तक कर दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश का किसान लाभान्वित हो, इसका बेहतर प्रबंधन शिवराज सरकार द्वारा किया गया और वर्ष 2020 में पुन: सरकार में आते ही किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा की पुरानी किश्त भरने का काम किया जिसका भरपूर लाभ प्रदेश के किसानों को मिला है। फसल बीमा की न्यूनतम

नए कृषि कानून से किसानों को ऐसे हो रहा फायदा

नए कृषि कानून का असर अब दिखना शुरू हो गया है, किसानों को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। मप्र में दो मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें नए कृषि कानून ने किसानों की बड़ी मदद की। पहला मामला डबरा क्षेत्र का है, जहां प्रशासन किसानों की कमाई लेकर भागे व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर उन्हें पैसा लौटाएगा। वहीं दूसरा मामला बालाघाट का है जहां किसानों का पैसा न देने पर राइस मिलर पर मामला दर्ज होगा। इसी तरह होशंगाबाद जिले में पिपरिया एसडीएम ने नए कृषि कानून के तहत कंपनी को किसानों से अनुबंध के आधार पर धान खरीदने का आदेश दिया था। इसके पहले कंपनी अनुबंध पर तय किए गए दाम के मुताबिक खरीदी नहीं कर रही थी, जिसके बाद किसान अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें न्याय मिला। वहीं डबरा क्षेत्र में किसानों की उपज का 40 लाख रुपए भुगतान नहीं करके भाग गए एक व्यापारी की संपत्ति कुर्क होगी। ग्वालियर जिला प्रशासन कुर्क संपत्ति से किसानों का पैसा वापस दिलाएगा।

राशि को लेकर सरकार नए नियम बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और जिसका लाभ हमारे किसान परिवारों को मिलेगा। प्रदेश के किसानों को अब फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके द्वारा उत्पादित कच्चे माल का उपयोग फूड प्रोसेसिंग में कर रोजगार भी बढ़ाए जाएंगे। जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले की उद्यानिकी फसल को पहचान दिलाने की कोशिशें भी प्रारंभ की गई हैं। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सहकारी बैंक का भरोसा बेहद जरूरी है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए भरने का ऐलान कर दिया है। साथ ही भावांतर के 470 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की है।

देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर करती है। देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। मौजूदा समय में कृषि, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है और देश के श्रमिकों के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से को आजीविका प्रदान करती है। कोविड-19 की वजह से पैदा आर्थिक मंदी के बीच 2020-21 में आर्थिक स्थिरता के लिए इसका योगदान और भी अधिक होने की उम्मीद है। मप्र का देश की जीडीपी में मप्र का योगदान 5 प्रतिशत है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 30 से 35 प्रतिशत योगदान किसानों का है। इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भलीभांति समझते हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं। भारतीय किसान सेना के प्रदेशाध्यक्ष केदार पटेल और सचिव जगदीश रावलिया का कहना है किसानों की ताकत को भाजपा सरकार ने पहचाना है। यही कारण है कि पिछले एक दशक में मप्र का किसान सबल हुआ है।

मप्र के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं कि नए कृषि कानूनों से किसानों का कोई नुकसान हो सकता है। इसकी ठोस वजह है। मप्र के किसानों ने हाल में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर बाजरे की उपज बेची है जो देश के अधिकतर राज्यों के मुकाबले अधिक है। नए कृषि कानून के तहत पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी मप्र के क्रय केंद्रों पर बाजरा बेचा। चूंकि राज्य सरकार लक्ष्य से अधिक बाजरा खरीदने को तैयार थी, इसलिए किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। जाहिर है, राज्य में नए कृषि कानूनों का डंका बजने लगा है। किसानों को इनका लाभ मिलने लगा है। होशंगाबाद जिले का मामला उल्लेखनीय है। इसे नए कृषि कानून का पहला प्रभाव माना जा रहा है। दरअसल, एक कंपनी ने किसानों से अनुबंध किया कि वह मंडी से 50 रुपए अधिक मूल्य पर उनका धान खरीदेगी। गत 9 दिसंबर को जिले की पिपरिया मंडी में धान की कीमत 2,950 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। अनुबंध के मुताबिक किसान अपनी उपज 3,000 रुपए की दर पर बेचना चाहते थे तो कंपनी टालमटोल करने लगी। इसकी शिकायत मिलने पर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ और नए कानून के तहत कंपनी को तय अनुबंध पर धान खरीदने पर बाध्य किया।

होशंगाबाद के किसान मानते हैं कि यह नए कृषि कानून से संभव हुआ, अन्यथा कंपनी इस मूल्य पर उनका उपज नहीं खरीदती। यह देखने की बात है कि क्या किसी अन्य राज्य में धान की खरीद 3,000 रुपए मूल्य पर हुई? दरअसल, किसानों का हित किसी हद तक राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। मप्र सरकार की नीतियां किसान-हितैषी हैं। इस राज्य में अधिकतर जिंसों का एमएसपी पंजाब और हरियाणा से भी अधिक है। इसके अलावा, राज्य में एमएसपी से कम मूल्य पर किसी भी उपज की बिक्री नहीं होती है। राज्य में भावांतर योजना भी प्रभावी है जिसके तहत यदि किसान की उपज एमएसपी से कम मूल्य पर बिकती है तो अंतर की भरपाई खुद राज्य सरकार करती है। यही वजह है कि इस राज्य में एमएसपी या नए कृषि कानूनों को लेकर एक भी विवाद नहीं है।

किसान आंदोलन के नाम पर देश के दूसरे राज्यों में जहां गरमाहट है, वहीं मप्र में सन्नाटा है। किसान अपने काम में व्यस्त हैं। दिल्ली के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बड़े चेहरों में एक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कक्काजी मप्र के हैं। उनके खाते में वर्ष 2011 में भोपाल का ऐतिहासिक महाजाम आंदोलन शामिल है, लेकिन इस बार दिल्ली आंदोलन की धमक से मप्र के किसान बेफिक्र हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि दिल्ली आंदोलन में कक्काजी की उपस्थिति के बावजूद आखिर मप्र में सन्नाटा क्यों है? दरअसल, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा, ज्वार की खरीद चल रही है। किसान अपनी उपज बेचने और नई फसल की देखरेख में जुटा है। इसके पीछे राज्य सरकार की वह अनूठी पहल है जो किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिला रही है।

● **नवीन रघुवंशी**

खेती का कायाकल्प होगा

संघ के एक नेता कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मोदी सरकार के नए कानूनों का किसानों के एक वर्ग द्वारा तीखा विरोध जारी है। इन किसानों के मन में शंका है कि नए कृषि कानूनों से उनकी आमदनी खतरे में पड़ सकती है। यह स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा दिला चुके हैं कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और न ही मंडी व्यवस्था। इससे किसानों को आश्वस्त होना चाहिए, लेकिन वे उलटे आक्रोशित हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इन किसानों का भ्रम और बढ़ा रहे हैं। केंद्र ने जो तीन कृषि कानून बनाए हैं, उनकी लंबे अर्से से प्रतीक्षा की जा रही थी। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की व्यवस्था तब बनाई गई थी, जब हम अपनी आबादी का पेट भरने में ही सक्षम नहीं थे। इसके उलट आज ऐसे अधिशेष की स्थिति है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदामों में अनाज रखने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है। ऐसे में भारत को खाद्यान्न के मोर्चे पर अकाल से अधिशेष की स्थिति का लाभ उठाने की दिशा में अग्रसर होना ही होगा। इसी कारण सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का उचित फैसला किया है।

भोपाल को सौगात

स्वच्छता के मामले में देश की नंबर-1 राजधानी को विकास का मॉडल बनाने के लिए मप्र सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट रोड और आर्च ब्रिज समेत शहर के प्रमुख पांच प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोपाल को मप्र ही नहीं देश का मॉडल शहर बनाना है, ये विकास कार्य उसी तारतम्य में कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आर्च ब्रिज के उद्घाटन पर कहा कि रानी कमलापति की स्मृति में एक मेला लगाया जाएगा। रानी कमलापति आर्च ब्रिज टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करके लाइटिंग लगाई जाएगी, उनकी स्मृति, इतिहास दिखाई दे, ताकि भोपाल दूर से ही दिखाई दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छतम राजधानियों में भोपाल का नाम है। इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। अब भोपाल के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, यह दोगुनी गति से किया जाएगा। आगामी 5 साल के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। सारी रूपरेखा जल्द ही हम प्रस्तुत करेंगे।

इससे पहले उन्होंने स्मार्ट रोड और फिर स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया। इसके बाद जाटखेड़ी स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन और शिरीन नदी पर तैयार एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकास कार्य किए गए हैं।

गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी के साथ ही मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी के मामले में भोपाल देश में पहले स्थान पर है। यहां विकास के काम निरंतर जारी हैं। प्रदेश सरकार के साथ में जिला प्रशासन विकास कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग कर रहा है। इसी तरह मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए चल रहे निर्माण कार्य राजधानी में तेजी से जारी हैं। इंदौर की अपेक्षा यहां अधिक काम हुआ है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि राजधानी में हो रहे अन्य विकास कार्य भी तेजी से चलें। जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है।

विकास कार्यों के लोकार्पण की श्रृंखला में स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया गया। भारत माता चौराहा से पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित स्मार्ट रोड के पास लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ में बनाया गया है। पार्क में पहुंचने के लिए 3.6 मीटर चौड़ा पाथवे बनाया है। पार्क के लगभग 24 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट और साढ़े चार हजार वर्गमीटर का क्षेत्र पार्किंग बनाई गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी के पेन सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की पहली स्मार्ट रोड भारत माता चौराहा से पॉलीटेक्निक चौराहा तक बनाई गई है। सड़क की कुल लंबाई 2.2 किमी है। इसकी लागत 43 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दो मीटर की यूटीलिटी डक्ट बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट पोल, साइकिल ट्रैक व फुटपाथ भी बनाया गया है।

स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है। इसमें ठोस अपशिष्ट निष्पादन के लिए तीन आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस कचरा ट्रांसफर स्टेशन से साकेत नगर, शक्ति नगर, बागमुगालिया और आसपास के रहवासियों को फायदा होगा। नवनिर्मित ट्रांसफर स्टेशन में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी की पेन सिटी योजना के तहत छोटे तालाब पर गिन्नौरी से किलोल पार्क क्षेत्र को जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण किया गया है। ब्रिज की कुल लंबाई 200 मीटर है। दोनों ही ओर कुल 534 मीटर की अप्रोच रोड बनाई गई है। ब्रिज की चौड़ाई 10.75 मीटर और आर्च की ऊंचाई 30 मीटर है। नगर निगम द्वारा कोहेफिजा शिरीन नदी पर 6.47 करोड़ रुपए की लागत से 5 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं चार इमली क्षेत्र में लगभग 5.50 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है। इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण से शहर एवं तालाबों को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकेगा।

जिन विकास कार्यों का लोकार्पण गत दिनों किया गया, उससे शहर की तस्वीर बदल गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य सभी विकास कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा कराकर उनका लोकार्पण कराया जाएगा।

● **अरविंद नारद**

शहर सरकार बनाने भाजपा का मास्टर प्लान

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है। भाजपा ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अब अंत्योदय समितियों के गठन की तैयारी कर ली है। सरकार समितियों को पावरफुल बनाने का काम करेगी। समितियों के जरिए वार्ड स्तर पर अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश होगी। भाजपा ने जो प्लान तैयार किया है। उसके तहत वार्ड स्तर से लेकर नगर निगम स्तर तक अंत्योदय समितियों का गठन होगा, जिसके जरिए सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी। निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भी समितियों के जिम्मे होगा। समितियां वार्ड स्तर से लेकर शहरों के विकास का भी रोडमैप तैयार करेंगे। सरकार ने जो प्लान तैयार किया है। उसके तहत नए साल की शुरुआत में सरकार अंत्योदय समितियों के गठन का फैसला करेगी। इसके जरिए सरकार की बड़ी योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना खाद्य पर्ची का वितरण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करने का काम होगा। साथ ही समिति इस बात पर भी नजर रखेगी की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर भी समितियों को नजर रखने का अधिकार होगा। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अंत्योदय समितियां गठित करने पर विचार कर रही है। समितियों के जरिए विकास का रोडमैप तैयार होगा। इसको लेकर सरकार जल्दी फैसला करेगी।

सड़क की राह नहीं आसान

विकास की नई परिभाषा में प्रगति का एक रास्ता सड़क से होकर गुजरता है लेकिन मप्र में सड़क की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। इसकी वजह है बजट का अभाव। प्रदेश में लोक निर्माण विकास द्वारा सड़कों के संधारण, सड़कों के नवीनीकरण, सेतु निर्माण कराए जाने हैं, लेकिन विभाग के पास बजट का अभाव है। इसलिए विभाग ने वित्त विभाग को 1540 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। अगर वित्त विभाग समय पर उक्त राशि उपलब्ध करा देता है तो सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है।

प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं, वहां सड़कों का निर्माण किया जाए। लेकिन सड़कों का निर्माण करने वाली सरकार एजेंसी लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त बजट नहीं मिल पा रहा है। इसका असर यह हुआ है कि विभाग पर करीब 900 करोड़ की देनदारी है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य कैसे हो पाएगा, यह चिंता का विषय है।

लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सड़कों के संधारण के लिए 89 करोड़ मिले थे, जिसमें से विभाग ने 53 करोड़ खर्च किए। इसी तरह सड़कों के नवीनीकरण के लिए 150 करोड़, आवासीय भवनों के संधारण कार्य के लिए 59 करोड़, नई सड़कों के निर्माण के लिए 1015 करोड़, सेतु निर्माण के लिए 160 करोड़ सड़कों के मजबूतीकरण के लिए 210 करोड़ मिले थे। विभाग ने समय सीमा में उक्त राशि से विकास कार्य करवाया है। अब नया कार्य करवाने और मरम्मतीकरण के लिए करीब 1540 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब देखना यह है कि वित्त विभाग उक्त राशि कब तक मुहैया कराता है।

गौरतलब है कि अमेरिका की सड़कों से टक्कर लेने का दावा करने वाली टोल की सड़कों पर गड्ढों के रूप में बड़े-बड़े काले धब्बे उभर आए हैं। हालत यह है कि इन सड़कों की ऊपरी परत ही गायब बताई जा रही है। इन पर सरपट दौड़ने वाले वाहन भी हिचकोले खाने लगे हैं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के नाम पर हर साल 8 हजार करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद स्थिति निराशाजनक है। प्रदेश सरकार स्वयं मान रही है कि इस साल प्रदेश में अतिवृष्टि से कुल 5954 किमी सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। 1015 पुल-पुलियाएं भी जर्जर हुई हैं। इनकी मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सरकार से 1540 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। जाहिर है आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और निर्माण की राह आसान नहीं है।

पीडब्ल्यूडी के ही एक आला अधिकारी ने हाल ही में मालवा-निमाड़ और महाकौशल अंचल का दौरा किया। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है कि टोल वाली सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। ग्रामीण सड़कों की तुलना में बड़े शहरों की सड़कें ज्यादा परेशान कर रही हैं। स्टेट हाईवे जैसी स्थिति ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्गों की है, मेंटेनेंस न होने से ज्यादातर एनएच की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं।

मप्र सरकार के सामने बदहाल सड़कें चुनौती बनी हुई हैं। प्रदेश के करीब पांच दर्जन मार्गों पर टोल टैक्स चुकाने के बावजूद वाहन गड्ढेदार सड़कों पर हिचकोले खाने को विवश हैं। दोहरा टैक्स चुकाने के बावजूद प्रदेश के नागरिकों को सरपट सड़कें नसीब नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं विभागीय अधिकारियों को सड़कों की तकनीक सुधारने की नसीहत दे चुके हैं। उधर सड़क निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो मप्र में अन्य राज्यों की तुलना में सड़क बनाने की तकनीक और इच्छा शक्ति दोनों की कमी है। केरल और मुंबई की सड़कें ज्यादा बारिश झेलने के बावजूद हमसे बेहतर क्यों बनी रहती हैं, इस सवाल का जवाब न तो प्रदेश के सड़क विकास निगम के पास है और न ही लोक निर्माण विभाग के पास।

मप्र में सड़क निर्माण के बारे में बात करें तो तकनीक, स्पेसिफिकेशन, मॉनिटरिंग और पूरे सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। हमारे यहां सड़क पर यदि गड्ढा हुआ तो उसके बड़े होने का इंतजार होता है, तुरंत ही उसका इलाज नहीं किया जाता जबकि दिल्ली-मुंबई में मेंटेनेंस तुरंत होता है। यही कारण है कि वहां सड़कें ज्यादा खराब नहीं हो पातीं।

● राकेश ग्रोवर

कोलार की सड़कों का 414 करोड़ में होगा उन्नयन

राजधानी को आसपास के शहरों से जोड़ने वाले व्यस्ततम मार्गों पर ट्रैफिक की आवाजाही आसान बनाने की तैयारी है। कोलार मुख्य मार्ग और लिंक रोड नंबर 3 को 414 करोड़ रुपए खर्च कर दुरुस्त किया जाएगा। सर्विस रोड भी अपग्रेड होगी। साथ ही अयोध्या बायपास पर बिना रुके वाहनों के मूवमेंट के लिए 337 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। खास बात यह है कि सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) योजना में राशि मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र इस योजना में राज्यों को सड़क व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए राशि देता है। पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के अन्य राज्यों की राजधानी की तरह नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जनप्रतिनिधि भी कई बार कह चुके हैं कि शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके अनुरुप अधोसंरचनाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। सुविधाएं व विकास न होने से अपेक्षित निवेश नहीं आ रहा है। केंद्र की योजनाओं का उचित फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके मद्देनजर जनप्रतिनिधियों ने शहर के दो मुख्य मार्गों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव सीआरआईएफ योजना में भेजने के निर्देश दिए हैं।

31 गौण खनिज की ई-नीलामी

रेत की तर्ज पर अब प्रदेश में सुलेमानी पत्थर (अगेट), चूना कंकड़, अभ्रक, ऑकर, चाक, चीनी मिट्टी, बालू (अन्य) शेल, स्लेट और स्टोटाइट सहित 31 गौण खनिज की भी ई-नीलामी होगी। मप्र सरकार ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन करते हुए 31 गौण खनिजों को इसमें शामिल कर लिया है। अब ऑनलाइन आवेदन पर खनन का पट्टा मिलेगा। पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया। पट्टाधारी गौण खदानों में काम करने वाले 75 प्रतिशत लोग मप्र के ही हैं।

मंत्रिपरिषद् ने मप्र गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें अनुसूची 5 के 31 गौण खनिजों के उत्खनन पट्टा आवेदन/ई-निविदा से आवंटन करने के प्रावधान किए गए हैं। संशोधन अनुसार निजी भूमि पर भूमि-स्वामी/सहमति धारक को रायल्टी के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन के आधार पर उत्खनन पट्टा स्वीकृत करने के प्रावधान किए गए हैं। संचालक उत्खनन पट्टा विभागीय मंत्री के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत कर सकेंगे। शासकीय व निजी भूमि पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र पर ई-निविदा के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिए अनुसूची 5 के उत्खनन पट्टा आवंटन करने के प्रावधान किए गए हैं। उच्चतम निविदाकार को देय रॉयल्टी के अलावा स्वीकृत ई-निविदा दर से वन टाइम बिट के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। संचालक शासकीय भूमि पर तथा शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त क्षेत्र पर राज्य सरकार से तथा निजी भूमि पर विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्वीकृत कर सकेंगे।

निजी भूमि अथवा ई-निविदा से अनुसूची 5 के स्वीकृत उत्खनन पट्टों में 25 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक निवेश कर उद्योग स्थापित करने पर उत्खनन पट्टे का 10-10 वर्ष के लिए दो बार नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुसूची 1 और 2 के खनिजों के 4 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के उत्खनन पट्टे कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृत किए जा सकेंगे। इसमें 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र स्वीकृत करने के अधिकार संचालक को दिए जा रहे हैं। अनुसूची एक के खनिजों के मामलों में स्वीकृति से पहले संचालक द्वारा विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुसूची एक में पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा) को शामिल किया जा रहा है। इससे अब पत्थर से रेत बनाने के उत्खनन पट्टे भी स्वीकृत हो सकेंगे। गौण खनिज रेत बजरी की रॉयल्टी दर 125 रुपए प्रति घन मीटर निर्धारित की गई। यह भी प्रावधान किया गया है कि बाहर के राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गौण खनिज पर 25 रुपए प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क लिया जाएगा।

फर्शी पत्थर की वार्षिक डेडरेंट की राशि दो लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर रुपए 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। पट्टाधारी को स्वीकृत खदानों में से 75 प्रतिशत रोजगार मप्र के मूल निवासियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सरकारी तालाब, बांध आदि से गाद के साथ निकाली गई रेत का निर्वर्तन मप्र गौण खनिज नियम 1996 एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत किया जाएगा। नियमों अनुसूची 5 (31 गौण खनिज) की रायल्टी व डेडरेंट की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। विभिन्न आवेदन शुल्क, न्यायालयीन स्टाम्प शुल्क, प्रतिभू निक्षेप, सुरक्षा राशि, रेखांक शुल्क में भी वृद्धि की गई है। अनुसूची 5 के खनिजों के लिए उत्खनन पट्टे के लिए नए आवेदन शुल्क एवं सुरक्षा राशि भी निर्धारित की गई हैं। नियम में उपरोक्त अनुसार संशोधन करने से न केवल प्रदेश के खनिज राजस्व में भारी वृद्धि संभावित हैं बल्कि गौण खनिज के खदानों में प्रदेश के मूल निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलना संभावित है। इसी के साथ प्रदेश में खनिज आधारित निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार पिछले पांच साल से नियम बना रही थी। नए नियमों के तहत सरकार पत्थर से रेत बनाने के लिए पट्टा भी देगी। इसके साथ ही सरकार ने खनिज के दाम भी तय कर दिए हैं। अब मंत्री के अनुमोदन से संचालक उत्खनन पट्टा दे सकेंगे। वहीं चार हेक्टेयर तक के खनिज पट्टे कलेक्टर जिला स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले गौण खनिज पर 25 रुपए घनमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। अभी तक पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर आवेदन करने वालों को खदान आवंटित करने का प्रविधान था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 31 मुख्य खनिजों को गौण खनिज घोषित किया है। राज्य सरकार फरवरी 2018 में इनको गौण खनिजों की सूची में शामिल कर चुकी है, पर नियम न होने के कारण खदानों की नीलामी नहीं हो रही थी। इससे राज्य सरकार को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। कोरोनाकाल में सरकार को खाली खजाना भरने के लिए गौण खनिज की याद आई और अब नियम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस खनिज के 100 से अधिक आवेदन दो साल से खनिज विभाग में पड़े हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

ये होंगे अब गौण खनिज

अगेट, बॉल क्ले, बैराइट्स, कैल्केरियस सैंड, कैल्साइट, चॉक, चीनी मिट्टी, अन्य क्ले, कोरण्डम, डायस्पोर, डोलोमाइट, डयुनाइट अथवा पायरोसेनाइट, फेलसाइट, फेल्सपार, अग्निसह मृत्तिका, फुरुकाइट क्वार्टजाइट, जिप्सम, जस्पर, कयोलिन, लेटेराइट, चूना कंकड़, अभ्रक, ऑकर, पाइरोफाइलाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट, बालू (अन्य) शेल, सिलिका बालू, स्लेट और स्टोटाइट अथवा टैल्क या सोपस्टोन। कैबिनेट ने भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत किसी परिवार के पुनर्वास के लिए ग्रामों में सरकारी भूमि मिल जाती है, तो जिस एजेंसी के लिए भू-अर्जन किया जा रहा है, उससे सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य की 1.6 गुना राशि लेकर विकास कार्य कराए जाएंगे। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित एजेंसी से भुगतान कराकर ग्रामों की निजी भूमि पर पुनर्वास कराया जाएगा।

करे कोई भरे कोई

बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली का भी जवाब नहीं। डिफाल्टरों से करोड़ों रुपए की वसूली नहीं करने वाली प्रदेश की तीनों कंपनियां अब इसकी भरपाई ईमानदार उपभोक्ताओं से करने की तैयारी में है। इसके लिए उनके पास एक ही हथकंडा बिजली की दर बढ़ाने का है। कंपनी ने डिफाल्टरों की 3,212 करोड़ रुपए की राशि माफ कर उसे बट्टे खाते में डाल दिया। अब नियामक आयोग से इसकी भरपाई के लिए याचिका लगाई है। प्रदेश के कई आम उपभोक्ताओं ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। 5 जनवरी को नियामक आयोग मामले की सुनवाई करेगा।

बिजली की दरों में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी कंपनियां आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका देने की तैयारी में हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से मप्र विद्युत नियामक आयोग में सत्यापन याचिका दायर की गई है। वर्ष 2018-19 की इस राशि की भरपाई अब करने के लिए गुहार लगाई है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर इसकी भरपाई कराई जाए। पावर मैनेजमेंट की ओर से पेश की जाने वाली टैरिफ याचिका में डूबत खातों का विवरण दिया जाता है।

यह ऐसे उपभोक्ता होते हैं, जिससे बिजली बिल का बकाया वसूल कर पाने में कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं। वसूली नहीं कर पाने की स्थित में इसे डूबत खाते में डाल दिया जाता है। सूत्रों की मानें तो यह प्रदेश का एक बड़ा स्कैंडल है। इसमें बड़े उद्योगपतियों के बिल माफ करने का खेल किया जाता है। इसकी मलाई में सभी बंदरबांट करते हैं। सूची सार्वजनिक न होने से ऐसे चेहरे अभी तक बेनकाब नहीं हो पाए। जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने 771.35 करोड़ डिफाल्टरों के माफ किए। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने 762.68 करोड़ और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने 1678.07 करोड़ रुपए डिफाल्टरों के माफ किए हैं।

विद्युत नियामक आयोग ने 2018-19 की टैरिफ याचिका के समय 6 करोड़ रुपए पहले ही डिफाल्टरों की माफ कर चुकी है। तब याचिका में डिफाल्टरों की कुल 326 करोड़ रुपए माफ करने की मांग की गई थी। आयोग ने तीनों कंपनियों से इसका डिटेल मांगा, जो वे पेश नहीं कर पाई। इसके बाद आयोग ने तीनों कंपनियों को दो-दो करोड़ रुपए का टोकन देते हुए सत्यापन याचिका पेश करने का निर्देश दिया था। अब जाकर सत्यापन याचिका पेश की गई है और आयोग से 3206 करोड़ रुपए माफ करते हुए इसकी भरपाई कराने का आग्रह किया गया है।

टैरिफ रेग्युलेशन 2015 के मुताबिक कुल प्राप्त राजस्व का अधिकतम एक प्रतिशत ही माफ किया जा सकता है। वह भी पूरा डिटेल देने के बाद ही आयोग ऐसा कर सकता है। इसमें कंपनी को बताना पड़ता है कि वसूली के लिए क्या प्रयास किए। इलेक्ट्रिसिटी डेफ्थ रिकवरी एक्ट का पालन किया गया की नहीं। इस एक्ट में कुर्की का प्रावधान है। किसानों से बकाया वसूलने के लिए इसी एक्ट के तहत उनके वाहन और कृषि संबंधी उपकरण उठा लाती हैं। वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व 30 हजार करोड़ की थी। ऐसे में 3212 करोड़ की राशि 10 प्रतिशत से अधिक बन रहा है। नियामक आयोग भी इस राशि को माफ नहीं कर सकता है।

विद्युत मामलों के जानकार अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल और राजेश चौधरी ने बताया कि कंपनियां हर बार मनमानी करती हैं। पहले नियमों को ताक पर रखकर डिफाल्टर उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाता है। इसके बाद इसकी भरपाई नियमित और ईमानदारी से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से की जाती है। उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि ऐसे डिफाल्टरों की सूची सार्वजनिक की जाए। इससे पता चलेगा कि ऐसे कौन लोग हैं। साथ ही इसकी जवाबदारी तय करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों से भरपाई करनी चाहिए।

एक तरफ जहां बिजली कंपनियों ने डिफाल्टरों के करोड़ों रुपए माफ किए, वहीं अब आम उपभोक्ताओं पर भार डाल दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच अब बिजली भी महंगी हो गई है। नए टैरिफ में 8 पैसे से लेकर 20 पैसे तक दाम बढ़ाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि 51 से 150 यूनिट की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता पर की गई है। इसके साथ ही नॉन डोमेस्टिक में फिक्स चार्ज भी 150 रुपए प्रति किलोवॉट से बढ़ाकर 153 रुपए कर दिया है। नए साल में लोगों को बिजली के बिल नए टैरिफ के हिसाब से मिलेंगे। दिसंबर माह के बिल जनरेट हो चुके हैं, ऐसे में जनवरी में बढ़े बिल नहीं मिलेंगे, क्योंकि नई दरें अपडेट होंगी और फरवरी में मिलने वाला बिल नई टैरिफ दर से आएगा।

विद्युत नियामक आयोग ने पिछले साल 17 अगस्त-2019 को वर्ष 2019-20 के लिए टैरिफ जारी किया था। इस साल करीब 4 महीने देरी से 26 दिसंबर 2020 से आगामी आदेश तक के लिए नए टैरिफ अनुसार नई दरें लागू कर दी हैं। हालांकि अधिकारियों के अनुसार दिसंबर माह का बिल तो जनरेट हो चुका है। अब जनवरी से लागू करेंगे। आयोग ने उपभोक्ताओं को मीटर चार्ज में राहत भी दी है। नए टैरिफ में मीटर चार्ज खत्म कर दिया है। अभी तक सिंगल फेस पर 10 रुपए, थ्री फेस पर 25 व 10 किलोवॉट से अधिक के कनेक्शन पर 125 रुपए प्रतिमाह मीटर चार्ज लगता था। अब उपभोक्ताओं को यह नहीं देना होगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

टैरिफ की ये रहेंगी नई दरें

100 वॉट लोड तक के प्रतिमाह 30 यूनिट खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर नए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके साथ ही निम्न दाब वाले उद्योग, विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम के लिए अस्थाई कनेक्शन लेने वालों के लिए टैरिफ में वृद्धि नहीं की गई है। औद्योगिक टैरिफ नहीं बढ़ने से बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर बिजली बिलों का भार नहीं बढ़ेगा। सरकार द्वारा 100 यूनिट पर 100 रुपए बिल पर फिलहाल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे लेकर शासन ने नया आदेश नहीं दिया है, इसलिए फिलहाल यथावत ही बिल जाएंगे।

नकली खाद का लंबा है नेटवर्क

म प्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को खुशहाल और संपन्न बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नकली खाद और बीज का धंधा जोरों पर चल रहा है। हाल ही में संस्कारधानी जबलपुर में नकली खाद के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है। खजरी-खिरिया बायपास पर 22 दिसंबर को हुए नकली खाद फैक्ट्री का नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। अब माढ़ोताल क्षेत्र के ग्रीन सिटी में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहां 40 लाख रुपए के रॉ मटेरियल और तैयार प्रोडक्ट मिले हैं। रिहायशी इलाके में एक मकान में चल रहे इस गोरखधंधे की जानकारी खजरी-खिरिया की कार्रवाई के दौरान ही मयंक खत्री ने दी थी। पुलिस इसके संचालक फूल सिंह लोधी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गत दिनों इस सील मकान को खोलकर तलाशी ली गई तो इसका खुलासा हुआ। इसके भी लंबे लिंक मिले हैं।

जानकारी के अनुसार माढ़ोताल ग्रीन सिटी गली नंबर पांच में दुर्गा मंदिर के पास एक मकान में ये गोरखधंधा चल रहा था। इस नकली खाद फैक्ट्री के संचालक फूल सिंह लोधी को माढ़ोताल पुलिस ने तीन दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। उसी के बाद इस मकान को सील कर दिया गया था। गत दिनों कृषि विभाग के उपसंचालक एसके निगम और अधारताल एसडीएम ऋषभ जैन की अगुवाई में टीम पहुंची और घर को खोला गया। यहां भी खजरी-खिरिया बायपास की तरह नमक, कोयला, डोलोमाइट डस्ट, चूना आदि रॉ मटेरियल मिक्स कर नकली खाद बनाया जा रहा था।

कृषि विभाग के उपसंचालक एसके निगम के मुताबिक 21 दिसंबर को अमर कृषि फार्म पर जो कार्रवाई की गई थी, उसी दौरान इसके बारे में मालूम चला था। पुलिस ने तभी सील कर दिया था। इस मकान को खोला गया, तो यहां विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट, पैकिंग व रॉ मटेरियल मिले। बड़ी मात्रा में सील पैक, रैपर, खाली पैकेट मिले हैं। शंका है कि यह गोरखधंधा और नामी कंपनियों के नाम पर प्रोडक्ट बेचने का काम अर्से से चल रहा था। यहां काछी एग्रो नाम का तैयार प्रोडक्ट मिला है। इसका मुख्य ऑफिस इंदौर में है। लगभग 40 लाख रुपए का रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट मिला है।

एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया कि मकान मालिक और किराएदार दोनों पर कार्रवाई होगी। यहां दूसरी ब्रांडेड कंपनियों के नाम से प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा था। खजरी-खिरिया बायपास की तुलना में यहां कई अन्य ब्रांडेड कंपनियों के नाम से तैयार नकली प्रोडक्ट मिला है। बड़ी मात्रा में रैपर, खाली पैकेट, सील करने की मशीन आदि जब्त हुई है। यहां से कई जगह सप्लाई हो रही थी। उसका भी लिंक मिला है। उन पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में अलग से एफआईआर होगी।

खजरी-खिरिया बायपास पर 22 दिसंबर को क्राइम ब्रांच और माढ़ोताल की संयुक्त टीम ने दबिश देकर नकली खाद-कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस नकली फैक्ट्री के संचालक बीटी तिराहा निवासी मयंक खत्री को उसी रात टीम ने नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं अमर कृषि फॉर्म स्थित छह हजार वर्गफीट के गोदाम में दो करोड़ रुपए कीमत की सामग्री जब्त करते हुए मौके से पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था। मयंक से पूछताछ के आधार पर टीम ने उसी रात चेरीताल में संचालित महेश बीज-भंडार की दुकान को सील कर दिया था। दरअसल इस दुकान का संचालक मयंक का भाई महेश खत्री था। महेश मप्र, उप्र, असम व छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। इसके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।

कृषि विभाग द्वारा महेश बीज भंडार की जांच की। जांच में प्रतिष्ठान में लाइसेंस की शर्तों के विपरीत दूसरी कंपनियों के कीटनाशक और खाद मिले। वहीं उसके बिल-बाउचर की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि वह मप्र सहित उप्र, असम व छत्तीसगढ़ में भी नकली खाद व कीटनाशक की सप्लाई करता था। दुकान में स्टॉक पंजीयन तक नहीं मिला। कृषि विभाग के उप संचालक डॉ. एसके निगम के मुताबिक दुकान संचालक महेश खत्री के खिलाफ कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। नकली खाद-कीटनाशक की फैक्ट्री चलाने वाले मयंक ने पूछताछ में बताया कि वह मार्बल पाउडर और कोयला सिवनी टोला से मंगवाता था। वहीं नमक के पैकेट खोवा मंडी से थोक में छह रुपए की दर से खरीदता था। रैपर व कई अन्य सामान वह राजस्थान से बुलवाता था। वहीं कीटनाशक की बोतल वह इंदौर से मंगवाता था।

● **विकास दुबे**

16 गुना मुनाफे का खेल

दोनों ही स्थानों पर नकली खाद में नमक, पत्थर का चूरा, कोयला व चूना आदि का उपयोग किया जा रहा था। वहीं कीटनाशक तैयार करने में कोयले सहित सस्ता केमिकल मिलाया जा रहा था। दोनों ही स्थानों पर 50 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए कीमत के प्रोडक्ट जब्त हुए हैं। जबकि रॉ मटेरियल सहित पैकिंग आदि का कुल खर्च मुश्किल से 10 से 50 रुपए आता था। आरोपी इस प्रोडक्ट में ब्रांडेड प्रोडक्ट वाली कीमत दर्शाते थे, लेकिन इसे दुकानदारों को 70 से 80 प्रतिशत के डिस्काउंट में देते थे। दुकानदार भी किसानों को डिस्काउंट में देते थे। इस कारण हाथोंहाथ नकली खाद-कीटनाशक बिक जाता था। ग्रीन सिटी में नकली खाद-कीटनाशक की दुकान में की गई कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों के बाद देर रात जिले की आठ खाद-कीटनाशक दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों में कृषि केंद्र सिहोरा, दीपांशु कृषि फार्म ग्राम खुलरी, श्री सांई कृषि केंद्र बुढ़ागर, श्री कृषि सेवा केंद्र पौंडा, ओम कृषि केंद्र मझौली के गोदाम, हरिओम ट्रेडर्स लखनपुर, सत्य सांई कृषि केंद्र चरगंवा और वासुदेव कृषि केंद्र मझौली शामिल हैं।

कपास के किसानों से खुली लूट

एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को हर फसल (अनाज) का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, तो वहीं मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार किसानों की फसलों को खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। लेकिन प्रदेश में ही कपास के किसानों से सरकारी बिक्री केंद्रों पर ही खुली लूट की जा रही है। मप्र में निमाड़ की मंडियों में कपास (रुई) को औने-पौने दामों में खरीदने की साजिश की जा रही है। किसानों का आरोप है कि मंडियों में कपास को औने-पौने दामों में (जो कि एमएसपी से काफी कम हैं) खरीदने के पीछे भारतीय कपास निगम के अधिकारियों और मंडी प्रबंधन की ही मिलीभगत है। उनका कहना है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) किसानों की कपास को खराब बताकर या दूसरी कमी निकालकर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहा है।

बता दें कि कपास की मप्र में इतनी पैदावार है कि उसे **सफेद सोना** कहा जाता है; क्योंकि यह एक नकदी फसल है। हालांकि कपास की खेती से किसानों को उतना लाभ कभी नहीं मिल पाता, जितना कि बिचौलिए और अधिकारी मिलकर लूट ले जाते हैं। लेकिन इन दिनों जैसे ही मंडी में कपास की आवक चरम पर होती है, मंडियों के अंदर किसानों से धोखाधड़ी करके लूट का यह खेल शुरू हो जाता है। जहां तक मप्र में कपास की पैदावार की बात करें, तो गुजरात के बाद मप्र को कपास उत्पादन में गिना जा सकता है। प्रदेश में कपास सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पैदा होती है। यहां कपास की खेती करीब साढ़े सात लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर होती है, जिसकी 75 फीसदी पैदावार अकेले निमाड़ क्षेत्र से होती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा और देवास भी कपास के प्रमुख जिले हैं।

प्रदेश में कपास के किसानों के साथ अब कई संगठन आ गए हैं। राज्य सरकार से किसानों की मांग है कि कपास में कमी निकालकर किसानों से की जा रही लूट बंद करके उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि सरकार ने ही तय किया है, दिया जाए। किसानों के साथ आरएसएस से जुड़े संगठन भी उतर आए हैं। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, वहीं अधिकारी अपनी सफाई पेश करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर मंडी की स्थिति देखें, तो वहां रुई खरीदने में जिस कदर आना-कानी की जा रही है, उसका अंदाजा मंडी में लगे रुई से भरे किसानों के अनगिनत वाहनों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। इन संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वह किसानों से लूट का खेल खेलेगी, तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे।

किसानों का कहना है कि मंडियों में कपास की खरीद आराम तरीके से अधिकारियों की मनमानी से होती है। इससे किसानों को काफी तकलीफ होती है। जिन किसानों के भाड़े के वाहन होते हैं, उन पर भाड़ा बढ़ता जाता है। सीसीआई के नियमों के अनुसार कपास में 12 फीसदी से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई-कई हफ्ते खुले में वाहन खड़े रहते हैं, जिससे रुई पर ओस पड़ने से वह गीली और खराब होने लगती है, जिसे बाद में खराब बता दिया जाता है। इतना ही नहीं उनकी अच्छे रेशे की रुई को मशीनों में जांच के नाम पर ले जाकर खराब रेशे की रुई से बदलने का खेल भी खूब चलता है। इसके अलावा रेशे की लंबाई को मशीन से न मापकर हाथ से मापकर मनमर्जी के दाम किसानों को बता दिए जाते हैं, जिससे किसानों को हजारों-लाखों का नुकसान हो जाता है।

बता दें कि सरकार की तरफ से देशभर में कपास की खरीदी के लिए अधिकृत सीसीआई ही तय करती है कि कपास के भाव क्या होंगे? लेकिन इस भाव को **न्यूनतम समर्थन मूल्य** से कम भी नहीं होना चाहिए। इस बार कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,825 रुपए तय था; लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें कपास की यह कीमत भी नहीं मिल रही, जो कि पहले ही काफी कम है। लेकिन इतने पर भी मंडी में किसानों को 23.5 से 24.5 मिमी के कपास का भाव 5,365 रुपए प्रति क्विंटल और 24.5 से 25.5 मिमी रेशे वाली कपास का भाव 5515 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। यहां खरीदी के बाद कपास को प्राइवेट जिनिंग प्रेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

समय पर नहीं होता भुगतान

कपास को नकदी फसल कहा जाता है। सरकार इसे नकद में खरीदने का दावा करती है। लेकिन मंडियों की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कपास बेचने वाले किसानों का कहना है कि उनकी कपास उधार में ली जाती है और उसका भुगतान 15-20 दिन से लेकर एक-सवा महीने तक में किया जाता है। किसानों का कहना है कि पहले से ही लूट मचा रही सीसीआई के अधिकारी किसानों को काफी टहलाकर, परेशान करके और काफी टालमटोल के बाद कई-कई दिनों में कपास खरीदते हैं और उसके बाद किसानों को भुगतान के लिए चक्कर लगवाते रहते हैं। किसानों ने मांग की है कि अगर सरकार उनका नकद भुगतान करने को सुनिश्चित नहीं करती है, जो कि पहले से ही तय है, तो किसान इसके खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं देरी से भुगतान को लेकर मंडी अधिकारियों का कहना है कि मंडी में आवक बहुत ज्यादा है। एक-एक दिन में भारी मात्रा में कपास खरीदी जाती है, जिसके चलते भुगतान में थोड़ी-बहुत देरी हो गई होगी; लेकिन इसके पीछे किसानों को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। इधर किसानों के समर्थन में उतरे संगठनों का कहना है कि मंडियों में किसानों को हर तरह से लूटा जा रहा है। सरकार का यह खेल बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है।

टूटेगा चुनौतियों का चक्रव्यूह?

बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ...

वर्ष 2020 हताशा-निराशा, टूटन, विरोध प्रदर्शनों का ऐसा गवाह रहा है, जो शायद ही कभी और इस दौर में भी शायद ही कहीं देखने को मिला। कोविड-19 महामारी के बड़े सबक में यह भी रहा है कि दुनिया में जिसने इसकी कम परवाह की, उसे उतना ही झेलना पड़ा। भारत में कोरोना ने सिर्फ मौतें ही नहीं दी हैं, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के साथ सामाजिक व मानसिक विकारों में भी वृद्धि की है। यानी पूरा वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा। अब आशा की जा रही है कि वर्ष 2021 में इन चुनौतियों का चक्रव्यूह टूटेगा।

● राजेंद्र आगाल

वर्ष 2020 बीत रहा है। वर्ष 2021 के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। इस बार वर्ष बीतते-बीतते गिरिधर कविराय की ये पंक्तियां हर मन पर छाई हैं- **बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ। जो बनि आवै सहज में, ताही में चित देई।** वर्ष 2020 का स्वागत करते समय हम इक्कीसवीं शताब्दी के पांचवें हिस्से की समाप्ति के साथ नवोन्मेष की उम्मीदों से भरे हुए थे। तीन माह बीतते-बीतते कोरोना के रूप में 2020 ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव भरी सौगात दी। उसके पश्चात् तो **वर्ष पर्यंत** संकट के नवोन्मेष होते रहे। घरों में कैद होने से लेकर आए दिन मौतों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इन स्थितियों में अब 2021 से चुनौती भरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बीती हुई कड़वी यादों को भुलाकर 2021 में कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद के साथ नए वर्ष की अगवानी की जा रही है। कोरोना वैक्सीन की संभावित खोज पूरी होने से पूरी दुनिया को उम्मीद जगी है कि वर्ष 2021 में 2020 वाली चुनौतियां नहीं रहेंगी।

इतिहास के पन्नों में ऐसे वर्ष ढूंढे शायद ही मिलें, जब किसी एक ही वजह से पूरी या कम से कम दो-तिहाई दुनिया त्राहिमाम कर उठी हो। महामारियों के इतिहास में भी ऐसा वक्त शायद ही उतर आया हो, जब एक ही महामारी ने लगभग सभी महादेशों में कुछेक महीनों के अंतराल में ही ऐसा तांडव मचाया कि न सिर्फ विकास, उन्नति और वैज्ञानिक शोध-परख, बल्कि प्रकृति पर विजय के ऊंचे-ऊंचे दावों की पोल खोल दी हो। वर्ष के शुरू होते ही कोविड-19 के संक्रमण की आंधी में जिंदगियां, रोजगार, अर्थव्यवस्था सबकुछ ध्वस्त होने लगा तो लोगों और सरकारों के होश फाख्ता हो गए। वर्ष खत्म होने तक भी उसका आतंक जारी है लेकिन उतनी ही तेजी से वैक्सीन का ईजाद कर दुनिया ने अपने लिए उम्मीद भी बंधाई है। यह अलग बात है कि कोरोनावायरस ने म्युटेट होकर फिर इम्तिहान की शर्तें कड़ी कर दी हैं। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि इन शर्तों पर भी दुनिया खरी उतरेगी।

सरकार की निष्क्रियता

अलबत्ता, अपने देश में सिर्फ महामारी की तबाही, देश के स्वास्थ्य ढांचे और उस पर काबू पाने के तरीके ने और ज्यादा कहर बरपाया। मार्च के मध्य तक सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि कोई खतरा है। सत्तारूढ़ पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति की अगवानी में नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन और मप्र की कांग्रेस सरकार में टूट करवाने में ही व्यस्त रही। जब पानी सिर से ऊपर उठने लगा तो अचानक बेहद सख्त देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान करके सबकुछ ठप कर दिया गया। नतीजतन, रोजगार के अभाव में शहरों से ऐसा पलायन हुआ, जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। आवागमन के सारे साधन बंद होने से लोग पैदल सैकड़ों, हजारों किमी चलने को मजबूर हुए। उन्हें जगह-जगह पुलिसिया लाठी, बैरीकेड्स, यहां तक कि सड़कों पर खोदे गए गड्ढों का सामना करना पड़ा। यहीं नहीं, पहले ही सात तिमाहियों से ढहती अर्थव्यवस्था ठप हो गई, जिसकी वृद्धि दर 24 अंकों तक शून्य से नीचे चली गई, जो दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई। करोड़ों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा।

विरोध प्रदर्शनों का वर्ष

यही नहीं, यह वर्ष विरोध प्रदर्शनों, केंद्र-राज्य टकराहटों, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र के हस्तक्षेप, संस्थाओं की बदहाली की भी ऐसी मिसाल दे गया है, जो देश की आगे की सियासत की दिशा तय करेगा। वर्ष शुरू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के देशव्यापी विरोध से, जिसकी अनूठी मिसाल दिल्ली के शाहीनबाग का धरना बना, और खत्म हुआ 2020 के तीन नए कृषि कानूनों के किसान विरोध से। किसान महीनेभर से ज्यादा कड़ाके की ठंड में दिल्ली को लगभग चारों दिशाओं से घेरे बैठे हैं। ऐसा नजारा इतिहास में 19वीं सदी के प्रारंभ में शायद बनारस में दर्ज है जब वहां निगम कर के खिलाफ लाखों लोग अंग्रेज रेजिडेंट के दफ्तर-घर को घेरकर बैठ गए थे और अंततः सरकार को निगम कर वापस लेना पड़ा था। तब भी लोगों को वहीं खाना बनाते, गाते-बजाते देखकर अंग्रेज हतप्रभ थे। लेकिन इस बार क्या होता है, यह तो अब अगले वर्ष ही दिखेगा। हालांकि सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का आव्हान किया है। देखना है अवसर कैसा मंजर लेकर आता है।

2020 में कोरोना महामारी के अलावा ऐसी कई घटनाएं हुईं, जो हमेशा याद रहेंगी। फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा दो-तिहाई से अधिक सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। फरवरी के आखिरी हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति के **अनौपचारिक** दौरे के लिए अहमदाबाद में आयोजन किया गया। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के भाजपा में शामिल होने से मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में सीएए विरोधी धरने को लेकर फरवरी के आखिरी हफ्ते में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे में कई जिंदगियां स्वाहा हो गईं। 24 मार्च को रात 8 बजे महज चार घंटे के नोटिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा, महाभारत 18 दिन चला, यह लड़ाई 22 दिन में जीती जाएगी। मुस्लिम संगठन के मजहबी आयोजन को कोरोनावायरस की आमद का दोषी बताया जाता रहा लेकिन बांबे हाइकोर्ट ने उसे बेबुनियाद बताया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद शहरों और औद्योगिक केंद्रों से पैदल सैकड़ों किमी की पैदल यात्रा करने पर मजबूर लोग, यह नजारा इतिहास में कम ढूंढे मिलेगा। कानपुर के

2020 विरोध-प्रदर्शन और विसंगतियों के नाम रहा

यदि किसी साल का सिंहावलोकन करें तो उसका संबंध किसी एक घटनाक्रम तक सीमित नहीं रह सकता, भले ही वह घटना कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न रही हो? इस कड़ी में यदि इसी साल का उदाहरण लें तो यह वर्ष विरोध-प्रदर्शन, तल्खी और विसंगतियों के नाम रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में हुए शाहीन बाग गतिरोध के बाद दिल्ली में दंगे हो गए। इससे पहले कि दंगों की आग बुझती उसके पूर्व ही कोरोना ने दस्तक दे डाली। अब जब हमें लगा कि बदतर दौर बीत गया तो कृषि कानूनों के विरोध की चिंगारी ने नए विवाद की आग भड़का दी है। विपक्षी दलों के साथ ही मीडिया का एक वर्ग भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यही आभास कराना चाहता है कि भारत तानाशाही की ओर उन्मुख है। जबकि मेरा मानना है हम आदतन मत-विरोध वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। असल में हम समस्या से निदान के बजाय संभावित समाधान में ही मीनमेख निकालने लगते हैं। विरोध-प्रदर्शन का अधिकार किसी भी उदारवादी बहुलतावादी व्यवस्था का अपरिहार्य अंग है। हालांकि इस दिशा में हम अभी तक साधन और साध्य की पवित्रता के मर्म को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। आखिर मार्ग अवरुद्ध करना या सार्वजनिक-निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना कैसे शांतिपूर्ण है? स्मरण रहे कि कोई भी लोकतंत्र विमर्श की धारा से ही विकसित होता है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन का गैर-आंदोलनकारी स्वरूप विकसित करना और उनके शांतिपूर्ण प्रतिकार का दायित्व समाज और प्राधिकारी संस्थाओं का ही है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि विरोध-प्रदर्शन को अपने मूल तत्व से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आंदोलन की आत्मा होता है।

डॉन विकास दुबे ने अपने गांव में सात पुलिसवालों को मार गिराया तो पुलिस ने उसके कथित समर्पण के बाद विवादास्पद एनकाउंटर में मार गिराया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को खुदकशी की घटना महीनों टीवी की सुर्खियां और केंद्र-राज्य टकराहट का कारण बनी रही। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को खलनायिका बनाने की तरह-तरह से कोशिशें हुई लेकिन अंततः कुछ नहीं मिला। वहीं उप्र के हाथरस के एक गांव में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना भी सुर्खियों और कई मोड़ से गुजरी। राजस्थान में कुछ हफ्ते चले कांग्रेस के सचिन पायलट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराजगी आखिर दूर हुई, आरोप था कि भाजपा हवा दे रही थी लेकिन पर्याप्त विधायक नहीं जुट पाए। आखिर लंबे अरसे बाद राम मंदिर प्रकरण का पटाक्षेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमिपूजन के साथ हुआ। नवंबर में बिहार के विधानसभा नतीजे भले एनडीए को जीत दिला गए मगर बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। तेजस्वी बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर नए नेता की तरह उभरे, तो भाजपा नीतीश का बड़ा भाई बनकर। भारत में तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चारों कोने पर लगभग महीनेभर से किसान डटे हुए हैं। अमेरिका में आखिर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन के राष्ट्रपति पद पर मुहर लगी पर ट्रंप बगावती मूड में नजर आए।

चुनौतियों की भरमार

नववर्ष 2021 पर चुनौतियों का बड़ा बोझ रहेगा। 2020 में जनता ने जिन चुनौतियों का सामना किया है, 2021 को उन चुनौतियों से भी निपटना होगा। इन सबसे अलग देश के सामने 2021 के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना ही बना हुआ है। अभी कोरोना के पहले संस्करण के स्थायी इलाज के लिए टीका बाजार में आ नहीं पाया है कि कोरोना का दूसरा संस्करण दस्तक दे रहा है। जिस तरह इंग्लैंड के बाद भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित मरीज मिलने लगे हैं, उसके बाद यह चुनौती कम होने के स्थान पर बढ़ती ही नजर आ रही है। भारत में कोरोना ने सिर्फ मौतें ही नहीं दी हैं, बेरोजगारी, आर्थिक संकट के साथ सामाजिक व मानसिक विकारों में भी वृद्धि की है। विद्यार्थी महीनों से अपने स्कूल-कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई-लिखाई की बातें तो हो रही हैं किंतु वह पढ़ाई पूरी तरह प्रभावी हो यह नहीं कहा जा सकता। जिस तरह कोरोना के तीव्र प्रवाह में नौकरियां बही हैं, पहले से ही सुस्त अर्थव्यवस्था में इस संकट ने और पलीता लगाया है। आर्थिक संकट और किसान आंदोलन जैसी सौगातों के साथ 2021 में प्रवेश करते भारत की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संकट का समाधान है।

कोरोना के पहले ही स्ट्रेन में हमने देख लिया था कि हम कोरोना जैसी बीमारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। कोरोना के कारण कोरोना से इतर बीमारियों का इलाज भी जिस तरह थम सा गया था, वह चिंता का विषय है। कोरोना के गंभीर मरीजों को सघन चिकित्सा उपलब्ध कराना दुष्कर हो रहा था और अस्पतालों में कोरोना के इलाज के चलते अन्य बीमारियों के मरीज लाइलाज रह जा रहे थे। इस कारण भी भारी संख्या में मौतें हुईं और कई जगह तो इनका संज्ञान भी नहीं लिया गया। ऐसे में 2021 का स्वागत करते हुए हमें इन चुनौतियों से निपटने और तदानुरूप रणनीति बनाने की जरूरत है। जनता को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से तो काम नहीं चलेगा।

वैक्सीनेशन बड़ी चुनौती

कोरोना महामारी के साये में बीते इस वर्ष को शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में जल्द ही हमें इससे बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि विज्ञानियों की हरी

कोविड-19 के बाद अगली महामारी

इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (आईपीबीईएस) ने एक असाधारण शोध पत्र में चेतावनी दी है कि नोवेल कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) जैसी महामारी हमें बार-बार नुकसान पहुंचाएंगे और अबकी तुलना में ज्यादा लोगों की जिंदगी छीनेंगे। आईपीबीईएस रिपोर्ट को दुनियाभर के 22 विशेषज्ञों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में नई बीमारियों के उभरने के पीछे इंसानों की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अक्टूबर में जारी रिपोर्ट ने कहा, जमीन के उपयोग में बदलाव वैश्विक स्तर पर महामारी के लिए अहम संचालक है और 1960 के बाद से 30 फीसदी से ज्यादा नए रोगों के उभरने की वजह भी है। रिपोर्ट ने आगे कहा, भले ही कोविड-19 की शुरुआत जानवरों पर रहने वाले रोगाणुओं से हुई है, सभी महामारियों की तरह, इसकी शुरुआत भी पूरी तरह से इंसानी गतिविधियों से प्रेरित रही है। हम अभी तक 17 लाख विषाणुओं की ही पहचान कर सके हैं, जो स्तनधारियों और पक्षियों में मौजूद हैं। इनमें से 50 फीसदी विषाणु में इंसानों को संक्रमित करने के गुण या क्षमता मौजूद है। रिपोर्ट को जारी करने वाले इको हेल्थ एलायंस के अध्यक्ष और आईपीबीईएस वर्कशॉप के प्रमुख पीटर दासजैक ने कहा, जो मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को बढ़ाती हैं, वही हमारे पर्यावरण पर अपने प्रभावों के जरिए महामारी के जोखिम भी लाती हैं। जमीन को इस्तेमाल करने के हमारे तरीके में बदलाव, खेती का विस्तार और सघन होना और गैर-टिकाऊ कारोबार, उत्पादन और खपत प्रकृति में तोड़-फोड़ पैदा करते हैं और वन्य जीवों, मवेशियों, रोगाणुओं और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाते हैं। यह महामारियों का पथ है। जूनोसिस या जूनोटिक रोग एक ऐसा ही रोग है जो किसी मवेशियों के स्रोत से सीधे या किसी मध्यस्थ प्रजाति के जरिए इंसानी आबादी तक आया है। जूनोटिक संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या प्रकृति में पाए जाने वाले परजीवियों से हो सकता है, जानवर ऐसे संक्रमणों को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जूनोसिस के उदाहरणों में एचआईवी-एड्स, इबोला, लाइम रोग, मलेरिया, रेबीज, वेस्ट नाइल बुखार और मौजूदा कोविड-19 शामिल हैं। हालांकि, महामारी की आर्थिक कीमत के मुकाबले इसकी रोकथाम के उपाय बहुत कम खर्चीले होंगे। मौजूदा महामारी ने वैश्विक स्तर पर जुलाई 2020 तक लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर का बोझ डाला है।

झंडी मिलते ही टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान कई देशों की वैक्सीन चर्चा में है। लेकिन दुनिया की नजर सस्ती व सुरक्षित वैक्सीन पर है। इसलिए दुनिया की निगाहें भारत पर है। एक साल के भीतर ही कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में शामिल हो गया है।

वैक्सीन तैयार करने वाले संस्थान को प्रधानमंत्री केयर फंड से सीधे सहायता धनराशि उपलब्ध कराई गई। यदि यह काम परंपरागत प्रक्रिया से होता तो रकम जारी होने में ही लंबा समय लग जाता। इसका अर्थ है कि नेतृत्व में यदि दूरदर्शिता हो तो हमारे विज्ञानी भी वह सब कर सकते हैं जो अब तक विकसित देशों में ही हो सकता था। परमाणु अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में हमारी अपनी उपलब्धियां हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा उपभोक्ता बाजार विदेशी कंपनियों के माल से भरा पड़ा है। पर जिस किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य तय किए गए और हमारे विज्ञानियों को चुनौतियां मिलीं, वहां उन्होंने सफलता प्राप्त की है। दरअसल भारत एक सुप्त महाशक्ति है। यदि वह जाग जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। इतिहास इसका गवाह है कि भारत दुनिया के सभ्य व संपन्न देशों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि पुरातनकाल में ही भारत मिट्टी के बरतन बनाने की कला, औजार, आभूषण, मानव-निर्मित वस्तुओं तथा मिश्रित धातु की मूर्तियों के निर्माण का कौशल विकसित कर चुका था। बढ़ती जनसंख्या, अकाल तथा गरीबी के साथ कभी एक संपन्न देश रहा भारत आक्रमणकारी विदेशी शासकों द्वारा दमन तथा दरिद्रता का शिकार बना दिया गया। वर्ष 1857 में आजादी के पहले स्वप्न ने परिवर्तन की प्रक्रिया को उकसा दिया। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन ने राजनीति, जनजीवन, संगीत, कविता, साहित्य तथा विज्ञान में बेहतरीन नेताओं को उभारा। यह आंदोलन मन तथा उद्देश्य की एकता के साथ देशभक्ति और समर्पण द्वारा प्रेरित था।

रोजगार बड़ी जरूरत

कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना दिया है। ऐसे में देश में रोजगार की बड़ी जरूरत है। आज भारत के पास विशाल पैमाने पर कुशल और दक्ष मानव संसाधन है। सरकार द्वारा आरंभ पंचवर्षीय योजनाओं तथा मिशन मोड कार्यक्रमों के कारण मानव संसाधन का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग सोचते हैं कि सबकुछ सरकार ही करेगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया की कोई भी सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है। अपने देश में आजादी है, लेकिन जिम्मेदारी की भावना नहीं है। हर जगह हम मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। चाहे सड़क पर वाहन चलाने की बात हो या कहीं भी कूड़ा-कचरा फेंकने की। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। देश को मुख्यत: आर्थिक शक्ति से सशक्त बनाया जा सकता है। आर्थिक शक्ति प्रतिस्पर्धा से आएगी व प्रतिस्पर्धा ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान को प्रौद्योगिकी से समृद्ध करना होता है और प्रौद्योगिकी को व्यवसाय से शक्ति प्राप्त होती है। व्यवसाय को नवीन प्रबंधन से शक्ति मिलती है और प्रबंधन नेतृत्व से प्रबल होता है। मस्तिष्क की नैतिक श्रेष्ठता नेता की सबसे बड़ी विशेषता है। संयोग से यह क्षमता भी आज देश के नेतृत्व में है। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता युगों से उन महान विचारकों द्वारा समृद्ध की जाती रही है, जिन्होंने हमेशा जीवन को मस्तिष्क, शरीर तथा बुद्धि के मेल के रूप से एक समन्वित रूप में देखा है। आने वाले दशकों में देश के युवा सभ्यतागत तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीय धाराओं का एक संगम देखेंगे।

आज हमारे युवा वैज्ञानिक अनुसंधान, आविष्कार और नवीन प्रयोग में संलग्न होने की बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि ये उच्च प्रौद्योगिकी विकास के बड़े घटक हैं। इन कारकों के बीच एक भिन्नता स्थापित करना उपयोगी है। वैज्ञानिक अनुसंधान भौतिक विश्व की प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। आविष्कार किसी नए उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा का निर्माण या किसी ऐसी चीज का निर्माण है जो अस्तित्व में नहीं है। भारत के युवाओं के पास विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए इस दशक के अंत तक विकसित भारत के लक्ष्य द्वारा देश के लिए योगदान करने का एक अनूठा अवसर है। युवाओं का अदम्य उत्साह, राष्ट्र-निर्माण की क्षमता और रचनात्मक नेतृत्व भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ व विश्व में सही स्थान दिला सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने

अर्थव्यवस्था हुई चकनाचूर

2020 की शुरूआत में कोविड-19 महामारी के फूटने से देश को झटका लगा। लाकडाउन ने भी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया लेकिन भारत इसमें अकेला नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया ही प्रभावित थी। सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए दी गई मदद से अब ये धीरे-धीरे उठ रही है। जीडीपी वृद्धि भविष्यवाणी की तुलना में बहुत कम होने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन, कृषि, पर्यटन, आतिथ्य और अन्य कई क्षेत्र हैं जिन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। प्रमुख क्षेत्रों में से बेरोजगार हो जाना एक बड़ा नुकसान था। यह अनुमान लगाया गया था कि 2017-18 में नौकरी की हानि 45 वर्ष के ऊंचे स्तर पर थी। ये सब नोटबंदी और जीएसटी के रोल आउट के प्रभाव के कारण था। ऊंची जीडीपी वृद्धि के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विकास संकेतकों ने अन्य समस्याओं को भी दिखाया। यहां तक कि जब देश कोरोना वायरस के साथ संघर्ष कर रहा था, सरकार ने 2020 में तीन कृषि कानून पारित किए जिसने मोदी सरकार के लिए एक और सिरदर्द पैदा कर दिया। इसने हजारों किसानों को विरोध करने के लिए उकसाया है। पंजाब में केंद्रित प्रदर्शन अब सारे राज्यों में फैल चुके हैं और हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से किसानों की पैरवी करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन सीमा पर चिंता पैदा कर रहा है और वह हमेशा से ही भारत के लिए एक चुनौती रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ कई घर्षण बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने हैं। घरेलू पक्ष पर एनडीए गठबंधन ने बिहार चुनाव जीता लेकिन दिल्ली केजरीवाल के पास रह गई। कुल मिलाकर वर्ष 2020 मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के लिए चुनौतियों भरा वर्ष था।

उत्पादों को बेचने की आक्रामक प्रवृत्ति का भारतीय उद्यमियों में अभाव है। हमें भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपनी जैव-विविधता को पहचानना चाहिए और उन्हें पेटेंट करना चाहिए।

ज्ञान से संपन्न मस्तिष्क उत्पन्न करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, ताकि वे नए विचार दे सके। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा-प्रणाली ऐसा नहीं करती। उसमें एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि केवल पढ़ने की। पर यह संतोष की बात है कि मोदी सरकार इस दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों, तकनीशियनों तथा कृषकों व अन्य लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और प्रयासों को समन्वित करके विकास लक्ष्यों में मदद देनी चाहिए। हमारे देश के नीति निर्माताओं को विकास के लक्ष्यों को कार्यों में परिणत करने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करना चाहिए।

धार खोता दिशाहीन विपक्ष

सत्तापक्ष की तरह विपक्ष की भी एक प्रकृति होती है। दुख की बात है कि भारतीय राजनीति में पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान विपक्ष की इस प्रकृति में विकृति पनपती दिख रही है जिसमें विरोध नीतियों के बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गया है। इसमें देशहित के खिलाफ मुखरता को भी लोकतंत्र की लड़ाई का नाम देकर सही ठहराया जाने लगा है। यही कारण है कि 2014 से लगातार हाशिये पर खिसकते जा रहे विपक्ष ने अब अपनी पहचान भी खोनी शुरू कर दी है। देखा जाए तो एक सर्वमान्य और सक्षम नेतृत्व का अभाव आज विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बनाने की असफल कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली है। लिहाजा अब खुद पार्टी के ही कई नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि या तो परिवारवाद जिंदा रह सकता है या फिर पार्टी, लेकिन कांग्रेस में अभी भी परिवार का झंडा उठाने वालों की संख्या ही अधिक है।

राहुल गांधी की अनियमितता और अहम मौकों पर छुट्टी पर जाने की उनकी आदत ने विपक्ष के दूसरे दलों को भी असहज करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती के बीच उनका छुट्टी पर जाना राजद को रास नहीं आया था। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी योग्यता पर संदेह जता दिया। एक तरह से कांग्रेस में नेतृत्व का संकट विपक्ष का नेतृत्व संकट भी बन गया है। निकट भविष्य में इस संकट का समाधान भी होता नहीं दिख रहा।

हर 100 साल में होता है महामारी का हमला

दुनिया में हर 100 साल पर महामारी का हमला हुआ है। सन् 1720 में दुनिया में द ग्रेट प्लेग आफ मार्सेल फैला था। जिसमें 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 100 साल बाद सन् 1820 में एशियाई देशों में हैजा फैला। उसमें भी एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह सन् 1918-1920 में दुनिया ने झेला स्पेनिश फ्लू का कहर। इस बीमारी ने उस वक्त करीब 5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और अब फिर 100 साल बाद दुनिया पर आई कोरोना की तबाही। सन् 1720 पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। जहां इस प्लेग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50 हजार लोग मारे गए। बाकी 50 हजार लोग अगले दो सालों में मर गए। सन् 1820 ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले के पूरे 100 साल बाद एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, अरब देशों, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन और मॉरिशस जैसे देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। हैजा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। जबकि सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। सन् करीब 100 साल बाद 1920 में धरती पर फिर तबाही आई। इस बार ये तबाही स्पैनिश फ्लू की शक्ल में आई थी। वैसे ये फ्लू फैला तो 1918 से ही था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में दो से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे।

आगे की चिंता

विश्व बैंक ने साल के पूर्वार्द्ध में ही चेतावनी दे दी कि इस साल पूरी दुनिया की जीडीपी में कम से कम 5.2 प्रतिशत की गिरावट आने का खतरा है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 24.9 फीसदी की गिरावट दर्ज भी हो चुकी थी। ये झटके आने अभी बंद नहीं हुए हैं। मार्च-अप्रैल की तेज गिरावट के बाद से अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों में कुछ-कुछ सुधार के संकेत दिख रहे हैं। थोड़ी खुशखबरी भी आती है, लेकिन फिर बड़ी आशंका दिखने लगती है। अभी अक्टूबर तक हाल सुधर रहा था, लेकिन नवंबर ने फिर हाल बिगाड़ दिया। सीएमआईई के कंज्यूमर सर्वे में दिखता है कि नवंबर में रोजगार के आंकड़े में लगभग 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई और भारत में सिर्फ 4.3 फीसदी लोग ऐसे थे, जिनकी आमदनी **पिछले साल** के इसी महीने के मुकाबले बढ़ी है। इस साल की शुरुआत में सबसे बड़ी चिंता थी, आर्थिक तरक्की की रफ्तार। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सरकार ग्रोथ को वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ कर पाएगी? अब यह सवाल और बड़ा हो चुका है और चिंता भी। ऐसे में, दस साल पहले लौटकर देखना बुरा नहीं रहेगा। ठीक दस साल पहले प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री थे और 2011-12 के बजट में उन्होंने यह उम्मीद जताई थी कि अगले साल देश की जीडीपी 9 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगी। वह साल इसलिए भी याद रखना चाहिए कि उस वक्त भी अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट से बाहर निकली ही थी। यह था 2008 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट। रिजर्व बैंक के कड़े नियमों और गवर्नर वाईवी रेड्डी के अनुशासित रवैये की वजह से भारत इस संकट का सीधा शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी दुनिया का इतना असर जरूर आया कि देश के व्यापारियों को तरह-तरह के सहारे की जरूरत पड़ गई।

महाराजा की घर वापसी

आजादी के तुरंत बाद 1948 में भारत के अग्रणी उद्यमी समूह टाटा ने एक एयरलाइंस की शुरुआत की थी, नाम था एयरइंडिया इंटरनेशनल। हालांकि उसके पहले 1932 में उसने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और जेआरडी टाटा ने इसकी पहली उड़ान खुद भरी और यह सफलता के आकाश में उड़ने लगी। लेकिन पंडित नेहरू की नजर इस पर थी और 1953 में इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, हालांकि जेआरडी टाटा इसके चेयरमैन 1977 तक बने रहे। ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया ने सरकार के हाथों में जाने के बाद तरक्की नहीं की, यह दुनिया के आकाश में छा गई। दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश में इसकी उड़ानें जाने लगीं और इसका विस्तार होता रहा। और एक समय आया कि यह घाटे में चलने लगी। विशालकाय स्टाफ, नौकरशाही और **भ्रष्ट राजनेताओं** ने मिलकर इसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। 2018 आते-आते यह हर दिन 20 से 26 करोड़ रुपए का घाटा देने लगी। 2018-19 में कुल घाटा 8,556 करोड़ रुपए का था और उस पर 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। और तब से सरकार ने इसे बेचने की तमाम कोशिशें शुरू कर दीं।

यूपीए सरकार के एक मंत्री पर तो खुला आरोप है कि उन्होंने अपने आर्थिक हितों के लिए तमाम तरह की हेराफेरी करवाई। इसके लाभ वाले रूट की सीटों को अरब देशों की एयरलाइंस को औने-पौने दामों में दे दिया, कई विमान खरीदने के ऑर्डर दे दिए और अन्य तरह की गड़बड़ियां की। इससे इसका लाभ कम हुआ और घाटा बढ़ा। इसके अलावा एयर इंडिया में राजनीतिक आधार पर हमेशा नियुक्तियां होती रहती थीं, जिससे स्टाफ की संख्या बेशुमार हो गई। आज इस समय इसके पास 125 विमान हैं और 20 हजार से भी ज्यादा कर्मचारी। एक समय इसकी प्रति विमान स्टाफ संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी।

बहरहाल अब इसे खरीदने के इच्छुकों की तादाद कम है और टाटा समूह के अलावा अमेरिका की एक कंपनी तथा एक भारतीय निजी एयरलाइन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कोरोना के कारण देश-विदेश के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि इसे खरीदने में बहुत कम ही पार्टियां इच्छुक हैं। टाटा समूह के पास एयरलाइन का पर्याप्त अनुभव है। दरअसल जब टाटा समूह से एयर इंडिया छिना, तो उसके बाद से समूह ने हमेशा कोशिश की कि वह भारत के आकाश में अपना नाम फिर से लिखे। उदारीकरण के बाद जब बहुत-सी निजी एयरलाइनों ने भारत में अपने कदम रखे, तो टाटा ने भी अपनी एयरलाइंस शुरू करने की इच्छा जताई। लेकिन उस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह कहा कि टाटा को इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह विदेशी धन से निवेश कर रहा है।

टाटा ने भारत में अपनी एयरलाइंस शुरू करने के लिए दुनिया की सबसे बढ़िया एयरलाइनों में से एक सिंगापुर एयरलाइन से हाथ मिलाया था। टाटा समूह के प्रतिद्वंद्वियों ने एक भ्रष्ट राजनेता से मिलकर देशभक्ति की आड़ में उसका प्रस्ताव रद्द करवा दिया। लेकिन टाटा का प्रयास जारी रहा और बाद में समूह ने एयर एशिया और फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा को जन्म दिया। ये दोनों विमान सेवाएं तमाम कठिनाइयों के बावजूद अब भी काम कर रही हैं। लेकिन अब समूह ने बड़े पैमाने पर इसमें कदम रखने का इरादा बनाया है और इसलिए उसने एयर इंडिया में दांव लगाने का फैसला किया है। एयर इंडिया भारत की दो सरकारी एयरलाइनों-इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय से बनी है। घरेलू विमान सेवा इंडियन एयरलाइंस इस विलय के पहले घाटे में नहीं थी और उसका काम ठीक ही चल रहा था, लेकिन विलय के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। विलय के समय यह तर्क दिया गया था कि इससे एक मजबूत एयरलाइंस खड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नई कंपनी का घाटा बढ़ता ही रहा। वह एक मूर्खतापूर्ण कदम था और क्यों उठाया गया, यह जानना मुश्किल है। आलोचकों का मानना है कि इसके पीछे भी निहित स्वार्थी तत्व थे।

एयर इंडिया का घाटा भले ही बड़ा हो, लेकिन इसके पास परिसंपत्तियां काफी हैं, जो नए ऑपरेटर के काम आ सकती हैं। मुंबई के शानदार इलाके नरीमन प्वाइंट में इसका मुख्यालय आज भी बहुत शान से खड़ा है। इसके अलावा भी देश के विभिन्न हिस्सों में इसके अपने दर्जनों ऑफिस हैं, जो इसका बहुत बड़ा आधार हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के हवाई अड्डों पर उसके अपने स्लॉट हैं, जो उसका खर्च कम करते हैं और नए खरीदार को फायदा पहुंचाएंगे। इसके पास अनुभवी पायलट और अन्य कर्मी भी हैं और 100 से भी ज्यादा विमान हैं, जिनमें आधुनिकतम विमान ड्रीम लाइनर भी है। यह सही है कि इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों को रखकर कोई भी एयरलाइंस चल नहीं सकती और इसमें सरकार को वीआरएस के जरिए कटौती करनी ही होगी। फिलहाल कुछ सौ कर्मियों ने इसके लिए आवेदन किया है। अब भी प्रति विमान कर्मियों की संख्या 100 के आसपास है, जो ज्यादा है।

● **राजेश बोरकर**

टाटा समूह के पास अनुभव

सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो जैसे महंगे शहरों में किराए के ऑफिस बंद करना महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे कर्ज कम करके बेचने का विचार किया है, जो खरीदार को काफी सहारा देगा। साथ ही पहले की तरह 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखने का इरादा भी त्याग दिया है। यह एक ऐसी शर्त थी, जो किसी भी खरीदार को पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे सरकारी हस्तक्षेप का खतरा हमेशा बना रहता। अब यह राजनेताओं और अड़ियल नौकरशाहों से दूर रहेगी। अब एयर इंडिया की बिक्री की शर्तें भी आसान हो गई हैं और खरीदार को बोली के मूल्य का कुल 15 प्रतिशत ही देना होगा, इससे खरीदार पर तुरंत बोझ नहीं पड़ेगा। टाटा समूह के पास न केवल एयरलाइंस चलाने का अनुभव है, बल्कि यह पूरी तरह से एक पेशेवर कंपनी है, जो कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखती है। एयर इंडिया आगे भी चले, इसके विमान उड़ते रहें, क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सत्कार की हमारी एक परंपरा भी है और इसके साथ देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। इस बिक्री पर जल्दी से जल्दी मुहर लगना जनता के हित में भी है, जिसके टैक्स के पैसे से यह चलती है।

कांग्रेस के लिए निर्णायक घड़ी

राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने से पहले कांग्रेस को एक सवाल का जवाब जरूर खोजना चाहिए। वह यह कि राहुल कांग्रेस की समस्याओं का समाधान हैं या खुद समस्या हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग इसी सवाल से भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जवाब पता है।

दिल से या बेदिल से राहुल गांधी एक बार फिर से। सोनिया गांधी के साथ पार्टी के असंतुष्टों और संतुष्टों की बैठक का यही नतीजा है। सोनिया गांधी बेटे से इतर देखने को तैयार नहीं हैं और असंतुष्टों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक है उसकी न तो उनके पास ताकत है और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति। उन्होंने अभी तक ठहरे हुए शांत पानी में कंकड़ फेंकने का काम किया है। सोनिया को भी पता है कि वह असंतुष्टों से लड़ने की ताकत खो चुकी हैं। ऐसे में यथास्थिति के अलावा दोनों खेमों के पास कोई रास्ता नहीं है।

उम्मीद का स्तर गिर जाए तो ऐसा ही होता है। सोनिया गांधी इस बात से संतुष्ट हो गई लगती हैं कि बैठक में राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष पद संभालने की बात का विरोध नहीं हुआ। असंतुष्टों को लगा कि पहली बार पूरा परिवार विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में उपस्थित हुआ। यही प्रगति है। इसीलिए सोनिया गांधी के साथ चली करीब 5 घंटे की बैठक में पिछली बार की तरह दोनों खेमों की ओर से आक्रामकता नदारद थी। शायद गांधी परिवार के तीनों सदस्यों खासतौर से राहुल की अप्रत्याशित विनम्रता से अंसतुष्ट खेमा हतप्रभ रह गया हो।

दरअसल दोनों खेमे युद्ध को टाल रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे युद्ध नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि दोनों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी पराजय की मानसिकता से ग्रस्त है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति और संगठन को सोच-विचार में असमर्थ बना देती है। कांग्रेस फिलहाल इसी दौर से गुजर रही है। सवाल है कि कांग्रेस को जरूरत किस चीज की है और उसे मिल क्या रहा है। पार्टी को जरूरत एक ऐसे नेता की है जो उसे पराजय की इस मानसिकता से निकालकर अगले राजनीतिक युद्ध के लिए तैयार कर सके। क्या राहुल गांधी में वह क्षमता है? पिछले 16 वर्षों के दौरान तो राहुल गांधी इस क्षमता के दर्शन नहीं करा पाए हैं। फिर ऐसा क्या बदल गया है कि उन्हें एक बार फिर अध्यक्ष पद सौंपने की तैयारी है। राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बदला है, पर कांग्रेसियों में जरूर बदलाव आया है। उनकी अपेक्षाएं घट गई हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह पार्टी अध्यक्ष पद छोड़कर गए थे उससे लगता था कि वह जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अब उनके परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसी बैठक के विस्तार में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। फिर राहुल गांधी ने डेढ़ साल पहले ऐसा क्यों कहा था? दरअसल उनको और उनके परिवार को उम्मीद थी कि राहुल का ऐसा बयान आते ही कांग्रेस में हाहाकार मच जाएगा। देशभर से 'राहुल लाओ देश बचाओ' की गूंज सुनाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देशभर के कांग्रेसियों को तो छोड़िए सोनिया के साथ हुई बैठक में भी अंबिका सोनी के 'राहुल लाओ' के प्रस्ताव का विरोध भले ही न हुआ हो, मगर उसे समर्थन भी नहीं मिला।

किसी समस्या का हल खोजने के लिए पहली जरूरत है उस समस्या को स्वीकार करना और पहचानना। कांग्रेस ऐसा करने में असमर्थ दिखती है। इतना ही नहीं वह कोई नया राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करने में लगातार नाकाम हो रही है। उसका संगठन हारी हुई सेना के शिविर जैसा दिखता है। वहां तलवार पर सान चढ़ाने वालों से ज्यादा बड़ी संख्या अपने घाव सहलाने वालों की है। यानी कांग्रेस समस्या को पहचान ही नहीं पा रही है। यदि पहचानने का प्रयास करती तो पहले गांधी परिवार से ही दो प्रश्न तो पूछने ही चाहिए थे कि असम में हेमंत बिस्व सरमा और मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर क्यों गए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरा यह कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी छुट्टी मनाने शिमला क्यों चले गए? क्या ऐसी सहूलियत पार्टी के दूसरे नेताओं को भी उपलब्ध है?

चूंकि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं तब आखिर वह किस हैसियत से सभी सांगठनिक फैसले ले रहे हैं। इन फैसलों की जवाबदेही किसकी होगी? सोनिया या राहुल की? पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही पार्टी की उप्र इकाई प्रियंका के हवाले है। बीते दिनों उप्र में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। उनमें से 4 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। प्रियंका से कोई सवाल पूछेगा? बिना जवाबदेही के कोई संगठन आगे बढ़ना तो दूर चलना भी मुश्किल है। यह समझ लीजिए कि प्रियंका से कोई सवाल न पूछकर पार्टी के नीति निर्माता किसी दूसरे नेता से सवाल करने का नैतिक अधिकार खो देते हैं।

कहते हैं कि बिना अमल के परिकल्पना या सपने का कोई अर्थ नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी के पास सपने हैं, परंतु उन्हें साकार करने

मजबूत सलाहकार की भी कमी

कांग्रेस के पास इस समय मजबूत सलाहकार की भी कमी है। अशोक गहलोत जैसा नेता कांग्रेस की जरूरत है। राहुल अध्यक्ष हैं ही नहीं, लेकिन भाजपा के निशाने पर सिर्फ वही हैं। भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी हर मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर रखते हैं। एक-दो नेताओं को छोड़कर कितने कांग्रेस नेता हैं, जो राहुल पर भाजपा नेताओं के हमले के वक्त उन पर मजबूत जवाबी हमला करते हैं? हां, नेतृत्व की आलोचना यदा-कदा करते रहते हैं। राहुल सच में इतने ही कमजोर नेता होते, तो भाजपा दिन-रात उनकी निंदा में भला क्यों अपना वक्त बर्बाद करती? कांग्रेस की तरफ से भाजपा को जवाब नहीं मिलने से राहुल गांधी कांग्रेस की कमजोर कड़ी बन गए हैं। राहुल खुद भी ममता बनर्जी जैसे आक्रामक नेता नहीं हैं, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोरोना का दबाव कम होते ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शायद जनवरी या फरवरी तक। इस पर तैयारी शुरू हो चुकी है।

कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर

2014 और 2019 में आम चुनाव के अलावा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। इसके कारणों की पड़ताल करके तत्काल उनमें सुधार की आवश्यकता है। अन्यथा कांग्रेस इस कदर पतन की ओर चली जाएगी कि उसे दोबारा उबरना मुश्किल हो जाएगा। अपने आधारभूत वोट बैंक का खिसकना और युवाओं का पार्टी पर से विश्वास उठना उसके लिए गंभीर चिंता का विषय है। पिछले दो आम चुनावों में भारत में 18.7 करोड़ वोटर ने पहली बार मतदान किया। 2014 में 10.15 करोड़ और 2019 में 8.55 करोड़ युवा मतदाता जुड़े। युवाओं ने मोदी और भाजपा के लिए भारी मतदान किया। भाजपा का वोट शेयर 2009 में 7.84 करोड़ से बढ़कर 2014 में 17.6 करोड़ और 2019 में 22.9 करोड़ हो गया। इसके विपरीत कांग्रेस ने जहां 2009 में 1.23 करोड़ वोटर गंवाए। हालांकि बाद में स्थिति में मामूली सुधार हुआ। लेकिन 2019 के चुनावी फैसले के करीब सवा साल बाद भी कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में निरंतर गिरावट के कारणों का ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। कई राज्यों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों में कमी देखी गई है। सीडब्ल्यूसी प्रभावी रूप से भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे और जनविरोधी नीति के खिलाफ जनमत जुटाने में सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रही है। अब जो बैठकें भी होती हैं, वो अंतर्कलह में उलझी होती हैं, जिससे राष्ट्रीय एजेंडा और देश के अहम मुद्दे दब जाते हैं।

की कुवत नहीं बची है। कांग्रेस को जरूरत है ऐसे नेता या नेताओं की जो पार्टी के लिए सपना देखें और उसे पूरा करने का उद्यम करें। अपने राजनीतिक विरोधी की ट्विटर या ऐसे अन्य मंचों पर आलोचना कर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझकर कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कोई रेस जीतनी है तो उसके लिए मैदान में उतरना और दौड़ना पड़ता है। किनारे खड़े होकर ताली बजाने से आज तक कोई रेस नहीं जीती। कांग्रेस जिस हालत में है उसमें उसे ऐसा नेता चाहिए जिसमें जोखिम और उसकी जवाबदेही लेने का माद्दा हो।

राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने से पहले कांग्रेस को एक सवाल का जवाब जरूर खोजना चाहिए। वह यह कि राहुल कांग्रेस की समस्याओं का समाधान हैं या खुद समस्या हैं। हालांकि कांग्रेस के लोग इसी सवाल से भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें जवाब पता है। सच्चाई तो यह भी है कि कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर खत्म हो गई है। उसका जो भी वजूद है वह राज्य इकाइयों की वजह से है। उसकी समस्या का हल वहीं से निकलेगा, दस जनपथ या गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से नहीं। पार्टी में दूसरी पीढ़ी के नेता हाशिए पर हैं। जो नहीं हैं, मानकर चलिए कि वे राहुल गांधी के कृपापात्र हैं। कृपापात्र बोझ तो बन सकते हैं, बोझ उठाने वाले नहीं। इन बोझ बने नेताओं से मुक्ति पाने में ही कांग्रेस की मुक्ति का मार्ग है। फिर वह परिवार के सदस्य हों या कोई और। ऐसे में यक्ष प्रश्न यही है कि इस बात को समझे कौन और समझाए कौन।

कांग्रेस के भीतर आजकल बीच की लकीर (धर्मनिरपेक्ष) पर चलने को लेकर इसलिए भी भय रहने लगा है, क्योंकि उसकी अपनी ही पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की जनता के भीतर यह बात पैठ रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है या मुस्लिमों के प्रति उसका रुझान ज्यादा है। जबकि सच यह है कि कांग्रेस के पास मुस्लिमों का समर्थन 30 फीसदी भी नहीं रह गया है। हाल के चुनाव नतीजों से यह साफ जाहिर हो जाता है। नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा के लिए आरएसएस ने हिंदुत्व की जो नई परिभाषा अब गढ़ी है, उसमें उसका नेता अब चाहे मोदी, शाह या योगी में कोई भी रहे, कांग्रेस और बाकी विपक्ष के लिए स्थिति एक-सी ही रहेगी; तब तक, जब तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जनता को यह नहीं समझा देते कि भाजपा की लाइन सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है, उनके हितों की रक्षा और इससे उनकी मूल समस्याएं हल करने के लिए नहीं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल कोशिश करें, तो वो जनता को मुद्दों पर मतदान करने वाली जनता बनाया जा सकता है। बिहार में विधानसभा के हाल के चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत आक्रामक तरीके से जात-पात पर मतदान करने वाले इस राज्य में जोखिम लेकर रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनाकर भाजपा से ज्यादा सीटें जीतकर यह कर दिखाया।

इसे कांग्रेस में फिर घमासान मच गया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 ही सीटें मिलने से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता फिर मुखर हुए हैं। लेकिन यह दौर नेतृत्व की निंदा तक ही सीमित है। सुझाव कहीं से नहीं आ रहा। याद रहे कि दो साल पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर इन और बहुत-से पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को कांग्रेस का एकछत्र नेता कहा था। राहुल कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, जो सोनिया गांधी के विपरीत सोच रखते हैं। जबकि पार्टी में बहुत-से ऐसे नेता हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें सोनिया गांधी जैसा बनना होगा। लेकिन राहुल के नेतृत्व की आलोचना करते हुए कोई भी नेता विकल्प नहीं सुझाता। भूपेश बघेल जैसे नेता हैं, जो उम्मीद जगाते हैं और वह पूरी तरह राहुल के साथ है।

बहुत पहले उप्र के नेता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। वह हार गए थे, लेकिन इससे कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की आवाज जिंदा रही, भले यह संदेश भी गया कि गांधी परिवार ही कांग्रेस में सर्वमान्य नेतृत्व है। आज कौन है, जो चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतर सके? तहलका से बात करते हुए इस सारे विवाद से खुद को अलग रखे हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं, जो पूरी कांग्रेस में गांधी परिवार के नेताओं की तरह सर्वमान्य नेता होने का दावा कर सके। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से बाहर का नेतृत्व लाने के लिए तो शरद पवार जैसे पार्टी से बाहर के किसी नेता को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी परिवार से ज्यादा सर्वमान्य नेतृत्व कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद पार्टी नेता असली समस्या की तरफ नहीं देख रहे और नेतृत्व के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। असली समस्या भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए उससे निपटना है और हालात जब माकूल होंगे, तो यही राहुल गांधी सफल नेता बन जाएंगे।

● **इन्द्र कुमार**

बंगाल में सजा जंग का मैदान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है। भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच पिछले एक साल से चुनावी घमासान देखा जा रहा है। अब धीरे-धीरे कांग्रेस और वामदल भी सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन चुनावी मैदान में फिलहाल ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा ही दिख रही है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि वह पश्चिम बंगाल में इस बार भगवा सरकार बना ले। लेकिन ममता बनर्जी उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हैं। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार किसके हाथ में सत्ता सौंपती है।

मुश्किलें जहां भी होती हैं, उनका असर कभी एकतरफा नहीं होता। किसी के लिए थोड़ा कम तो किसी और के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मुश्किलें जब दो विरोधियों के बीच हथियार के रूप में जगह पा जाती हैं तो दुधारी तलवार का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और फिर नुकसान भी दोनों तरफ होते हैं। बस थोड़ा कम या थोड़े ज्यादा का फर्क रहता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अमित शाह और ममता बनर्जी के सामने ऐसी ही मुश्किलें हैं जो चुनौती बनी हुई हैं। ममता बनर्जी निश्चित तौर पर इस वक्त ज्यादा नुकसान उठा रही हैं, लिहाजा भाजपा फायदे में है, लेकिन चुनाव तक ऐसा ही माहौल होगा। ममता बनर्जी ही घाटे में रहेंगी और भाजपा को फायदा होगा, ऐसी गारंटी भी तो नहीं है।

अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव में भी वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे इसी साल के शुरू में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में। जैसे दिल्ली में अमित शाह और उनके साथी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार किए हुए थे, ममता बनर्जी के खिलाफ भी करीब-करीब वैसा ही माहौल बन चुका है। भाजपा के सामने दिल्ली में जो सबसे बड़ी चुनौती रही, पश्चिम बंगाल में भी वैसी ही है, कौन बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री? अमित शाह को ऐलान करना पड़ा है कि अगर चुनावों में भाजपा की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से ही होगा। अब तक के भाषणों में अमित शाह बंगाल से जुड़े भाजपा नेताओं के नाम तो लेते हैं, लेकिन संदेश यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव में लड़ रही है।

पश्चिम बंगाल के बोलपुर में भाजपा समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और ये देखकर अमित शाह बोल पड़े कि ऐसा रोड शो तो जीवन में नहीं देखा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष रहते भी कई रोड शो किए, लेकिन बंगाल के बोलपुर जैसा सैलाब नहीं देखा। भाजपा नेता अमित शाह ने रोड शो की भीड़ और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे नेताओं को बंगाल में बदलाव की तड़प बताया है। अमित शाह बंगाल के लोक मानस पर ममता बनर्जी के ही औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं- परिवर्तन। परिवर्तन के नाम पर ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट की सत्ता का सफाया कर अपना राज कायम किया और अब उसे काफी बड़ी चुनौती मिलने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और वो अपने उन नेताओं को भी साथ रख पाने में नाकाम साबित हो रही हैं जो कभी उनके लिए एक पैर

पीके के हाथ में टीएमसी की रणनीतिक कमान

ममता बनर्जी के हाव-भाव और भाषणों में काफी दिनों से प्रशांत किशोर का असर देखा जा रहा है। भाजपा पर तो वो हमलावर और आक्रामक रहती ही हैं, लेकिन बाकी सबसे हंसते मुस्कुराते मिलती हैं। ऐसा आम चुनाव के दौरान नहीं था। तब तो आलम ये रहा कि चलते-चलते कहीं जय श्रीराम का नारा सुन लेतीं तो गाड़ी रोककर वहीं बिफर पड़ती थीं। परदे के पीछे रहकर प्रशांत किशोर कदम-कदम पर ममता बनर्जी की राजनीति को तराश रहे हैं और भाजपा के सामने खड़ी चुनौतियों में ये भी एक है। यह किसी से छिपा नहीं है कि बंगाल में चाहे स्थानीय चुनाव ही क्यों न हों, चुनावों के दौरान हिंसा आम बात है। लेकिन जब यह राजनीतिक हिंसा बंगाल की धरती पर होती है, तो उसकी पृष्ठभूमि में मां माटी और मानुष का नारा होता है जो मां, माटी और मानुष इन तीनों शब्दों की व्याख्या को संकुचित करने का मनोविज्ञान लिए होता है। इसी प्रकार जब वहां की मुख्यमंत्री बंगाल की धरती पर खड़े होकर गैर बंगला भाषी को बाहरी कहने का काम करती हैं तो वो भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत के आभामंडल को अस्वीकार करने का असफल प्रयास करती नजर आती हैं।

पर खड़े रहा करते थे, उनकी हर बात को पत्थर की लकीर माना करते थे।

ये तो सबको मालूम है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कोई नई बात है। ममता बनर्जी हमेशा ही ऐसी चुनौतियों से जूझती रही हैं। कई बार तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहता है तो भी ममता बनर्जी अपने सामने चुनौतियां खड़ी कर लेती हैं और इसके पीछे अक्सर तुनकमिजाजी में लिए उनके फैसले होते हैं। तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ममता बनर्जी को मुश्किल में डालने के बावजूद भाजपा के सामने भी चुनौतियों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वो ममता बनर्जी के मुकाबले खड़ा कर सके। ठीक ऐसा ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था।

भाजपा की दिक्कत ये होती है कि स्थानीय नेताओं को भी वो फ्रंट पर निर्भीक होकर लड़ने नहीं देती। दिल्ली चुनाव में भाजपा चाहती तो पार्टी की बैठकों में साफ-साफ बोल देती कि कोई भी पहले से खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानकर न चले, लेकिन ये बात दिल्ली के लोगों को नहीं बताती, तो भी काम चल जाता। मनोज तिवारी चुनावों के दौरान दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ग्लैमर के मामले में मनोज तिवारी में कोई कमी तो है नहीं। रही बात **स्थानीय राजनीति** पर पकड़ की तो भाजपा उनके संसदीय क्षेत्र की सीटें भी गंवा बैठी थी। अमित शाह ने ये समझाने में ही इतनी ऊर्जा खत्म कर दी कि मनोज तिवारी तो भाजपा के सत्ता हासिल करने पर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। जबसे मनोज तिवारी को दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक बने रहे। तभी अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा के साथ बहस करने के लिए चैलेंज कर दिया। लोगों को कन्फ्यूज होना ही था। हो गए और फैसला सुना दिए।

पश्चिम बंगाल में भी वही हाल है। मान लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय तो मप्र से जाकर पश्चिम बंगाल के प्रभार की रस्म निभाते हैं। वैसे भी उनका दिल मप्र में लगा रहता है और दिमाग पश्चिम बंगाल में लगाना पड़ता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और राज्यपाल जगदीप धनखड़ बारी-बारी तो कभी साथ ही साथ ममता बनर्जी को घेरे रहते हैं। ढोल बाजे के साथ भाजपा में आने वाले शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी सबको मालूम है कि वो तो भाजपा के सत्ता में आने पर भी मुख्यमंत्री बनने से रहे, भले ही आगे चलकर वो भाजपा में असम वाले हिमंता बिस्वा सरमा जैसा जौहर ही क्यों न दिखाने लगें, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो संघ का प्रचारक रहा होगा।

कांग्रेस-लेफ्ट गठबंधन किसके खिलाफ?

पश्चिम बंगाल को लेकर तो पहले से ही साफ था कि कांग्रेस का ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता नहीं होने वाला है और ये इसलिए नहीं कि 2019 के आम चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस नेतृत्व ने सूबे में पार्टी की कमान सौंप दी थी। ये अधीर रंजन चौधरी ही थे जो 2011 में भी कांग्रेस के टीएमसी के साथ गठबंधन के कट्टर विरोधी रहे, लेकिन तब केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने उनकी एक न चली। जब सालभर बाद ही ममता बनर्जी ने केंद्र की यूपीए सरकार से कई मसलों को लेकर अपना समर्थन वापस ले लिया तो सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस नेताओं में पहले नंबर पर अधीर रंजन चौधरी ही रहे। अधीर रंजन चौधरी को 2019 के आम चुनाव के बाद कोलकाता से दिल्ली बुलाया गया और लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया और उसकी बड़ी वजह ये रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से लोकसभा चुनाव हार गए थे। साथ ही, अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस को कोई ऐसा नेता चाहिए था कि वो भाजपा के हमलों का काउंटर कर सके। ये तो मानना पड़ेगा कि अपने बयानों से अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस नेतृत्व की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा ही अलग प्रदर्शन किया। इससे पहले हुए 2016 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े किए। 2019 में कांग्रेस को तो दो सीटें मिलीं भी, लेकिन लेफ्ट का तो खाता भी नहीं खुल सका।

असम में भी 2016 के चुनाव के लिए पहले से ही भाजपा ने सर्बानंद सोनवाल को भेज दिया था। तब वो केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको पहले से ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। शायद ये 2015 में दिल्ली और बिहार चुनाव में भाजपा को मिली हार के चलते ऐहतियाती उपाय भी था। हालांकि, उसके बाद उप्र में भाजपा बगैर चेहरे के ही लड़ी और चुनाव जीतने के कई दिनों बाद तक सस्पेंस बने रहने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। भाजपा की जो भी मजबूरी रहती हो, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, भाजपा को मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमेशा ही सफाई देती रहनी पड़ सकती है, और ये पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के लिए बहुत बड़ी बाधा है।

पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं और ये ममता बनर्जी के कोर-वोटर माने जाते हैं। साफ है बाकी बचे 70 फीसदी हिंदुओं में ही भाजपा अपना भविष्य देख रही होगी। अनुपात तो बहुत बड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी का वोटर एकजुट होगा। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी उसमें कुछ खलल डालकर वोट काटने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है ओवैसी की पार्टी कुछ सीटें जीत भी ले और कई सीटों पर बिहार में चिराग पासवान की तरह बंगाल में ममता बनर्जी की जड़ें खोदने में कामयाब भी रहे, लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। ऐसा भी तो नहीं कि सारे हिंदू ममता बनर्जी के खिलाफ ही होंगे और सब के सब एकजुट होकर भाजपा को वोट दे देंगे। याद रहे 2019 की मोदी लहर में भी भाजपा को 18 सीटें ही मिली हैं, जबकि 22 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर उभरती है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

कोयले की जंग

छत्तीसगढ़ सरकार हसदेव अरण्य के जिस जंगल को हाथियों के लिए सुरक्षित रहवास बनाना चाहती है, वहां केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अधिग्रहण भू-अर्जन कानून के तहत नहीं बल्कि कोयला धारक कानून के तहत हो रही है। जिसके तहत कोयला वाले क्षेत्रों में केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी।

छत्तीसगढ़ के सघन वन क्षेत्रों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हित फिर से टकराने लगे हैं। यह नई जंग कोयले को लेकर हो रही है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक की खदान आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आवंटित किया है। इसके लिए कॉर्पोरेशन को 648.601 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इस बीच सरकार ने प्रस्तावित लेमरु हाथी रिजर्व के क्षेत्र में विस्तार का फैसला कर लिया। अगस्त में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मुहर लग गई। इस विस्तार में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक का क्षेत्र भी आता है। इसी दौरान आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने वन विभाग को आवेदन देकर वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति मांगी। 16 सितंबर 2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने अनुशंसा की शर्तों के साथ लिखा, लेमरु हाथी रिजर्व के 3827 वर्ग किमी क्षेत्रफल में 64 कोल ब्लॉक आ रहे हैं। इसमें मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक भी इसी क्षेत्र में शामिल है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय ने वन विभाग के प्रमुख सचिव को इसकी जानकारी दी। वहां से आपत्तियों के बाद कोल ब्लॉक के लिए वन और राजस्व वन भूमि का डायवर्जन खटाई में पड़ता दिखा। अब कोयला मंत्रालय ने राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को दरकिनार कर कोयला धारक अधिनियम के तहत प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन परियोजनाओं के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस क्षेत्र में आकर खनन योजनाओं का विरोध कर चुके हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन परियोजनाओं के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस क्षेत्र में आकर खनन योजनाओं का विरोध कर चुके हैं। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक के लिए जिस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें 502 हेक्टेयर वन भूमि है। इसमें 489 हेक्टेयर में संरक्षित वन है। मोरगा ओर केतमा गांव में स्थित 145 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि भी इसके दायरे में है। अधिग्रहण अधिसूचना के मुताबिक 1.34 एकड़ सरकारी भूमि और 155 एकड़ निजी भूमि का भी अधिग्रहण होना है। यह पूरी जमीन कोरबा की पोड़ी उपरोड़ा तहसील के गांवों में है। अधिसूचना के मुताबिक परियोजना से हितबद्ध व्यक्तियों को केंद्रीय कोयला नियंत्रक के समक्ष आपत्तियां करनी होंगी। इसके लिए अधिकतम समय-सीमा 30 दिन निर्धारित है। इस कानून के तहत हितबद्ध व्यक्ति उसे माना जाएगा जिसे अधिग्रहण से मुआवजा मिलने वाला है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े आलोक शुक्ला अधिग्रहण की इस अधिसूचना को गैर कानूनी बता रहे हैं। शुक्ला कहते हैं कि वहां वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें भी ग्रामसभा की सहमति आवश्यक है। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ही बाइपास कर दिया है। अब कोल बियरर एक्ट से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें वन भूमि को भी शामिल कर लिया गया है। यह गैरकानूनी है। शुक्ला कहते हैं, राज्य सरकार को इसका विरोध करना चाहिए।

हसदेव अरण्य उस बड़े वनाच्छादित गलियारे का हिस्सा है, जो मध्य भारत से गुजरते हुए 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारत के स्थानीय लोगों, आदिवासियों का एक पारंपरिक आवास स्थल है, और सैकड़ों हाथियों का निवास स्थान भी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मध्य भारत में लगभग 27,000 जंगली हाथियों की कुल आबादी का 10 प्रतिशत रहता है। मीतू गुप्ता राज्य के वन्यजीव बोर्ड के सदस्य हैं। वह बताती है कि स्थानीय लोक-कथाएं बताती हैं कि कभी इस क्षेत्र से हाथियों को पूरे उपमहाद्वीप में भेजा जाता था। हाथियों के आसपास मौजूद होने के चलते पारंपरिक घरों को इस तरह से बनाया जाता रहा है कि अन्न भंडारों को हाथी के हमले से सुरक्षित रखा जा सके, इन घरों में एक तरफ का दरवाजा खासतौर पर परिवारों के लिए होता है, ताकि अगर कोई हाथी घर की तरफ रुख करता है, तो इस दरवाजे से सुरक्षित निकला जा सके।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

पूरी स्थिति की समीक्षा कर रही है सरकार

छत्तीसगढ़ के वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, अधिग्रहण की अधिसूचना की जानकारी आई है। उसका पूरा विवरण मंगाया है। उसका अध्ययन कर पूरी समीक्षा की जा रही है। सरकार मामले की पूरी समीक्षा के बाद जरूरी कदम उठाएगी। वन मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से हसदेव अरण्य वन में ऐसे तीस कोयला ब्लॉक की पहचान की गई है, और इसमें किसी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक, द अडानी ग्रुप उन ब्लॉकों के दोहन में रुचि रखता है। इन जंगलों के नीचे पांच अरब टन कोयला पड़ा है। अडानी के लिए खनन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। इसकी वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ के सात कोयला खदानों और दो लौह-अयस्क खानों की सूची है, जिनमें अडानी 'माइन डेवलपर और ऑपरेटर' है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी कोयला खदान करने वाला समूह बन गया है। हसदेव अरण्य के इस हिस्से में एक कोयला ब्लॉक में कार्य चल रहा है और इसका खनन अडानी द्वारा किया जा रहा है, जहां यह पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान की सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी का एमडीओ है। इस खदान के लिए 1,00,000 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया था और कुछ हिस्सों को अभी भी साफ किया जा रहा है। इस खदान से सटे दो ब्लॉक भी इसी कंपनी को पट्टे पर दिए गए हैं, और अडानी ने इन दोनों के ठेके भी हासिल कर लिए हैं। हालांकि, स्थानीय समुदायों द्वारा चलाया जा रहा प्रतिरोध का एक उग्र आंदोलन इनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो गया है। एचएबीएसएस द्वारा कार्रवाई को लेकर समितियां बनाई गई हैं और आसपास के शहरों में विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं।

सैंडविच बनती कांग्रेस

एक लोक कहावत है कि सौ-सौ चट्ठे खाव, तमाशा घुसकर देखो। महाराष्ट्र में यही दशा कांग्रेस की हो रही है। उसे साझे की सत्ता में रहना है। इसलिए उसे महाविकास आघाड़ी के अपने दोनों सहयोगियों शिवसेना एवं राकांपा की धौंस और घुड़कियां सहते रहना है। सत्ता की चाह में वह अपने ही दोनों सहयोगी दलों के बीच सैंडविच बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 105 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद विपक्ष में बैठने को मजबूर भाजपा के नेता अक्सर कहते रहते हैं कि महाराष्ट्र की शिवसेनानीत सरकार को वे नहीं गिराएंगे। बल्कि यह सरकार अपने अंतर्विरोधों से कुछ दिनों में स्वयं गिर जाएगी। हालांकि सरकार में शामिल तीनों दल भाजपा के इस दावे को निराधार बताते हुए अपनी एकजुटता का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन अंतर्विरोध दबा भी नहीं पाते। हाल की दो घटनाएं इसका प्रत्यक्ष सबूत हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर महाविकास आघाड़ी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ठीक से लागू करने का ध्यान दिलाया। इस पत्र पर शिवसेना और कांग्रेस एक तरफ सफाई देती, तो राकांपा कुढ़ती नजर आई।

तब शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर बात रफा-दफा करने की कोशिश की कि सोनिया गांधी संप्रग की अध्यक्ष हैं, और महाराष्ट्र की त्रिदलीय सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इस पत्र में दबाव की राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। राउत ने यह कहकर सफाई तो दे दी, लेकिन कांग्रेस को इसका जवाब दिया जाना भी जरूरी था। यह जवाब ही शिवसेना मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह लिखकर दिया गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को नए नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस इसका कुशलता से नेतृत्व नहीं कर पा रही है।

यह पहला अवसर नहीं है, जब शिवसेना ने कांग्रेस के विरुद्ध आवाज उठाने की पहल की हो। सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद सामना में ही कांग्रेस को पुरानी खाट बताते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। दरअसल शिवसेना की कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। महाराष्ट्र में उसका मुख्यमंत्री रहे और मुंबई सहित कुछ बड़ी महानगरपालिकाओं में सत्ता कायम रहे, उसकी इच्छाएं बस यहीं तक सीमित हैं। राकांपा भी क्षेत्रीय दल है। लेकिन उसके नेता शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति का स्वाद चख चुके हैं। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तीन दशक से हिलोरें मार रही है। उनका दल संप्रग का सदस्य भी है। देश के अन्य राज्यों में सक्रिय कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं से उनकी अच्छी मित्रता भी है। इसका लाभ उठाकर वह संप्रग का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अब चूंकि महाराष्ट्र का ही एक और दल शिवसेना उनके साथ है। इसलिए उसके मुख से यह मांग उठवाई गई है। वर्ष 1985 में शिवसेना ने भाजपा के साथ भी उसने ऐसा ही समझौता किया था कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा आगे बढ़ेगी, और राज्य की राजनीति में शिवसेना। चूंकि भाजपा राष्ट्रीय दल है, इसलिए वह महाराष्ट्र को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती थी। उसने महाराष्ट्र में भी अपना जनाधार बढ़ाया।

विधानसभा चुनाव में उसकी जीत का प्रतिशत हमेशा शिवसेना से ज्यादा रहा। राष्ट्रीय राजनीति में उसे शिवसेना की ज्यादा जरूरत नहीं रही और 2014 के विधानसभा चुनाव में वह शिवसेना से अलग लड़कर भी उससे लगभग दोगुनी सीटें जीतने में सफल रही। इसके विपरीत राकांपा अभी शिवसेना से कमजोर स्थिति में है। महाराष्ट्र में उसके जनाधार का अपना निर्धारित दायरा है और राष्ट्रीय राजनीति में उसे शिवसेना की जरूरत है। आज शिवसेना ने शरद पवार को संप्रग अध्यक्ष बनाने के लिए मुंह खोला है, तो कल अन्य राज्यों के भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल भी मुंह खोल सकते हैं। दबाव बढ़ने पर कांग्रेस को संप्रग का अध्यक्ष पद छोड़ना भी पड़ सकता है। इससे भाजपा का नुकसान हो न हो, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका से कांग्रेस जरूर किनारे लग जाएगी।

यहां तक कि शिवसेना-राकांपा के नजदीक आने का नुकसान महाराष्ट्र की अंदरूनी राजनीति में भी कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह ही भिवंडी महानगरपालिका में कांग्रेस के 16 सभासद राकांपा में शामिल हो गए। राकांपा और शिवसेना पंचायत चुनावों तथा महानगरपालिका चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस में नेतृत्वविहीनता की स्थिति सर्वविदित है। किसी भी स्तर के चुनाव में सीटों के समझौते की बातचीत करते समय सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही दबना पड़े तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार महाराष्ट्र और राष्ट्र, दोनों स्तरों पर प्रत्यक्ष नुकसान का आभास होते हुए भी कांग्रेस शिवसेना एवं राकांपा के साथ बने रहने को मजबूर है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहना, उसके लिए भागते भूत की लंगोटी जैसा ही है।

● **बिन्दु माथुर**

प्रासंगिकता पर सवाल

शिवसेना ने सामना में देश के दोनों राजनीतिक गठबंधनों की भी तुलना करते हुए अपनी राय दी है- एनडीए में भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में है। एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और अमित शाह जैसा राजनीतिक प्रबंधक है, लेकिन यूपीए में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। अव्वल तो शिवसेना ने कांग्रेस नेतृत्व या यूपीए को लेकर कोई नई बात नहीं कही है। जो भी कहा है वे वही बातें हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चल रही होंगी। हो सकता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मन में भी कहीं न कहीं ये बातें हों। हमेशा न सही, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद तो ये सवाल सामने उभरता ही होगा। शिवसेना से पहले ये सारे सवाल कांग्रेस के भीतर ही उठे हैं। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जी-23 से जुड़े कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के मन में भी ये ही सवाल हैं और जो चिट्ठियां सोनिया गांधी को लिखी गई हैं उनमें भी कोई अलग चीज नहीं है। ऐसी ही बातों को लेकर कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में 5 घंटे तक मीटिंग भी कर चुकी हैं। हालांकि, मीटिंग से कोई नतीजा निकला हो ऐसा नहीं लगता। कम से कम गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के बाद जो कुछ कहा उससे तो ऐसा ही लगता है।

50 फीसदी से ज्यादा वादे पूरे

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बात करें अशोक गहलोत के पिछले 2 कार्यकालों की तो इस बार के तीसरे कार्यकाल में शुरुआती 2 सालों में गहलोत सरकार को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 10 महीने से कोरोना महामारी, 34 दिन की सियासी बाड़ाबंदी और लगभग 8 महीने की चुनाव आचार संहिता के साथ प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद गहलोत सरकार का दावा है कि इन 2 वर्षों में हमने चुनावी घोषणा पत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं।

किसान और रोजगार के वादों के जरिए सत्ता में आई कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 501 बिंदु थे। इनमें से गहलोत सरकार ने 252 से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने रिफाइनरी और मेट्रो प्रोजेक्ट को फिर से नई गति दी है तो वहीं कोविड की चुनौती को निरोगी राजस्थान जैसी अभिनव योजना के जरिए अवसर में भी बदला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि केंद्र से मदद नहीं मिलने के बावजूद राजस्थान के विकास की रफ्तार अपनी जगह बदस्तूर रही है। वहीं, इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने में राजस्थान देश-दुनिया के लिए एक नजीर बना है।

गहलोत सरकार के दूसरे साल में जिस तरह से कोरोना की चुनौती के बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार बरकरार है निश्चित तौर पर जनता ने निकाय चुनाव में उसी पर ही मोहर लगाई है। अगर सरकार के 2 साल के कामकाज को देखें तो कई उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। एक तरफ गहलोत सरकार ने कोरोना में कुशल प्रबंधन के जरिए देश के समक्ष एक नजीर पेश की तो वहीं बीते साल में सरकार को सियासी संकट का भी सामना करना पड़ा।

सरकार के दो सालों का कार्यकाल ग्राम पंचायतों, नगर निगम, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता और कोरोना संकट के कारण प्रभावित रहा। इसके बावजूद गहलोत सरकार दो साल में अपने जनघोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे पूरे कर चुकी है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार बनते ही उसे सरकारी दस्तावेज बनाकर उसे जनघोषणा पत्र का नाम दिया।

दरअसल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 24 दिसंबर को हुआ था। इसी दिन गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खासतौर पर किसानों की कर्जमाफी का बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना हो, नई नौकरियों का रास्ता खोलना हो, प्रदेश में मेट्रो रिफाइनरी जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना हो या फिर निरोगी राजस्थान जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना को अमलीजामा पहनाना हो सरकार ने इन 2 सालों में ऐसे न जाने कितने अहम फैसले लिए हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ पहुंचा है।

केंद्र से मिलने वाली मदद में आई कमी और नागरिकों के जीवन बचाने को लेकर जुटाए गए संसाधनों की वजह से कई सारी योजनाओं को सरकार चाहकर भी अमलीजामा नहीं पहना सकी है। कोरोना के अलावा सरकार के समक्ष इस साल सियासी संकट भी एक बड़ी चुनौती रहा। कोरोनाकाल के बीच ही सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने को लेकर मंत्री-विधायकों को 34 दिन बाड़ाबंदी में रहना पड़ा। पहले जयपुर और उसके बाद जैसलमेर में विधायकों और मंत्रियों की बाड़ाबंदी हुई, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से 50 फीसदी से अधिक घोषणाओं को लागू करने का साहस दिखाया है और आने वाले समय का रोडमैप भी तैयार किया है। इतनी सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सियासी चुनौतियों के बीच चुनावी घोषणा पत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा वादे पूरे करते हुए 2 साल का सफलतम कार्यकाल पूरा करने के लिए गहलोत सरकार बधाई की पात्र है। जनता ने निकाय चुनाव में सरकार पर भरोसा व्यक्त किया है ऐसे में सरकार चाहेगी कि 2 साल के अवसर पर कई नई सौगातें जनता को दी जाएं ताकि अगले साल आने वाले उपचुनाव की चुनौती के लिए पूरी तैयारी से मैदान में उतरा जा सके।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

ये रहीं सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का ऋण माफ किया। 20.50 लाख किसानों के 7692 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए। 28016 सीमांत एवं लघु किसानों के 290 करोड़ रुपए के मध्यकालीन व दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किए। वृद्ध किसानों को पेंशन उपलब्ध कराई गई। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आसान दर पर गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराई। राज्य की सभी 144 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ा गया। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन। राजीव गांधी सेवा केंद्रों को लाइब्रेरी से जोड़ा। पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया। प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाने की दिशा में काम। बंद किए गए 20,000 स्कूलों की समीक्षा कर नए सिरे से खोले गए। राज्य की सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास बनाए गए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय, सांस, गुर्दा रोग की दवाइयों को शामिल कर निःशुल्क दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर 709 की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 28 लाख बीपीएल के 1.17 करोड़ स्टेट बीपीएल के 29 लाख यानी कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को एक मार्च 2019 से 1 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण। 1114 किलोमीटर लंबाई से 330 गांवों को सड़कों से जोड़ा। राज्य की नई राजस्थान पर्यटन नीति बनीं, 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में 24×7 महिला हेल्पलाइन।

हेट पॉलिटिक्स का अड्डा

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने उप्र को नफरत की राजनीति का केंद्र बताया है। पत्र में कहा गया है कि धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। पूर्व नौकरशाहों ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीकेए नैयर समेत 104 रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। सभी ने 'उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून-2020' को वापस लेने की मांग की है। नौकरशाहों का कहना है कि इस कानून ने उप्र को नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है।

पत्र में लिखा गया है कि उप्र एक समय में गंगा-जमुना तहजीब को सींचने वाला था, लेकिन अब इस कानून के आने से नफरत, विभाजन कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन चुका है। इन रिटायर्ड अफसरशाहों ने इस अध्यादेश को पूरी तरह गैर-कानूनी बताया है। पत्र में पूर्व अफसरों ने लिखा है कि कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। लव जिहाद का नाम राइट विंग विचारधारा रखने वालों ने दिया है। इसमें कथित तौर पर मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को बहलाकर शादी करते हैं और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। ये केवल मनगढ़ंत कहानी है। यह एक तरफ का जघन्य अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ आपके प्रशासन ने किया है।

पूर्व अफसरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है। जिसमें कहा गया है कि अगर लड़का और लड़की नाबालिग है और खुद की मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से भी कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने पिछले महीने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें किसी के व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। बता दें अध्यादेश में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धर्म बदलने के कम से कम दो महीने पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। इसमें यह व्यवस्था भी है कि विवाह करने के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन गैर-कानूनी माना जाएगा। इसके तहत दंड का भी प्रावधान है।

पत्र में कहा गया है कि उप्र, जिसे कभी गंगा-जमुनी तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है, और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। उप्र में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है। जो भारतीय बस एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं।

पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है जिसमें इस महीने के शुरू में उप्र के मुरादाबाद में हुए मामले का जिक्र किया गया था। जिसमें अल्पसंख्यकों को कथित रूप से बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में लिखा गया है, यह अक्षम्य है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपत्ति से पूछताछ करती रही। जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया था।

पिछले हफ्ते उप्र के बिजनौर में दो किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहां लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया। एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की को जबरन शादी करने की कोशिश करने के आरोप में एक हफ्ते से अधिक समय से जेल में रखा गया था। हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था।

साथ ही पत्र में लिखा गया है कि ये अत्याचार, कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना, जारी हैं। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही बात कही थी एक अंतरजातीय दंपति को फिर से मिलाने के लिए। कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवनसाथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उप्र राज्य को है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कानून से बढ़ी कट्टरता

पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि यह कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश है। इसके तहत कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं से शादी कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, लेकिन यह केवल मनगढ़ंत बातें हैं। यह एक तरह का अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ किया जा रहा है। पत्र में पूर्व अफसरों ने कहा है कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट के पिछले महीने एक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। गौरतलब है कि अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म बदलने से 2 महीने पहले प्रशासन को लिखित रूप में जानकारी देनी होगी। कानून में यह भी कहा गया है कि केवल विवाह करने के मकसद से अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो यह गैर-कानूनी माना जाएगा और इसके तहत सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत अब तक 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ था।

अपराधी बेखौफ

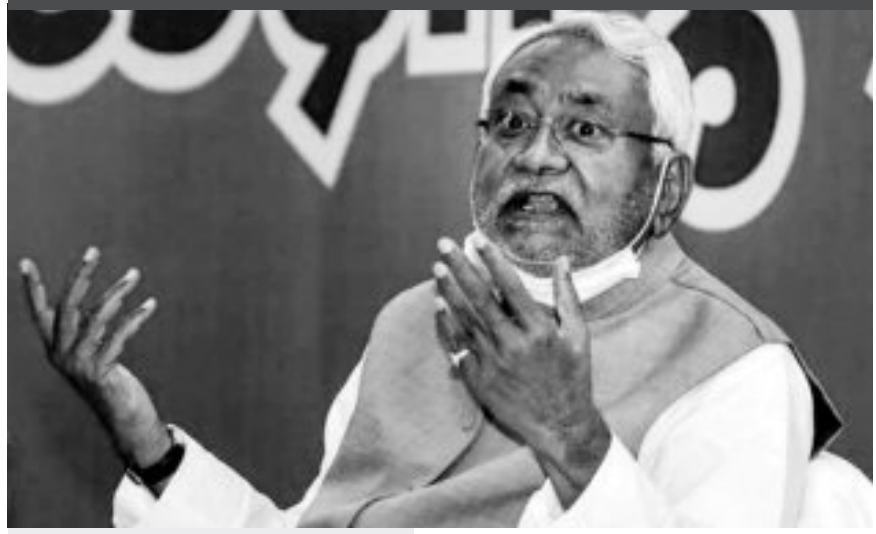

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले तीन कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की खातिर काफी ख्याति अर्जित की थी, लेकिन अपने नए कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्हें कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता की बागडोर संभालने के तुरंत बाद राज्य में हत्या, अपहरण, लूट और डकैती सहित अन्य अपराध की घटनाओं में अचानक उछाल से सरकार सकते में है और मुख्यमंत्री ने 'डैमेज कंट्रोल के लिए खुद ही कमान संभाल ली है। विधानसभा चुनाव जीतने के एक महीने के भीतर राज्य की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री को कानून-व्यवस्था पर लगातार तीन बैठकें करनी पड़ी हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे हालात फौरन नियंत्रण में लाएं या कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें।

दरअसल, मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद से ही राज्य में कई ताबड़तोड़ घटनाएं हुई हैं, जो चिंता का कारण बनीं। पिछले दिनों हथियारबंद अपराधियों ने एक विद्यालय की शिक्षिका की पटना में सरेआम हत्या कर दी। डेहरी-ऑन-सोन में रहने वाली वह महिला राजधानी में अपने पति के साथ शादी की पहली सालगिरह मनाने आई थी। बदमाशों ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर आंख में गोली मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में, चावल मिल मालिक दो व्यवसायी भाई, राकेश कुमार गुप्ता और अमित कुमार गुप्ता अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनके परिवार ने अनहोनी की आशंका जताई, लेकिन दस दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पटना पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई। परिजनों को फिरौती के लिए अपहरण की आशंका है।

पटना से दूर, उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में, स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर स्थित एक आभूषण की दुकान से दिनदहाड़े 7 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए गए। इस दौरान अपराधियों ने 20 राउंड गोलियां भी चलाईं। इधर, खगड़िया जिले में अलग-अलग घटनाओं में एक सत्ताधारी जद-यू और एक राजद कार्यकर्ता की हत्या ने राज्य पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा दीं। छपरा में एक पूर्व विधायक के पुत्र की भी हत्या हो गई। राज्य भर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसने न केवल विपक्ष बल्कि सत्तारूढ़ जद(यू)-भाजपा गठबंधन के कुछ नेताओं को भी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाने का मौका दे दिया। बिहार भाजपा के अध्यक्ष और सांसद डॉ. संजय जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ सांसद छेदी पासवान और दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। रोहतास में एक पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे की हत्या के बाद पासवान ने वहां के पुलिस अधीक्षक को अक्षम बताकर उन पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने बढ़ाई सतर्कता

सत्तारूढ़ दल का दावा है कि 2005 में राज्य में सत्ता में आने के बाद नीतीश ने बिहार में कानून-व्यवस्था बहाल करने में सफलता पाई है और इस कार्यकाल के दौरान भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जहां तक कानून-व्यवस्था का प्रश्न है, वे अपनी पूर्व की उपलब्धियों पर निश्चिंत नहीं रह सकते। हालांकि नीतीश, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं और अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने कई कड़े दिशा-निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने नामजद अपराधियों पर फौरन कार्रवाई करने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राज्य भर में रात में गश्त तेज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अपने क्षेत्र में किसी भी चूक के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को भी कहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने आईजी, डीआईजी और जिला एसपी को नियमित रूप से रात्रि गश्त लगाने के लिए भी कहा है। इन उपायों से जल्द ही कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में आएगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश के अपने पास गृह विभाग रखने के कारण चुनौतियां वाकई बड़ी हैं। पूर्व में भी गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहा है, लेकिन राज्य के सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि इस बार इसे भाजपा अपने खाते में चाहती थी।

नीतीश को कानून-व्यवस्था पर सहयोगी दलों के नेता ही घेरने लगे, तो विपक्ष भी हमलावर हो उठा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि जद(यू) और भाजपा के नेताओं ने तथाकथित जंगलराज के नाम पर लोगों को डराने की हमेशा कोशिश की है, लेकिन वे अब कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हे भगवान, बिहार में बहुत ज्यादा ही सुशासन है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी आरोप लगाया कि बिहार में आजकल अपराधियों का आत्मविश्वास चरम पर है, जबकि मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास बिलकुल नीचे। वे पूछती हैं, जंगलराज चिल्लाने वाले कहां हैं?

राजद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता महज नीतीश पर दबाव बनाने के लिए कानून-व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, मुख्यमंत्री जो गृह विभाग संभाल रहे हैं, उस पर भाजपा की नजर थी, लेकिन नीतीश ने मना कर दिया। हालांकि जवाब में जद-यू प्रवक्ता तथा पूर्व सूचना-प्रसारण मंत्री नीरज कुमार का कहना है कि तेजस्वी ने भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी करार दिए गए अपने पिता (लालू प्रसाद यादव) से राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे कहते हैं, तेजस्वी अबोध हैं, इसलिए जंगलराज और मंगलराज का अंतर नहीं समझ पाएंगे। नीरज जिक्र करते हैं कि 17 जुलाई 1997 को पटना हाइकोर्ट ने तत्कालीन राजद शासन के लिए 'जंगलराज' शब्द का इस्तेमाल किया था और उसी साल 5 अगस्त को यह भी कहा कि जंगलराज में भी कुछ नियम-कायदे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में वह भी नहीं है।

● **विनोद बक्सरी**

लोकतांत्रिक प्रणाली से हताश

भारत के साथ सदियों पुराने ऐतिहासिक पारस्परिक सहयोग और रोटी-बेटी का संबंध रखने वाले नेपाल में हाल के दिनों में एक और आंदोलन जोर पकड़ रहा है। नेपाल का इस बार का आंदोलन दुनिया भर के देशों को चौंका रहा है। नेपाल के सत्ता प्रतिष्ठान में जारी ड्रामे से त्रस्त नेपाली जनता अब सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र को खत्म करके दुनिया की आखिरी हिंदू राजशाही को वापस लाने की मांग कर रही है और यह सारा बदलाव महज 12 साल में ही हो गया है। दरअसल, नेपाल दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। हालांकि नेपाल की वर्तमान सीमा का निर्धारण उनके और ब्रिटेन के बीच 1814 से 1816 तक चली लड़ाई के बाद हुई संधि से ही हुआ है। वहां हमेशा से राजा का शासन था लेकिन उस दौर में वहां राणाओं ने नेपाल को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग रखा।

भारत की आजादी के साथ नेपाल में भी लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। नेपाली कांग्रेस पार्टी के देशभर में चलाए गए आंदोलन और भारत की मदद से 1951 में वहां राणाओं की सत्ता समाप्त हुई और वास्तविक सत्ता राजाओं के हाथ में आ गई और इसके बाद लोकतंत्र के लिए आंदोलन लगातार जोर पकड़ता गया। 1959 में नेपाल ने अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया। संसदीय चुनाव हुए जिसमें नेपाली कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया लेकिन इसके अगले ही साल राजा महेंद्र ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अकुशलता का आरोप लगाकर संसद को भंग कर दिया। इसके बाद 1962 में नेपाल के राजा ने बुनियादी लोकतंत्र के नाम पर किसी भी पार्टी के सहयोग के बिना ही राष्ट्र पंचायत का गठन किया। यहां तक कि मंत्रिमंडल का गठन भी राजा ने स्वयं ही किया। राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद 1972 में राजा बीरेंद्र ने नेपाल की राजगद्दी संभाली। इसके कुछ सालों बाद 1980 में संवैधानिक सुधार की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। नेपाल के राजा ने कुछ बातें तो मानीं लेकिन उनकी अजीब-सी शर्तों के कारण नेपाली कांग्रेस ने 1985 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नेपाली कांग्रेस ने 1986 के चुनावों का बहिष्कार भी किया। आंदोलन जोर पकड़ता गया। 1990 तक सड़कों पर प्रदर्शनों, सभाओं, हड़तालों के दबाव में आखिरकार राजा बीरेंद्र ने पंचायत पद्धति खत्म कर राजनीतिक पार्टियों को वैधता देने वाले नए संविधान पर अपनी मंजूरी दे दी। नए संविधान के तहत 1991 में नेपाल में चुनाव हुए। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। तीन साल बाद 1994 में कोइराला सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। दोबारा चुनाव करवाए गए और नेपाल में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ लेकिन अगले ही साल इस सरकार को भंग कर दिया गया। उसी समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजशाही के खात्मे के लिए देशभर खासकर नेपाल के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह शुरू कर दिया। एक तरफ देश में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी तो दूसरी तरफ नेपाल के राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद को लेकर म्यूजिकल चेयर का खेल खेलने में व्यस्त थे।

1999 में हुए चुनाव में नेपाली कांग्रेस फिर से सत्ता में आई और कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगले ही साल पार्टी में विद्रोह के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा और गिरिजा प्रसाद कोइराला चौथी बार प्रधानमंत्री बने। उठापटक के इसी दौर में नेपाल के राजपरिवार को भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ा। जून 2001 में राजकुमार दीपेंद्र ने राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत राजपरिवार के कई सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। राजा बीरेंद्र की हत्या के बाद उनके भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र राजा बने। ज्ञानेंद्र स्वभाव से ही लोकतंत्र विरोधी थे इसलिए उनके राज में माओवादी विद्रोह की घटनाएं जोर पकड़ने लगीं। माओवादियों ने नेपाल के कई हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले कोईराला और बाद में देउबा ने माओवादियों के साथ समझौता करने की कोशिश की लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। परेशान राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल में आपातकाल लगा दिया। एक तरफ माओवादियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ राजा ज्ञानेंद्र लगातार नए प्रधानमंत्री बनाने और उन्हें हटाने के खेल में लगे थे। इस दौर में एक के बाद एक देउबा, लोकेंद्र बहादुर चंद्र, सूर्य बहादुर थापा, उसके बाद फिर से शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनाए गए।

फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने देउबा को बर्खास्त कर सारी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। लेकिन इसके महज तीन साल बाद 2008 में उनके हाथ से सब कुछ चला गया। मई 2008 में 240 वर्षों से चली आ रही हिंदू राजशाही को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से बाहर कर दिया गया। नेपाल में नई सरकार सत्ता में आई। नेपाल को हिंदू राष्ट्र की बजाय धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। 2008 में जिस नेपाल में वास्तविक लोकतंत्र आया था, अब 2020 में उसी नेपाल में फिर से लोकतंत्र को खत्म कर राजा को वापस लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भारत का अहम योगदान

नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भारत का अहम योगदान रहा है। नेपाल का शायद ही कोई ऐसा इलाका या फील्ड बचा होगा, जहां भारतीय मदद नहीं जा रही हो लेकिन इसके बावजूद नेपाली सत्ता में बैठे लोगों ने भारत विरोध की अंधी पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है। चीन के डर या मोह में वहां की सरकारों, खासकर वर्तमान प्रधानमंत्री ओली ने भारत विरोध के नाम पर नेपाल की संप्रभुता को चीन के आगे गिरवी रख दिया है। इन हालातों में नेपाल की देशभक्त जनता को यह लगने लगा है कि लोकतंत्र के नाम पर राज करने वाले इन नेताओं को अगर जल्द से जल्द सत्ता से बाहर नहीं किया गया तो नेपाल का भौगोलिक नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। डर इस बात का भी है कि जो नेपाल अपने राजनीतिक इतिहास में कभी किसी का गुलाम नहीं बना वो कहीं चीन का एक उपनिवेश मात्र बनकर न रह जाए इसलिए वहां की जनता सड़कों पर उतर रही है। इसलिए नेपाली लोग राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे हैं।

चीन की किरकिरी

बीते कुछ दशकों में किसी एक साल ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को शायद ही इतना प्रभावित किया हो जितना 2020 ने। इस साल की शुरुआत ही चीन के वुहान से निकले उस कोरोना वायरस से हुई जिसने जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया। इसका प्रकोप इतना बढ़ गया कि कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी को वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। चूंकि इसका कोई कारगर उपचार नहीं था तो उसके संक्रमण की मार से बचने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने ऐसा ही किया। इसकी वजह से सब कुछ थम गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। परिणामस्वरूप सेहत पर मंडराए इस संकट ने सामान्य जनजीवन से लेकर रोजगार तक पर घातक प्रहार किया। ऐसे में यह साल इस आपदा से जुड़ी तमाम त्रासद तस्वीरों के लिए भी याद रखा जाएगा।

दुनिया के अधिकांश देशों ने चीन को ही इस आपदा का असल दोषी माना। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नवंबर 2019 में ही चीन में इस जानलेवा वायरस की व्यापक मौजूदगी के बावजूद बीजिंग ने वैश्विक समुदाय को समय से इसकी सूचना ही नहीं दी। इतना ही नहीं जब दुनिया को इसकी भनक लगी तब भी चीन इसे छिपाकर उस पर पर्दा डालने का ही प्रयास करता रहा। यहां तक कि उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था पर भी अपने प्रभाव से शिकंजा कसने में कोताही नहीं की। इसी कारण डब्ल्यूएचओ ने न केवल कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने में विलंब किया, बल्कि उसके लिए चीन को जिम्मेदार मानने से ही इंकार कर दिया। इस वैश्विक संस्था पर चीन के अंकुश का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब इस महामारी की पड़ताल के लिए उसे अपनी जांच टीम चीन भेजनी थी तो यह काम भी उसे बीजिंग की शर्तों पर ही करना पड़ा। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने कोरोना को लेकर जवाबदेही तय करने और व्यापक जांच का मुद्दा उठाया तो चीन ने अपने आर्थिक दबदबे से उलटे उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चीन के प्रति नकारात्मक धारणा बनती गई।

इतने पर भी चीन नहीं माना। जब पूरी दुनिया उसके यहां से निकले वायरस से जूझने में जुटी थी तो उसने इस आपदा में अपने भौगोलिक विस्तार का अवसर तलाशने का दुस्साहस किया। उसने जापान के सेनकाकू द्वीप से लेकर दक्षिणी चीन सागर में अपने पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि जब उसने हिमालयी क्षेत्र में भारत को चुनौती दी तो भारत ने न केवल उसका कड़ाई से प्रतिकार किया, बल्कि उसने चीन की किसी भी धौंस-धमकी को कोई तवज्जो नहीं दी। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम रण क्षेत्रों में से एक लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य ने चीनी सैनिकों को करारा और माकूल जवाब दिया। इस तरह भारत ने चीन द्वारा बनाए जा रहे दबाव की हवा निकालकर रख दी। इससे पूरी दुनिया और खासकर चीन से भयाक्रांत देशों में यह भरोसा जगा कि भारत चीनी वार का पलटवार करने में सक्षम है। इसका ही नतीजा रहा कि जिस ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमकाया वह भारत के साथ मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास के लिए आगे आया। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अमेरिका और जापान को साधकर क्वॉड जैसे उस मंच को मजबूती दी जो भविष्य में चीन की चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।

सामरिक मोर्चे के अलावा कूटनीतिक अखाड़े में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। उदाहरण के तौर पर चीन अब तक जिस 'हिंद-प्रशांत रणनीति' को खारिज करता आया है उसे इस साल व्यापक मान्यता हासिल हुई। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों और यहां तक कि आसियान राष्ट्रों द्वारा इस क्षेत्र का महत्व स्वीकारने और उसके अनुरूप नीतियां बनाने से स्पष्ट है कि अब इस अवधारणा को स्वीकृति मिल रही है जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। श्रीलंका में राजपक्षे बंधुओं की सत्ता के बावजूद चीन को वहां उनके पहले कार्यकाल जैसा भाव नहीं मिल रहा। इसके विपरीत श्रीलंका भारत के साथ गलबहियां कर रहा है। मालदीव भी उसी नक्शेकदम पर भारत से प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है। यहां तक कि म्यांमार जैसे देश बीजिंग को आईना दिखा रहे हैं। नेपाल में हालिया राजनीतिक उठापटक में भी चीनी दखल को जिम्मेदार माना जा रहा है जिससे वहां की राजनीतिक बिरादरी में गहरा असंतोष है। और तो और अफगानिस्तान ने चंद रोज पहले हुए जासूसी कांड में चीन से जवाब मांगा है।

● **कुमार विनोद**

चीन को लगे कई झटके

आर्थिक मोर्चे पर भी इस साल चीन को खासी तपिश झेलनी पड़ी है। दुनिया के करीब 70 देशों ने अपने यहां 5जी की होड़ से उस हुआवे कंपनी को बाहर कर दिया है जिसे चीन अपने राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखता आया है। दुनिया की तमाम कंपनियां चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयां ले जा रही हैं। अमेरिका इस मामले में खासा सक्रिय हुआ है। वहीं जापान ने तो चीन छोड़कर जाने वाली अपनी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज तक का ऐलान किया है। भारत भी इससे बन रहे अवसरों को भुनाने में जुट गया है। ऐसे प्रयास रंग लाते भी दिख रहे हैं। बीते दिनों देश में कई उद्योगों विशेषकर स्मार्टफोन निर्माण के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। उनमें से कुछ संयंत्र तो काम भी करने लगे हैं। एक ऐसे समय में यह सब चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं जब वह स्वयं को वैश्विक नेतृत्व के दावेदार के तौर पर आगे बढ़ाने में जुटा था। इस साल चीन के प्रति दुनिया में दुर्भावना बढ़ी है और इसी कारण दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में जुट गई है। परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदल रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह साल वैश्विक विनिर्माण ढांचे के पुनर्गठन का भी साल रहा है और इस मामले में चीन की जमीन खिसक रही है। उसके द्वारा रिक्त किए जा रहे इस स्थान की पूर्ति में भारत जैसे देश बखूबी उभरे हैं। अपने संसाधनों के सापेक्ष भारत ने कोरोना आपदा का कहीं बेहतर तरीके से सामना करके भी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। ऐसे में यदि भारतीय नेतृत्व अपनी नीतियों पर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो चीन का उतार भारत के उभार में अवश्य रूपांतरित हो सकता है।

दरकते रिश्ते

वैश्वीकरण और उपभोक्तावादी व्यवस्था के कारण अब परिवार एक स्वाभाविक एवं पवित्र इकाई के रूप में अपना महत्व खोता जा रहा है। वैश्वीकरण ने भौगौलिक दूरियां भले कम कर दी हों, लेकिन सामाजिक दूरियां बढ़ा दी हैं। वैश्वीकरण ने समाज की उन औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं को भी लगभग खत्म-सा कर डाला है जो हमें मूल्य, प्रतिमान, सुरक्षा व स्थिरता देती थीं। आज परिवारों में व्यक्तिवाद का मूल्य हावी हो चुका है। बच्चों को जब माता-पिता की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो वे उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दो बेटों को अपने पिता की देखभाल न करने और पुश्तैनी घर पर कब्जा कर उन्हें आर्थिक मदद नहीं देने के कारण फटकार लगाई थी।

इसी तरह एक अन्य मामले में एक पंचाट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बेटों को अपने पिता को सात हजार रुपए प्रतिमाह जीवनयापन के लिए देने का निर्देश दिया था। लेकिन बेटों ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे ढेरों मामले मिल जाएंगे, जिनमें पारिवारिक विवादों में खासतौर से अभिभावकों की उपेक्षा, उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेने जैसे मामलों में अदालतों ने सख्त रुख अपनाया है और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं।

वैश्वीकरण ने परिवार की परंपरागत सत्ता संरचना को बदल डाला है। युवा पीढ़ी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और नौकरियों में संलग्न युवा अब परिवार के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को त्यागने में विश्वास नहीं करते। इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि उपभोक्तावादी समाज में परिवार भी बाजार का हिस्सा बन गया है और परिवार के भीतर भी व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत ने घर के बाहर महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं।

नए रोजगार और शैक्षणिक अवसरों की तलाश में युवा पीढ़ी की बढ़ती गतिशीलता से परिवार नाम की इकाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और इसी का नतीजा है कि यह परिवार इकाई कहीं न कहीं कमजोर पड़ती जा रही है और पारिवारिक संबंधों में क्षीणता आती जा रही है। भौगोलिक दूरियों और व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्य अब पहले की तरह बार-बार एक साथ आने में असमर्थ महसूस करते हैं। परिणामस्वरुप बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल और पोषण करने वाली इकाई के रूप में स्थापित 'परिवार' की आदर्श अवधारणा प्रभावित हुई है।

जाहिर है, बच्चों के लिए परिवार का मतलब अपनी पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गया है। बच्चों में उत्पन्न यह सोच स्पष्ट संकेत करती है कि अब समाज पर बाजारवाद, उपभोक्तावाद इतना हावी हो गया है कि करीबी रिश्ते भी बाजार और उपयोगिता की दृष्टि से आंके जाने लगे हैं। बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया है उसका श्रेय अकेले उन्हीं को जाता है, इसमें परिवार या समाज का कोई योगदान नहीं है।

और यही सोच उन्हें व्यक्तिवादी बनाती है। इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दिखावे के उपभोग को इतना बढ़ा दिया है कि व्यक्ति केवल भौतिक संसाधनों को जुटाने में व्यस्त रहने लगा है और वही उसके मनोरंजन के भी साधन बन गए हैं। भौतिकतावाद के प्रति आकर्षण ने सामाजिक संबंधों को हाशिए पर कर दिया है। उसी का परिणाम है कि नगरों में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है।

परिवार संस्था के कमजोर होने का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति को लगता है कि बाजार उसकी हर आवश्यकता पूरी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि परिवार कैसा होना चाहिए, उसमें सदस्यों की भूमिका क्या हो, यह भी अब बाजार तय करने लगा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि परिवार नाम की संस्था भी अब बाजार की वस्तु बनकर रह गई है। इसीलिए समाज विज्ञानी टालकट पारसंस कहा भी है कि 'परिवार एक कारखाना है जिसमें व्यक्तित्व को आकार दिया जाता है।' यह सच है कि पूर्व में समाज या व्यवस्था द्वारा उत्पन्न तनाव और निराशा को कम या समाप्त करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदाय से लगभग कट से गए हैं। इसी का नतीजा है कि भावनात्मक तनाव परिवार का एक नकारात्मक हिस्सा बनकर उभरा है।

आज ऐसे परिवारों की संख्या ज्यादा है जहां लड़कों के विवाह के बाद उनके माता-पिता या तो घर में अकेले रह रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम में, क्योंकि बच्चों ने माता-पिता को अकेले घर में छोड़ दिया या उन्हें घर से बेदखल कर दिया और अपना अलग परिवार बसा लिया। रिश्तों का खोखलापन इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम अपने रिश्तों की कदर भी नहीं करते और सोशल मीडिया पर मदर्स-डे, फादर्स-डे, सिस्टर्स-डे, ब्रदर्स-डे, फ्रेंडशिप-डे मनाते हैं। यही रिश्तों का बाजारीकरण है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

दिखावे की संस्कृति का संकट

वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक संबंधों पर भी दिखावे की संस्कृति का संकट गहरा गया है। व्यक्ति स्वयं को नए तरीके से अभिव्यक्त करने लगा है और केवल खुद से प्यार करने लगा है, इसलिए समूह फोटो का स्थान सेल्फी ने ले लिया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले जहां परिवार को प्रतिमान एवं मूल्य आकार देते थे, वहीं अब यह काम तकनीक और आभासी यथार्थ कर रहे हैं। परिवार में बच्चों के समाजीकरण अब बाजार और तकनीक कर रहे हैं। यही कारण है कि बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा नहीं होता। संबंधों में अविश्वास उभरा है, इसलिए लोग अलगाव का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन हो गया है कि वे किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर पाते। कहते हैं कि आज के दौर में मनुष्य ज्यादा स्वतंत्र एवं विकसित हुआ है, पर ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में मनुष्य आज अधिक जकड़न में है, क्योंकि उसके पास स्वाभाविक जीवन जीने का समय ही नहीं है। सब कुछ कृत्रिम है, आभासी है।

पराधीन नहिं तोर सुपासा

हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वे प्रयास भी करता है। कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। यहां जानिए ऐसी इच्छाओं के विषय में जो कुछ लोग कभी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। इन असंभव इच्छाओं के विषय में लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बताया था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरित मानस के अरण्यकाण्ड में जब शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने प्रणय का प्रस्ताव रखती है तब लक्ष्मण कहते हैं कि-

सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा।।
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु करहिं उनहि सब छाजा।।

इस दोहे में लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं कि हे सुंदरी। मैं तो श्रीराम का सेवक हूं, मैं पराधीन हूं, अत: मुझे जीवन साथी बनाकर तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम श्रीराम के पास जाओ, वे ही सभी काम करने में समर्थ हैं।

सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुख गति विभिचारी।।
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी।।

इस दोहे में लक्ष्मण ने 6 ऐसे पुरुषों के विषय में बात की है, जिनकी कुछ इच्छाएं पूरी होना असंभव ही है।

पहला पुरुष है सेवक- यदि कोई सेवक सुख चाहता है तो उसकी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। सेवक को सदैव मालिक यानी स्वामी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहना होता है। अत: वह स्वयं के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता।

दूसरा पुरुष है भिखारी- यदि कोई भिखारी ये सोचे कि उसे समाज में पूर्ण मान-सम्मान मिले, सभी लोग उसका आदर करे तो यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। भिखारी को सदैव लोगों की ओर से धिक्कारा ही जाता है, उन्हें हर बार अपमानित ही होना पड़ता है।

तीसरा पुरुष है व्यसनी यानी नशा करने वाला- यदि कोई व्यसनी (जिसे जुए, शराब आदि का नशा करने की आदत हो) यह इच्छा करे कि उसके पास सदैव बहुत सारा धन रहे तो यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों के पास यदि कुबेर का खजाना भी हो तो वह भी खाली हो जाएगा। ये लोग सदैव दरिद्र ही रहते हैं। नशे की लत में अपना सब कुछ लुटा देते हैं।

चौथा पुरुष है व्यभिचारी- शास्त्रों के अनुसार व्यभिचार को भयंकर पाप माना गया है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है और अन्य स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखता है तो उसे कभी भी सद्गति नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। जिस समय इनकी गुप्त बातें प्रकट हो जाती हैं, तभी इनके सारे सुख खत्म हो जाते हैं। साथ ही, ऐसे लोग भयंकर पीड़ाओं को भोगते हैं।

पांचवां पुरुष है लोभी यानी लालची- जो लोग लालची होते हैं, वे हमेशा सिर्फ धन के विषय में ही सोचते हैं, उनके लिए यश की इच्छा करना व्यर्थ है। लालच के कारण घर-परिवार और मित्रों को भी महत्व नहीं देते। धन की कामना से वे किसी का भी अहित कर सकते हैं। इस कारण इन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती है। अत: लोभी इंसान की यश पाने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है।

छठां पुरुष है अभिमानी- यदि कोई व्यक्ति घमंडी है, दूसरों को तुच्छ समझता है और स्वयं को श्रेष्ठ तो ऐसे लोगों को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। आमतौर पर ऐसे लोग चारों फल- अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, एक साथ पाना चाहते हैं, लेकिन यह इच्छा पूरी होना असंभव है। शास्त्रों में कई ऐसे अभिमानी पुरुष बताए गए हैं, जिनका नाश उनके घमंड के कारण ही हुआ है। रावण और कंस भी वैसे ही अभिमानी थे।

वहीं श्रीरामचरित मानस में इस बात का भी उल्लेख है कि 9 लोगों की बात तुरंत मान लेनी चाहिए? श्रीरामचरित मानस के अरण्य कांड में मारीज और रावण का प्रसंग है। इस प्रसंग में नौ लोग ऐसे बताए गए हैं, जिनकी बात तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना हम परेशानियों में फंस सकते हैं। रावण सीता का हरण करने के लिए मारीच के पास पहुंचा। रावण ने मारीच से कहा कि तुम छल-कपट करने वाला मृग बनो, ताकि में सीता का हरण कर सकूं। मारीच से रावण को समझाने की कोशिश की कि वह श्रीराम से दुश्मनी न करें। वे स्वयं नारायण के अवतार हैं। मारीच की ये बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया, खुद के बल और शक्तियों का घमंड करने लगा। इसके बाद मारीच को समझ आ गया कि रावण को समझाना असंभव है और सीता हरण के लिए उसकी मदद करने में ही भलाई है। रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्रीराम के हाथों से मरूं।

रामचरित मानस में लिखा है कि

तब मारीच हृदयं अनुमाना। नवहि बिरोधें नहिं कल्याना।।
सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। बैद बंदि कबि भानस गुनी।।

इस दोहे के अनुसार मारीच की सोच से बताया गया है कि हमें किन नौ लोगों की बातों को तुरंत मान लेना चाहिए। हमें शस्त्रधारी, हमारे राज जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान व्यक्ति, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन लोगों की बातें तुरंत मान लेनी चाहिए। इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे प्राण संकट में फंस सकते हैं। ऐसा सोचकर मारीच ने रावण की बात मान ली और वह स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता के सामने पहुंच गया। जब सीता ने सुंदर हिरण देखा तो श्रीराम से उसे लाने के लिए कहा। श्रीराम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए और श्रीराम के धनुष से छूटे बाण से मारीच यानी स्वर्ण मृग मारा गया।

● **ओम**

यशोदा

डोरबैल बजते ही मैंने दरवाजा खोला। सामने मुश्किल से दो महीने के बच्चे को गोद में लिए मेरे घर में काम की सहायिका यशोदा खड़ी थी। मैं हतप्रभ सी देखती रही और उसे अंदर आने को कहा। मैंने एकदम पूछा, अरे यह किसके बच्चे को लेकर आई हो। इतना छोटा और मुझे तो यह कुछ बीमार भी लग रहा है।

यशोदा हंसकर बोली मैडम यह मेरी बेटी है। अभी दो महीने की नहीं हुई, यह जन्म से ही इतनी कमजोर है।

तेरी बच्ची! क्या आसमान से भगवान जी ने भेज दी?

यशोदा की खुशी का कोई पार नहीं था। उसने कहा- मैडम जब मेरा छोटा बेटा हुआ तब मैं बेटी चाह रही थी। अब तो वह भी दस साल का हो गया है। भगवान ने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन मीना की दो बेटियां हैं इस बार उसकी यह जुड़वां बेटियां हुईं। इसकी दूसरी बहन तो काफी तंदुरुस्त है, यह कमजोर और बीमार सी है। मीना इसकी देखभाल नहीं करती थी। इसे रोते देखकर और भूख से बेहाल देखकर मैं इसके लिए दूध पिलाने वाली बोतल ले आई और दूध पिलाया। बच्ची जब बहुत बीमार हो गई तो मीना ने सोचा शायद यह बचेगी नहीं। चार बेटियों को पालना उसके लिए कठिन हो रहा था। तब मैंने मीना से कहा- यह बच्ची मुझे दे दे। मैं इसे पालूंगी। मैं उसी समय इसे अस्पताल ले गई। इसे एडमिट कर लिया। मीना तो इसे देखने भी नहीं आई। चार दिन बाद इसे अस्पताल से छुट्टी मिली। मैंने मीना से कहा- यह बच्ची मुझसे हिलमिल गई है और मुझे ही अपनी मां समझती है। यदि तुम मान जाओ तो मैं इसे गोद ले लूं? मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी बेटी हो। मेरे पास यह ठीक से पल जाएगी। पहले तो मीना मानी नहीं कहने लगी जैसे तीन पल रही हैं यह भी पल जाएगी। एक महीने मैं रोज उसे इस कमजोर सी बच्ची का वास्ता देकर समझाती रही। पर बाद में इसकी हालत देखकर मान गई। मैंने इसकी खूब देखभाल की और अब यह ठीक हो गई है।

मैं धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुन रही थी। यशोदा ने बड़े उत्साह से बताया- मैडम आज से मेरी यह आस्था गुड़िया कानूनन मेरी हो गई है। मैंने कोर्ट के सारे कागज भर दिए। अपने और मीना तथा उसके पति की रजामंदी से आस्था अब मेरी बच्ची है। उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। मैंने भी प्रसन्नता से बिटिया को शगुन देते हुए कहा- तुमने तो अपने नाम को सार्थक कर दिया। तुम सही अर्थों में 'यशोदा' हो।

- डॉ. मनोरमा शर्मा

अश्रु समंदर बह जाता है

शब्द गरल पीते ही
अश्रु समंदर बह जाता है।
खारा जल कपोल पर ढुलके
मन आघात दे जाता है।
वाणी की महिमा को समझो
हिय तराजू तोल कर बोलो।
आखर-आखर अर्थ भरा है
विष से अमृत मोल बड़ा है
शब्दों की अग्नि से झुलसा
तन बदन जल जाता है।
खारा जल कपोल पर ढुलके
मन आघात दे जाता है।
घायल करते शब्द मन को
तन में चिह्न दिखे न कोय।
मन का घाव भरे कभी न
हर पल उसमें पीड़ा होय।
मन मस्तिष्क पथराया सा
दुख अनंत दे जाता है।
खारा जल कपोल पर ढुलके
मन आघात दे जाता है।
कम बोलो और मीठा बोलो
जब भी तुम अपना मुंह खोलो।
अंतर ज्योति से चमकाकर
हर अक्षर मोती सम कर लो।
मुख मंडल पर बैठी शारदा
शब्द-शब्द सरसा जाता है।
खारा जल कपोल पर ढुलके
मन आघात दे जाता है।
शब्द गरल पीते ही
अश्रु समंदर बह जाता है।

- निशा नंदिनी भारतीय

आयाराम - गयाराम!

आलोक राम विधायक हैं। अपने आक्रामक तेवरों के कारण सोशल मीडिया वाले उन्हें आक्रमण कुमार संबोधित करते हैं। सत्ताधारी सरकार की शुरूआती 6 महीनों के कार्यकाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इन्होंने। इनके तीखे तेवरों से आहत होकर मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी मंत्रियों से विचार विमर्श किया। आलोक राम का सदुपयोग करने का सुझाव पेश किया जिसे सभी ने एकमत से सराहा।

आलोक राम मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले, अपना भाषण याद करने के लिए कागज हाथ में लेकर खुशी से सोचने लगे, अब सरकार की नकेल कसने का सही समय आ गया है। उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। भाषण पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, वर्तमान सरकार के सिर्फ 6 महीनों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सारे बदमाश निर्भय होकर अपराध कर रहे हैं। युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई सुरसा के मुंह के समान तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में सरकार के कामों से नाराज जनता आए दिन हड़ताल का आयोजन कर रही है। दिन-ब-दिन बढ़ते जातीय दंगों से जनता बेचैन, बेहाल हो रही है। राम राज्य लाने का वादा करने वाली सरकार, राज्य में शांति स्थापित करने में असफल हो चुकी है। अब गृहमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे।

इतने में विधायक आलोक राम का पीए दौड़ता-हांफता उनके पास आया और माफी मांगकर कहा, सर जी गलती से मैंने आपको पुराने भाषण वाला कागज दे दिया है। दरअसल वो तब का भाषण है जब आप विपक्ष के विधायक नेता थे। अब आप सत्ताधारी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अब आपको यह भाषण पढ़कर सुनाना है, जिस में पिछली सरकार के भ्रष्टाचारों का कच्चा चिट्ठा है। यह कहते हुए पीए ने मंत्री महोदय को चार पन्ने पकड़ाए।

आलोक राम के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैलने लगी। कहा, अच्छा हुआ तुमने समय रहते मुझे चेताया। वरना मेरे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर तो मैं।

- अशोक वाधवाणी

वाह कप्तान वाह...!

अर्बन होड़ से बचे, तो एक्सीलेंस पा ली

मधुकर बाबूराव रहाणे को अपने बच्चे में क्रिकेट के प्रति दीवानगी बचपन में ही दिख गई थी। सात साल के अजिंक्य को एक छोटे से क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए वो डोंबीवली ले आए। वे चाहते थे कि स्कूल की छुट्टियां बर्बाद न हो। यहां मैटिंग पर बच्चों को कोचिंग दी जाती थी। पिता ने कोचिंग कैंप में दाखिला करवाया तो आगे की जिम्मेदारी मां सुजाता ने संभाल ली। वे नियमित रूप से अजिंक्य को दो किमी दूर कैंप तक छोड़ने जाती थी, और कैंप खत्म होने पर लेने भी। एक बार कोच ने सचिन तेंडुलकर की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाते हुए पूछा जानते हो, ये कौन हैं? अजिंक्य ने सिर हिलाकर सचिन का नाम लिया। कोच ने मजाक में पूछा कि इनके साथ खेलना चाहते हो। अजिंक्य ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि वो एक दिन सचिन के साथ जरूर खेलेंगे। उनके पिता उस घटना के साक्षी हैं, और कहते हैं कि उस समय मैंने अजिंक्य की बात को बड़बोलेपन के रूप में लिया, और बहुत शर्मिंदा हुआ। लेकिन, उस दिन आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अजिंक्य की बचपन में कही गई बात 2011 में सच हुई। वे 16 महीनों से टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें 12वें खिलाड़ी से ऊपर जगह नहीं मिल पा रही थी। ड्रिंक्स ब्रेक में साथी खिलाड़ियों का गला तर कर रहे अजिंक्य के दिल की प्यास दिल्ली के कोटला स्टेडियम में बुझी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे टेस्ट मैच से एक दिन पहले उन्हें बताया गया कि उनका नाम भी अंतिम 11 में हैं।

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हराया। चार मैच की टेस्ट सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। इस जीत के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। वे तीन टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों जीते हैं। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। पहले यह रिकॉर्ड धोनी के नाम था। धोनी ने भी बतौर कप्तान अपने शुरुआती तीन मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी।

मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली की जगह कप्तानी संभालने वाले अजिंक्य रहाणे की तारीफ हर कोई कर रहा है। एडिलेड टेस्ट में बुरी तरह हारने वाली टीम इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अलग रंग में दिखी। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में सिर्फ 195 रन ही बना सकी। इस बीच भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रहाणे की कप्तानी की तारीफ क्रिकेट विशेषज्ञ से लेकर फैंस तक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन रहाणे ने समझदारी से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मेजबान टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी रहाणे के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, रहाणे ने गेंदबाजी में शानदार बदलाव करने के साथ फील्डरों को सही जगह खड़ा करने में चतुराई दिखाई। गेंदबाजों ने भी इसका परिणाम दिया। अश्विन, बुमराह, सिराज शानदार थे। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 195 पर ऑल आउट करना बेहतरीन प्रयास है। पहली पारी में बड़ी बढ़त बनाने का दारोमदार अब बल्लेबाजों पर है। वहीं महान स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा है कि रहाणे ने शानदार तरीके से टीम का नेतृत्व किया है।

विराट कोहली की कमान में टीम इंडिया के खिलाड़ी जब पूरी तरह पब कल्चर को आत्मसात कर चुके हैं, ऐसे में औसत कद काठी वाले सौम्य अजिंक्य रहाणे को देखना सुकून देता है। एक ऐसे दौर में जब खिलाड़ियों के टैटू उनकी आस्तीन और कॉलर से बाहर आ रहे हैं, तो अजिंक्य को देखकर लगता है कि उनके गले में अब भी एक रुद्राक्ष पड़ा होगा। जब टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों का एड्रेलेनिन मुंह के बल गिर जाने तक का अतिरिक्त उछाल दे रहा है, तो अजिंक्य किसी ऋषि की तरह मैदान में साधना करते नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की शर्मनाक हार के बाद दूसरे टेस्ट में विराट कोहली की जगह कप्तानी संभाल रहे अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व और उनके शतक ने कई संदेश दिए हैं।

इलाकाई तासीर आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगी। ये बात क्रिकेट खिलाड़ियों पर भी लागू होती है। मुंबई और दिल्ली के मिजाज का फर्क इन दोनों महानगरों से आने वाले खिलाड़ियों में भी दिखाई पड़ता रहा है। और अजिंक्य रहाणे तो मध्य महाराष्ट्र अंचल से मुंबई होकर टीम इंडिया का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में उनकी खामोशी उस लड़के की मनोदशा से समझी जा सकती है जो अंचल के घर से शहर के कॉलेज में दाखिला लेने आया है। इंटरनेट के दौर में अर्बन एटीट्यूड वाली खुमारी टीम इंडिया में एक समान फैली है, लेकिन अहमदनगर जिला मुख्यालय से 75 किमी दूर स्थित आश्वी खुर्द से आने वाले 32 साल के रहाणे अपनी पहचान को साथ लेकर चलते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों न, चार हजार लोगों की आबादी वाले इस कस्बे के बारे में विकिपीडिया पर तमाम जानकारियों के अलावा यह भी दर्ज है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे यहीं जन्मे हैं। एक कस्बे के इस अभिमान को उसका संस्कारी बेटा कैसे भूल सकता है।

● आशीष नेमा

...जब आखिरी फिल्म में गाने के लिए ओम पुरी ने की थी 4 दिन तक रिहर्सल

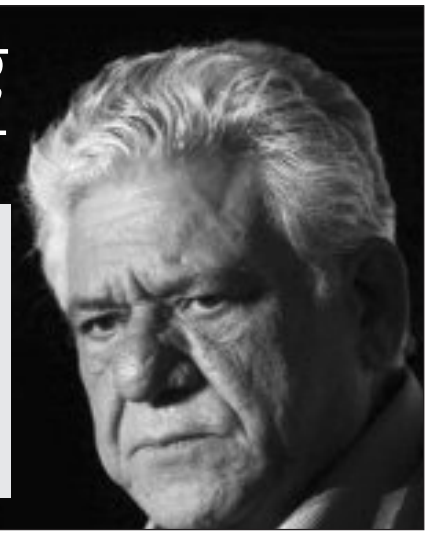

दिवंगत एक्टर ओम पुरी ने अपनी आखिरी फिल्म ओमप्रकाश जिंदाबाद के लिए पहली बार गाना गाया था। यह गाना था- उठवीर शूरवीर। यह फिल्म दिसंबर 2018 में रिलीज हो चुकी है। ओमपुरी अपने कैरियर में पहली बार सिंगिंग करने को लेकर बहुत नर्वस थे, इतना ही नहीं दो दिन की रिहर्सल के बावजूद वे रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो से बाहर आ गए थे।

सारे काम कैंसिल करके की थी रिहर्सल

हालांकि दो दिन बाद उन्होंने दोबारा मेकर्स को कॉल करके बेझिझक रिकॉर्डिंग की। फिल्म के डायरेक्टर रहे रंजीत गुप्ता ने एक इंटरव्यू में किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उन दो दिनों में ओम पुरी ने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए थे, और घर पर ही इस गाने की लगातार रिहर्सल की थी, जिसके बाद वे कॉन्फिडेंटली यह गाना रिकॉर्ड कर सके।

खराब कैरियर के चलते गोविंदा-सुनीता ने 4 सालों तक सीक्रेट रखी शादी

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एंटरटेनर में से एक गोविंदा 57 साल को हो चुके हैं। धमाकेदार डांस मूव और अलग स्टाइल से गोविंदा ने कामयाबी हासिल की और हर किसी को अपना दीवाना कर लिया। गोविंदा के चाचा आनंद सिंह एक सह डायरेक्टर और कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्म तन-बदन से गोविंदा को लॉन्च किया था। गोविंदा कुछ समय बाद ही आनंद की सिस्टर इन लॉ सुनीता मुंजाल से प्यार कर बैठे और दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। जहां इंडस्ट्री में कई लोग दो शादियों के कारण चर्चा में रहते हैं वहीं गोविंदा इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शादी के 18 साल बाद अपनी ही पत्नी से पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी की थी।

गोविंदा ने साल 2015 में पत्नी सुनीता से दोबारा शादी की है। इस बारे में एक्टर ने खुद आपकी अदालत के दौरान इंटरव्यू में बताया था। गोविंदा की मां निर्मला देवी चाहती थीं कि वो 49 साल की उम्र में दोबारा शादी करें। अपनी मां की मर्जी को पूरा करने के लिए गोविंदा ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने 11 दिसंबर 2015 में पत्नी सुनीता मुंजाल से दोबारा शादी की। दोनों की शादी धूमधाम से ट्रेडिशनल रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए हुई जिसमें उनके बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन भी शामिल हुए थे।

4 सालों तक सीक्रेट रखी थी शादी... जिस समय गोविंदा और सुनीता की शादी हुई उस समय एक्टर का कैरियर स्टेबल नहीं था इसलिए दोनों ने शादी तो कर ली मगर इस बात को पूरी दुनिया से छिपाकर रखा। बाद में जब गोविंदा ने अपनी शादी की बात सबको बताई तो हर कोई हैरान रह गया।

घरवाले नहीं माने तो सोहेल ने सीमा के साथ भागकर आर्य समाज मंदिर में की थी शादी

सलमान खान के छोटे भाई सोहेल 50 साल के हो चुके हैं। 20 दिसंबर, 1969 को मुंबई में जन्मे सोहेल सलमान खान के साथ फिल्म ट्यूबलाइट में भी नजर आए थे। वहीं, लवयात्री और दबंग-3 में उनका स्पेशल अपीयरेंस था। बतौर एक्टर सोहेल का फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं रहा लेकिन उनकी लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। सोहेल ने सीमा सचदेव से शादी की है जो कि पिछले दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज फेबुलेस लाइफ और बॉलीवुड वाइफ में नजर आने के बाद से तारीफ बटोर रही हैं। सीमा और सोहेल की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है। सीमा दिल्ली की रहने वाली हैं। फैशन डिजाइनिंग में कैरियर बनाने के लिए वो मुंबई गई थीं। इसी बीच सीमा और सोहेल की पहली मुलाकात हुई थी। बकौल सोहेल उन्हें सीमा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जल्द ही दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। ये कपल शादी करना चाहता था। लेकिन सीमा की फैमिली इस शादी के लिए बिलकुल तैयार नहीं थी। इसी के चलते सीमा और सोहेल ने एक बड़ा फैसला लिया। जिस दिन सोहेल की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या (1998) रिलीज हुई उसी दिन दोनों घर से भाग गए और आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।

जिसकी कुर्सी, उसकी थाली

सत्ताधारी को तो इस तबके के समक्ष अपनी मौजूदगी रखनी होती है और भला रोटी यानी भूख से बड़ा वोट पाने का रास्ता और क्या हो सकता है। इन योजनाओं के शुरु होने के बाद संचालन तो एनजीओ द्वारा कराया जाता है। एनजीओ को ठेका मिला, कुछ दिन चौक-चौराहे पर गरीब बस्ती के आसपास खाना बंटा, फिर तलाशते रहिए।

आप सोच रहे होंगे कि भला ये कुर्सी के साथ थाली का क्या मेल? बिलकुल है। दरअसल जब भी, जिस राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो सियासत के बैनर, पर्दे बदलने के साथ चौक-चौराहों पर लगी गरीब की थाली के रंग भी तो बदल जाते हैं। ब्रांड नेम और थाली के जायके पर सत्ता पार्टी का स्वाद चढ़ जाता है। अब गरीब को क्या है खाने में दाल-भात मिले या सब्जी-रोटी, वडा पाव मिले या दाल मखनी, खिचड़ी मिले या इडली या फिर दही-चावल। इस पर भी सवाल उठाना उसके ओहदे की बात थोड़ी है कि ये थाली दो-चार दिन मिले, महीने मिले या कुछ साल मिलते-मिलते कब विलुप्त हो जाए। पूर्वी दिल्ली के एक इलाके में स्थानीय सांसद गौतम गंभीर ने भी ऐसी ही सस्ती थाली की सेवा शुरू की है, जिसके बाद से यह विषय एक बार फिर सुर्खियों में है। एक और चीज देखिए। इस थाली में जायके और पौष्टिकता की भले आपको खुशबू नहीं आए, लेकिन हां, जिस राज्य में गरीब के नाम की थाली जन्म लेगी, उसमें फ्लेवर उस राज्य का ही होगा।

एक रोचक चीज और देखिए। जिस तरह किसी हवेली की कीमत को लेकर बोली लगती है कि उससे ज्यादा मुझसे लो, मैं तुम सबसे ज्यादा कीमत लगाता हूं। लेकिन यहां सियासत वाले गरीब की थाली पर जरा विपरीत बोली लगाते हैं, मैं तुमसे कम। दरअसल यहां कम कीमत लगाने पर अधिक मुनाफे का भरोसा रहता है न, इसलिए। तभी तो किसी ने दस रुपए में रोटी खिलाई, किसी ने आठ रुपए में, कोई पांच रुपए में, तो कोई एक रुपया, तो किसी ने मुफ्त में ही रोटी खिलाने की दावेदारी ठोक दी।

सत्ताधारी को तो इस तबके के समक्ष अपनी मौजूदगी रखनी होती है और भला रोटी यानी भूख से बड़ा वोट पाने का रास्ता और क्या हो सकता है। इन योजनाओं के शुरू होने के बाद संचालन तो एनजीओ द्वारा कराया जाता है। एनजीओ को ठेका मिला, कुछ दिन चौक-चौराहे पर गरीब बस्ती के आसपास खाना बंटा, फिर तलाशते रहिए। न दिखेगा ठेला और न ही बंटेगा खाना। इसी तरह इन थालियों की योजनाओं के नामकरण में भी सत्ता की मुहर होगी। यहां एक बड़ा सवाल यह भी जेहन में कौंधता है कि जैसे ही सत्ता में दल-बदल होता है तो ये थाली क्यों बंद हो जाती है?

इस थाली और कुर्सी की शुरुआत भी बहुत दिलचस्प रही है जिसे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने वर्ष 2013 में दक्षिण के मशहूर व्यंजनों के साथ तीन से पांच रुपए की कीमत में शुरू किया था। मजे की बात देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2016 में इसी थाली ने उन्हें दोबारा सत्ता में भी ला दिया। फिर क्या था, यहीं से यह थाली विभिन्न राज्यों में जायकों की खुशबू फैलाती गई, राजनीतिक पार्टियों ने इसे हाथों-हाथ लिया। दिल्ली में 2015 तक सत्ता में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जन आहार योजना चलती थी, गरीब को खाना मिलता था। सत्ता गई तो गरीब की रोटी भी गई। वह भी उस दिल्ली में जिसमें देशभर से लाखों प्रवासी कामगार आते हैं, रहते हैं।

उप्र में भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2015 में तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए दस रुपए में थाली की योजना प्रारंभ की थी। लेकिन यह योजना भी बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। महाराष्ट्र में भी कई बार कोशिशें हुईं, वहां शिव वडा पाव थाली शुरू की गई थी, वो हर चौक-चौराहे पर आज भी है तो, लेकिन उसमें मिलने वाला वडा पाव सामान्य कीमत में ही मिलता है। हां, बस शिव वडा पाव थाली के नाम पर उसे बेचने वाले रेहड़ी वालों को संरक्षण मिला रहता है। मालूम हो कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इस थाली की शुरुआत की थी।

दिल्ली से ही सटे हरियाणा में भी राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण राशि से पूरे राज्य के 22 जिलों में सस्ती थाली की रसोई खोली, मगर लॉकडाउन के बाद से इनको शुरू नहीं करवाया जा सका। सरकार के श्रम विभाग ने 2018 में 20 रुपए की लागत वाला खाना 10 रुपए में देना शुरू किया था। फरीदाबाद व पलवल के सामान्य अस्पताल में जनचेतना ट्रस्ट के तत्वावधान में 10 रुपए में भरपेट खाने की रसोई खोली गई, मगर ये भी अब नहीं चल रही हैं। इन दोनों रसोईघरों का शुभारंभ हरियाणा के तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने किया था।

असल में ऐसी रसोई एक बार बड़े जोर-शोर से खोल दी जाती है, लेकिन बाद में इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता, या कहें कि ध्यान नहीं दिया जाता। एनजीओ का मकसद ठेका लेने तक ही होता है। राजस्थान में भी अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी। वसुंधरा राजे ने दिसंबर, 2016 में इसकी शुरुआत की थी। पांच से आठ रुपए में भरपेट खाना मिलता था। सत्ता बदली तो अन्नपूर्णा की जगह अब यह इंदिरा रसोई बन गई। क्या गरीब वर्ग सिर्फ वोट पाने तक ही सीमित है? गरीब के लिए चलाई जाने वाली जन आहार योजना तो चलाई ही जा सकती है। क्या पता आप दोबारा सत्ता में आ जाएं, कम से कम गरीब को रोटी तो मिलती रहे। दरअसल हमारे देश में मुंशी प्रेमचंद का गरीब जो आज भी हमारे समाज का बड़ा तबका है, उसे वोट बैंक की सेहत के लिए सबसे बेहतर समझा जाता है, पर सिर्फ वोट पाने तक ही क्यों? क्या उस थाली को सत्ता के मोह से आगे उसकी पौष्टिकता और जरूरत के लिए निरंतर नहीं चलाया जा सकता? सियासत की रोटियां तो सिकती ही रहती हैं, गरीब के पास तो सिर्फ निवाले की भूख है।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687